अ० ख़्रामत्सोव

मई दिवस की परंपराएं



अनुवादक : सुरेन्द्र कुमार

i

Храмцов А. Ф.

ТРАДИЦИИ ПЕРВОМАЯ

на языке хинди

Khramtsov A. F.

TRADITIONS OF THE FIRST MAY DAY

in Hindi

सोवियत संघ में मुद्रित

$X\frac{0301050202\text{-}041}{014/(01)\text{-}89}335\text{-}89$
ISBN 5—01—001496—3

विषय-सूची

"कांग्रेस का सर्वोत्तम प्रस्ताव"

१८८९ का ग्रीष्मकाल पेरिस के नागरिकों और वहां पहुंचनेवाले हज़ारों विदेशियों, दोनों के लिए अविस्मरणीय था। गर्म मौसम के बावजूद, जब फ़्रांस की राजधानी पेरिस में सारी चहल-पहल आम तौर पर ठप्प हो जाती थी, और समाज के समृद्ध लोगों को प्रकृति की कोलाहलरहित स्थलियों तथा सागर की ओर ले जानेवाली घोड़ागाड़ियों का सड़कों पर तांता बन्ध जाता था, नगर के मार्गों पर भरपूर हलचल थी।

बात यह थी कि फ़्रांसीसी गणराज्य की सरकार ने ५ मई को आरम्भ होनेवाली अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी तथा बुर्जुआ वर्ग के लिए सत्ता का पथ प्रशस्त करनेवाली महान फ़्रांसीसी क्रान्ति की शताब्दी-जयन्ती के समारोहों में भाग लेने के लिए समस्त देशों को वर्ष के आरम्भ में ही निमंत्रण-पत्र भेज दिये थे। नृत्य, कार्निवाल, आतिशबाज़ी, उस समय के तकनीकी चमत्कारों के प्रदर्शन, बहुत से काफ़े और रेस्तरांओं में मनोरंजन कार्यक्रम तथा कामकाजी बैठकें, जिनमें बहुधा लाभदायी सौदे तय किये जाते थे — इन सबने बुर्जुआ वर्ग को मदहोश कर दिया था, जिसका यह पक्का विश्वास हो गया था कि वह जीवन का स्वामी है। यद्यपि स्विट्ज़रलैंड तथा अमरीका को छोड़कर लगभग सभी आमंत्रित देश राजतंत्रीय थे, कुलीन वर्ग के विशेषाधिकार अतीत की वस्तु बनते जा रहे थे, विधायी सत्ता संसदों के हाथों में पहुंच रही थी, बुर्जुआ-जनवादी स्वतंत्रताएं फल-फूल रही थीं।

ज़ारशाही रूस समेत नाना देशों के अभिजात वर्गीय हल्क़ों ने फ़्रांस का निमंत्रण स्वीकार कर लिया था। समस्त देशों में राजतंत्रवादियों के एक भाग ने अपने को पूंजीवादी अवस्थाओं के अनुकूल ढाल लिया था। दूसरे, जो कुछ भी नहीं भूले थे और जिन्होंने कुछ भी नहीं सीखा था, प्रतिक्रियावादी बूलांगिज़्म आन्दोलन को आशाभरी दृष्टि से देख रहे थे,

जिसका उस समय फ़्रांस में सशक्त राजनीतिक प्रभाव था। इन राजतंत्रवादियों ने न केवल अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी आयोजित करनेवाले फ़्रांस में, अपितु सर्वत्र इतिहास का चक्र पीछे घुमाने की अपनी आशाएं इस प्रतिक्रियावादी आन्दोलन के साथ जोड़ दी थीं।

अविराम समारोह अपनी पराकाष्ठा के, १४ जुलाई, याने बस्तिय पर धावे की शताब्दी-जयन्ती के समीप पहुंच रहे थे। राजधानी ने अपना ऐसा रूप-शृंगार आज से पहले कभी नहीं किया था। नगर के अधिकारियों ने कल्पना-शक्ति तथा उदारता का परिचय देते हुए राजधानी को दुल्हन की तरह सजा दिया था। राष्ट्रीय परिधान से सजी तथा सिर पर लाल फ़्रिगियाई टोपी पहनी फूल विक्रेता नवयुवतियां फूलों के गुलदस्ते मुफ़्त बांट रही थीं। स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व के प्रतीक के रूप में फ़्रांसीसी गणराज्य की राष्ट्रीय पताकाएं सर्वत्र लहरा रही थीं: नगर के अभिजातीय, बुर्जुआ तथा बोहिमियाई मोहल्लों की इमारतों की दीवालों पर, विशाल बूलेवारों में तथा लुक्ज़म्बर्ग उद्यान के समीप, शैंप्स एलीसेई में, लैटिन मोहल्ले, मोंतमार्ते तथा मोंतपार्नास्से में। पीतल के चमचमाते वाद्ययंत्रों, बैंडबाज़ों से संगीत-लहरियां प्रवाहित हो रही थीं। 'मार्सेल्येज़' गीत की ध्वनि के बीच लोग समारोही वेशभूषा में नगर की सड़कों पर चहलक़दमी कर रहे थे।

इसी उजले, रूपहले, चहल-पहलभरे दिन सुबह नौ बजे से कुछ ही समय पहले लोग पेत्रेले हाल के सामने जमा होने लगे थे। उनमें सर्वहारा के मुक्ति-संघर्ष के लोकप्रिय नेता और वे लोग भी थे, जो आगे चलकर उसके नेता बननेवाले थे। ये थे—विल्हेल्म लीब्क्नेख़्त और अवगुस्ट बेबेल, एलेनोर एवलिंग-मार्क्स और क्लारा ज़ेट्किन, जूल गेद और एडवर्ड वाइयां, गेओर्गी प्लेख़ानोव और पाल लाफ़ार्ग।...

अन्तत:, दरवाज़े खुले और लोग हाल में प्रवेश करने लगे, जो बहुत बड़ा नहीं था और ख़ूब सजाया हुआ था। उसकी गुंबद कांच की बनी थी, खिड़कियां रंगीन कांच की थीं, मंच लाल झंडों से सजा हुआ था, एक झंडे पर सुनहरे अक्षरों में यह नारा अंकित था: "दुनिया के मज़दूरो, एक हो!" मंच के दोनों ओर लिखा था: "पूंजीपतियों के वर्ग की राजनीतिक और आर्थिक बेदख़ली और उत्पादन के साधनों का समाजीकरण समाजवादियों का लक्ष्य है," तथा "जून १८४८ तथा अप्रैल और मई १८७१ के पेरिस तथा बाबेफ़, ब्लांकी और वार्लिन की ओर से हम विश्व के दोनों गोलार्द्धों के समाजवादी मज़दूरों का स्वागत करते हैं।"

इस प्रकार पहली अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर कांग्रेस आरम्भ हुई। उसने दूसरे इंटरनेशनल को जन्म दिया। १४ जुलाई की तिथि, पेरिस में बुर्जुआ समारोहों की पराकाष्ठा की तिथि कांग्रेस के उद्घाटन के लिए संयोगवश नहीं चुनी गयी थी। समाजवादियों ने इस तरह याद दिलाया कि १०० वर्षों के दौरान पूंजीवाद ने नाना देशों को मेहनतकशों के लिए एक तरह के बस्तिय में बदल डाला है, जिसे नष्ट करना और उसके खंडहरों पर एक नयी दुनिया का निर्माण करना मेहनतकशों का ध्येय है।

इस तिथि का निर्णय फ़रवरी १८८६ में हेग सम्मेलन में कर दिया गया था, जिसमें पेरिस कांग्रेस की तैयारी की गयी थी। कांग्रेस में जारी की गयी अपील के एक अंश में कहा गया था: "पूंजीपति वर्ग ने मज़दूरों के श्रम के फलों को देखने और उनकी प्रशंसा करने के लिए दुनिया के अमीरों तथा ताक़तवरों को अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में निमंत्रित किया है, जब कि मानवजाति के पास अब तक की तुलना में सबसे बड़ी सम्पदा के बीच स्वयं इन मज़दूरों की क़िस्मत में दयनीय जीवन बिताना बदा है। हम समाजवादी, जिनका ध्येय श्रम की मुक्ति, मौजूदा उजरत प्रणाली का उन्मूलन तथा ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना है, जिसके अन्तर्गत मेहनतकशों का अपने साझे श्रम से निर्मित सम्पदा पर अधिकार होगा, सच्चे उत्पादकों को १४ जुलाई के दिन पेरिस में मिलने के लिए निमंत्रित करते हैं।

"हम बिरादराना संघ को, ऐसे संघ को सुदृढ़ बनाने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं, जो अपनी बारी में समस्त देशों के सर्वहाराओं को उनके संघर्ष में नयी शक्ति प्रदान करेगा और नयी दुनिया की स्थापना की गति तेज़ करेगा।"

१४ जुलाई की सुबह की उपस्थिति-सूची के अनुसार २० देशों के ३६१ डेलीगेट उपस्थित थे। परन्तु अगले दिन शाम तक यह संख्या बढ़कर ४६७ तक पहुंच गयी और नये-नये डेलीगेटों के आगमन का सिलसिला जारी रहा। इस तरह दूसरे इंटरनेशनल की स्थापना-कांग्रेस पूंजीवाद के समस्त पूर्ववर्ती इतिहास का सबसे बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी पग बन गयी।

सभा में पाल लाफ़ार्ग ने स्वागत-भाषण किया। उन्होंने कहा: "बुर्जुआ वर्ग अपनी क्रान्ति की, उस क्रान्ति की १००वीं जयन्ती मना रहा है, जिसने सबके लिए न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता की घोषणा की थी और जिसका अन्त मज़दूरों के सबसे क्रूर तथा असीमित शोषण में हुआ।...

"१८८९ के अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के डेलीगेटों ने अपनी एक ही बैठक से यह प्रदर्शित कर दिया कि वे उससे कहीं अधिक हासिल करना चाहते हैं, जो १७८९ की क्रांति ने हासिल किया था, और वे १७८९ के 'मनुष्यों तथा नागरिकों के अधिकारों' के आगे सिर नहीं झुकायेंगे, जो थैलीशाहों के अधिकार सिद्ध हुए हैं।... नये चिन्तन के दूत इस हाल में जमा हुए हैं। वर्षों से वे सभ्य राष्ट्रों के मज़दूरों के बीच यह प्रचार करते रहे हैं: आप आपस में भाई-भाई हैं और आपका एक ही शत्रु है, वह है निजी पूंजी, वह चाहे प्रशियाई, ब्रिटिश, फ़्रांसीसी या चीनी पूंजी हो। उनका अथक प्रचार पूंजीपति वर्ग द्वारा समस्त राजनीतिक और आर्थिक उत्पीड़न के बावजूद दो दुनियाओं के समाजवादियों का आत्मिक एकीकरण पहले ही हासिल कर चुका है।"

हेग सम्मेलन द्वारा तैयार कार्य-सूची में कांग्रेस के निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए समस्त देशों में संघर्ष का दिन नियत करने का प्रश्न शामिल नहीं किया गया था। इस कारण मई दिवस के कतिपय आलोचक कभी-कभी यह कहते हैं कि इस उत्सव का जन्म सरासर संयोगवश हुआ था। वे कांग्रेस में भाग लेनेवालों में से कुछ लोगों के, विशेष रूप से अ० टाबारांट के संस्मरणों का हवाला देते हैं। अ० टाबारांट के अनुसार, २० जुलाई को, जब कांग्रेस के अधिवेशन को सात दिन हो चुके थे, गर्मी के कारण थके-मांदे डेलीगेट जल्दी से जल्दी अन्तिम बैठक पूरी करना चाहते थे। इस कारण उन्होंने १८९० में मई दिवस प्रदर्शन करने के विषय में फ़्रांसीसी प्रतिनिधि राइमों लाविन द्वारा अकस्मात प्रस्तुत प्रस्ताव को विशेष बहस के बिना ही स्वीकार कर लिया था।

परन्तु इस पक्ष के विरुद्ध काफ़ी प्रमाण हैं, ख़ास तौर पर स्वीकृत प्रस्ताव का अन्तर्य। उसके पाठ के तीन पैराग्राफ़ ये रहे: "एक नियत तिथि पर समस्त देशों तथा नगरों में विशाल अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शन होगा, जिसमें मेहनतकश लोग एक साथ अधिकारियों से कार्य-दिवस घटाकर आठ घंटे का करने तथा पेरिस की अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस के अन्य निर्णयों को कार्यान्वित करने की मांग करेंगे।

"यह बात ध्यान में रखते हुए कि अमरीकी श्रम संघ दिसम्बर १८८८ में सेंट लूईस में अपनी कांग्रेस में पहले ही १ मई, १८९० को ऐसा प्रदर्शन आयोजित करने का निर्णय स्वीकृत कर चुका है, इस तिथि की अभिपुष्टि की जाती है।

"विभिन्न देशों के मेहनतकशों के लिए यह आवश्यक है कि

वे अपने-अपने देशों की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार यह प्रदर्शन करें।"

प्रस्ताव के पहले पैराग्राफ़ का अपना ही पूर्व-इतिहास है। बात यह है कि फ़्रांस की ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रीय संघ की कांग्रेस ने, जो २८ अक्तूबर से लेकर ४ नवम्बर, १८८८ तक हुई थी, कार्य-दिवस ८ घंटे तक सीमित करने तथा न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए दो दिन तक आम प्रदर्शन करने का निर्णय किया था। यह योजना बनायी गयी थी कि १० फ़रवरी, १८८९ को फ़्रांस की तमाम ट्रेड यूनियनें तदनुरूपी मांगें लेकर प्रांत-प्रमुखों और मेयरों के पास प्रतिनिधिमंडल भेजें। २४ फ़रवरी को मज़दूर-प्रदर्शनों द्वारा समर्थित इन प्रतिनिधिमंडलों को अपनी मांगों के उत्तर प्राप्त होने थे। इस कार्रवाई की सफलता को ध्यान में रख कर (६० से अधिक नगरों में प्रदर्शन हुए थे) संघ की राष्ट्रीय परिषद ने पेरिस कांग्रेस के लिए एक प्रस्ताव का मसौदा मंज़ूर किया। मूलत: उसका पाठ वही था, जो प्रस्ताव के प्रथम पैराग्राफ़ का था। लाविन को उसे कांग्रेस में पेश करने का काम सौंपा गया। अत: मई दिवस के प्रस्ताव के "सांयोगिक" स्वरूप विषयक धारणा ग़लत है।

लाविन के प्रस्ताव का अगला पैराग्राफ़ इस बात का प्रमाण है कि उसपर अमरीकी श्रम संघ के प्रतिनिधि के साथ विचार-विमर्श हो चुका था, जिसने आठ घंटे के कार्य-दिवस के लिए अमरीकी आन्दोलन को नैतिक समर्थन प्रदान करने के लिए कांग्रेस से अपील की थी। परन्तु प्रस्ताव में केवल विशुद्ध आर्थिक संघर्ष का ही अर्थ निहित नहीं था, जिसकी ओर सैमुएल गोम्पर्स की अगुवाई में अमरीकी श्रम संघ का झुकाव था, अपितु उसमें राजनीतिक मांग भी निहित थी। प्रस्ताव में श्रम-क़ानूनों की मंज़ूरी की मांग की गयी थी, सो भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर। यह बात गोम्पर्स के लिए सुविधाजनक नहीं थी, जिन्होंने अपने संघ को समाजवादी आन्दोलन से बाहर रखने का प्रयत्न किया। इस कारण आगे चलकर अमरीकी श्रम संघ ने आठ घंटे के कार्य-दिवस के लिए संघर्ष अन्य साधनों से चलाया और इस उद्देश्य के लिए मई दिवस प्रदर्शनों का उपयोग नहीं किया।

अन्तत:, प्रस्ताव के तीसरे पैराग्राफ़ पर स्पष्टत: जर्मन प्रतिनिधिमंडल के साथ विचार किया गया था, जिसे यह आशंका थी कि कांग्रेस के निर्णय के कार्यान्वयन के लिए संघर्ष का कोई एक निश्चित रूप अपनाने के उसके दायित्व के कारण देश के अधिकारीगण समाजवादियों के विरुद्ध "असाधारण क़ानून" के, जो ३० सितम्बर,

१८९० को समाप्त होनेवाला था, लागू रहने की अवधि आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित होंगे।

यह बात भी ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि विभिन्न देशों में मज़दूर तथा समाजवादी आन्दोलन की स्थिति और विभिन्न ट्रेड यूनियन ग्रुपों के संघर्ष से सम्बन्धित अपनी रिपोर्टों में बहुत से वक्ताओं ने एक साथ अन्तर्राष्ट्रीय सर्वहारा कार्रवाइयां करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

एक साथ अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शन करने का विचार उभर चुका था। परन्तु इन प्रदर्शनों के स्वरूप पर तत्काल मतभेद भी पैदा हो गया था। पेरिस कांग्रेस में ही प्रस्ताव में निरूपित दृष्टिकोण पर आपत्ति की गयी थी। उदाहरणत: फ़ांसीसी डेलीगेट त्रेफ़ो ने कहा कि प्रदर्शन केवल आम हड़ताल द्वारा समर्थन की ही सूरत में कारगर हो सकते हैं, जो सामाजिक क्रान्ति के समारम्भ का काम करे। लीब्कनेख़्त ने इसपर आपत्ति करते हुए कहा कि मज़दूर संगठन इतने मज़बूत नहीं बने हैं कि वे ऐसी कार्रवाइयां सफलतापूर्वक सम्पन्न कर सकें। त्रेफ़ो ने यह संशोधन पेश किया कि प्रस्ताव का सरोकार केवल उन देशों से होगा, जहां आम हड़ताल के लिए सफल होने की सम्भावना रहेगी। बहुत से डेलीगेटों ने उनका समर्थन किया। परन्तु मतदान के समय संशोधन को बहुमत ने ठुकरा दिया। मतदान का परिणाम कांग्रेस में मार्क्सवादी शक्तियों की एक और विजय का द्योतक था।

दूसरे इंटरनेशनल की पहली कांग्रेस के समापन के तुरन्त उपरान्त बुर्जुआ प्रेस न तो कांग्रेस का और न उसके मई दिवस प्रस्ताव के महत्व का सही मूल्यांकन कर सका, ज़ाहिर है, उसने मई दिवस प्रस्ताव को स्वीकृत निर्णयों के प्रसार का एक आम साधन माना। इस बारे में चंद रिपोर्टों में मुख्यतया मज़दूर संगठनों की, जो एक आम कांग्रेस बुलाने पर सहमत नहीं हो सके थे, "संकीर्णवादिता" की चर्चा की गयी थी।

कुछ भी हो, मई दिवस प्रस्ताव ने वर्ग-संघर्ष को तेज़ करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर आन्दोलन का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। एंगेल्स ने लिखा: "पहली मई विषयक प्रस्ताव हमारी कांग्रेस द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों में से सर्वोत्तम था। वह सम्पूर्ण संसार में हमारी शक्ति सिद्ध करता है, पुनर्गठन के तमाम औपचारिक पगों की तुलना में यह इंटरनेशनल का बेहतर पुनरुज्जीवन है। ..."*

---

* लाउरा लफ़ार्ग को फ़े० एंगेल्स का पत्र, १९ अप्रैल, १८९०।

अध्याय १

पहली मई के पग

१. सर्वहारा एकजुटता के स्रोत

मेहनतकशों की अन्तर्राष्ट्रीय एकजुटता का उत्सव मज़दूर आन्दोलन की प्रभात वेला में पैदा नहीं हो सकता था। सर्वहारा के लिए पहले वर्ग-संघर्ष का अनुभव प्राप्त करना, अपने संगठनों को दृढ़ बनाना तथा वर्ग चेतना का विकास करना आवश्यक था। इसलिए श्रम तथा पूंजी के परस्पर विरोध की प्रक्रिया में अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर आन्दोलन के अन्दर सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के विचारों के विकास का एक लंबा इतिहास पहली मई के अन्तर्राष्ट्रीय एकजुटता के उत्सव में रूपान्तरण का पूर्वगामी है।

अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के विचार सबसे पहले फ़्रांसीसी विश्वकोशकारों तथा यूटोपियाई समाजवादियों ने प्रस्तुत किये थे। परन्तु वे यह नहीं जानते थे कि समाज में कौन सी शक्तियां इन विचारों के वाहक बन सकती हैं।

गत शताब्दी के चौथे दशक में जन्मे पहले सर्वहारा संगठनों पर यूटोपियावाद का प्रभाव पड़ा था। इन संगठनों के विचारधारानिरूपकों के अन्तर्राष्ट्रीय एकता तथा एकजुटता विषयक विचार वर्गेतर धारणाओं से युक्त थे, जो जनगण के भ्रातृत्व, समस्त राष्ट्रों की एकता के निर्माण, आदि में प्रतिबिम्बित होती थीं। परन्तु सामाजिक उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष की ओर प्रवृत्त स्वत:स्फूर्त वर्ग-भावना ने सर्वहाराओं को लोगों के भ्रातृत्व के नारे में मेहनतकश जनसाधारण की एकता का आह्वान देखने के लिए विवश किया।

शुरू में कारख़ाने या उद्योग की शाखा के स्तर पर और फिर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर अपने हितों के एकसमान होने की अनुभूति से पहले, स्वत:स्फूर्तता पर तथा बुर्जुआ और टुटपुंजिया जनवादियों

तथा यूटोपियाई समाजवादियों के प्रभाव पर क़ाबू पाने से पहले मज़दूरों को बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ा। केवल विज्ञानसम्मत सिद्धान्त, जो सर्वहारा के वर्ग-हित, कार्यभार तथा उद्देश्य व्यक्त करता था, सर्वहारा को उन्हें समझने में मदद दे सकता था। नये, द्रुत गति से बढ़ते मज़दूर वर्ग को सच्चे विचारधारानिरूपकों तथा नेताओं की आवश्यकता थी। और वे प्रकट हुए।

मार्क्स और एंगेल्स के कार्यकलाप ने नवजात सर्वहारा वर्ग में क्रान्तिकारी सिद्धान्त के समावेश की नींव रखी। सर्वहारा एकजुटता का विचार पहले-पहल १८४५ के अन्त में उद्घोषित तथा अभिपुष्ट (प्रेस में) किया गया था, जब एंगेल्स ने 'लन्दन में राष्ट्रों का उत्सव' शीर्षक कृति में लिखा: "...तमाम देशों में सर्वहाराओं का केवल एक ही हित, एक ही शत्रु है, उनके समक्ष केवल एक ही संघर्ष उपस्थित है; सर्वहाराओं का विशाल जनसमुदाय अपनी प्रकृति से ही जातीय पूर्वाग्रहों से मुक्त है... केवल सर्वहारा ही जातीय पृथकता का अन्त कर सकते हैं, केवल जाग्रत हो रहे सर्वहारा ही भिन्न-भिन्न जातियों के बीच भ्रातृत्व की स्थापना कर सकते हैं।" *

तभी, गत शताब्दी के पांचवें दशक के मध्य में, जर्मन, फ़्रांसीसी, इटालवी और पोलिश प्रवासियों और साथ ही अंग्रेज़-चार्टिस्टों ने लन्दन के एक पुराने सर्वहारा ज़िले — सोहो — में अपने लिए एक सराय चुनी। न्याय लीग ** में ऐक्यबद्ध ये लोग रोज़ शाम को सामाजिक तथा जातीय उत्पीड़न के विरुद्ध आगे संघर्ष की योजनाओं पर विचार और तर्क-वितर्क करने के लिए एकत्र होते। यहां लीग के सदस्यों ने हाल की दीवारों पर लाल फीता लटकाया। उसमें उनका आदर्श-वाक्य १२ भाषाओं में लिखा हुआ था। यह आदर्श-वाक्य था: "सब लोग भाई-भाई हैं।"

इस आदर्श-वाक्य को अंगीकार करनेवाले लोग बहुत अक्सर मार्क्स तथा एंगेल्स की कृतियों, उनकी विविधतापूर्ण अनुपम योग्यता, उच्च

---

* फ़े० एंगेल्स, 'लन्दन में राष्ट्रों का उत्सव', १८४५।

** न्याय लीग की स्थापना जर्मन राजनीतिक प्रवासियों और भ्रमणशील दस्तकारों के गोपनीय संगठन के रूप में पेरिस में १८३६-१८३७ में हुई थी। १८३९ में संघ के प्रमुख नेता स्विट्ज़रलैंड और लन्दन चले गये, जहां संघ शीघ्र एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन बन गया। उसमें विभिन्न जातियों के लोग, यूरोपीय देशों के सबसे अधिक चेतनशील, राजनीतिक तथा सैद्धान्तिक दृष्टि से सबसे अधिक सुशिक्षित मज़दूर ऐक्यबद्ध हो गये। संघ पर यूटोपियाई समाजवाद का बहुत ज़्यादा प्रभाव था।

नैतिक गुणों की चर्चा करते और उनसे मिलने की इच्छा प्रकट करते। जनवरी १८४७ में लीग ने जोज़ेफ़ मोल नामक अपने एक नेता को यह काम सौंपा कि वे मार्क्स तथा एंगेल्स को लीग में शामिल होने, उसका पुनर्गठन करने तथा उसका आधारभूत दस्तावेज़ तैयार करने में भाग लेने के लिए लिखें।

मार्क्स और एंगेल्स सहमत हो गये, हालांकि उन्होंने लीग के कार्यकलाप में अपनी शिरकत के लिए शर्तें रखीं: बड़े नामों की पूजा बंद की जाये, पंथवादिता तथा षड्यंत्र के तत्त्वों पर क़ाबू पाया जाये। मज़दूरों के अस्तित्वमान अन्तर्राष्ट्रीय संगठन को भावी सर्वहारा पार्टी के नाभिक में बदलने, विज्ञानसम्मत कम्युनिज़्म के सिद्धान्त को, जिसे उन्होंने तैयार करना आरम्भ कर दिया था, मज़दूर आन्दोलन के साथ ऐक्यबद्ध करने के लिए अनुकूल सम्भावनाओं के द्वार खुल गये थे। मार्क्स और एंगेल्स इन सम्भावनाओं का उपयोग करने से नहीं चूक सकते थे।

लीग की कांग्रेस की पहली ही मीटिंग में (लन्दन, जून १८४७) उसका नाम बदल कर कम्युनिस्ट लीग रख दिया गया। नया नाम संगठन के ध्येयों के अधिक अनुकूल था। एक नया चार्टर स्वीकृत किया गया, जिसने यह नारा — आदर्श-वाक्य — घोषित किया: "दुनिया के मज़दूरो, एक हो!"। इस नारे ने मज़दूरों के क्रांन्तिकारी आन्दोलन का एक बुनियादी सिद्धान्त, सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयतावाद का सिद्धान्त उद्घोषित किया, सर्वहारा के मुक्ति संघर्ष की सफलता की सबसे मुख्य शर्त पर ज़ोर दिया।

२८ सितम्बर, १८६४ को लन्दन के सेंट मार्टिन हाल में अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर संघ (पहला इंटरनेशनल) की स्थापना सर्वहारा एकजुटता के विकास में एक महत्वपूर्ण मंज़िल थी। ऐसे राष्ट्रोपरि कम्युनिस्ट निकाय के गठन ने अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर सर्वहारा एकजुटता को प्रकट करने की सम्भावना का ज़बर्दस्त प्रसार किया। संघ की जनरल कौंसिल के कार्यकलाप में विभिन्न देशों में हड़ताल-कार्रवाइयों के वास्ते पारस्परिक सहायता के संगठन को केन्द्रीय स्थान प्राप्त था। पहले इंटरनेशनल की स्थापना से पहले सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीय एकजुटता आन्दोलन अपेक्षाकृत विरल होते थे और पारस्परिक सहायता मुख्यतया घोषणाओं तथा वक्तव्यों तक सीमित होती थी।

अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर संघ का निर्माण हो चुकने पर अब एकजुटता अधिक ठोस तथा कारगर बन गयी। इस तरह संघ की जनरल कौंसिल

ने हड़तालें तोड़ने के लिए हड़तालतोड़कों का उपयोग नहीं होने दिया। अप्रैल १८६६ में, जब लन्दन की जालीदार तार बनानेवाली फ़ैक्टरी के मज़दूरों ने हड़ताल की, तो मालिकों ने यूरोप के अन्य देशों के बेरोज़गार मज़दूरों को कारखाने में काम पर लगाने का प्रयास किया। संघ की जनरल कौंसिल ने फ़्रांस, बेल्जियम और जर्मनी में संघ की राष्ट्रीय शाखाओं को इस बारे में सूचना दी और अपनी बारी में इन शाखाओं ने एकजुटता अभियान शुरू कर दिया। फलस्वरूप हड़तालियों को अपनी मुख्य मांगों की पूर्ति कराने में सफलता मिल गयी।

इसी तरह की घटनाएं उस ज़माने में लन्दन और एडिनबरा में दर्ज़ियों की हड़ताल के दौरान हुईं। पहले इंटरनेशनल की ऐसी कारगर कार्रवाइयां वर्ष-प्रतिवर्ष बढ़ती चली गयीं।

जनरल कौंसिल के तत्वावधान में अन्तर्राष्ट्रीय एकजुटता का अन्य रूप — हड़तालियों को आर्थिक सहायता का संगठन — कम कारगर नहीं रहा। जब फ़रवरी १८६७ में शर्लिरूआ ज़िले के हड़ताली बेल्जियन खान-मज़दूरों के विरुद्ध सैनिक भेजे गये और बहुत से हड़ताली मारे गये, तो संघ की जनरल कौंसिल ने ब्रिटेन की ट्रेड यूनियनों का आह्वान किया कि वे ज़ुल्म का शिकार बननेवालों को आर्थिक सहायता दें। काफ़ी मात्रा में धन एकत्र किया गया तथा शर्लिरूआ भेज दिया गया। संघ की फ़्रांसीसी शाखा ने भी ऐसा ही किया।

जर्मनी, आस्ट्रिया, इंगलैंड, फ़्रांस, अमरीका तथा बेल्जियम के मज़दूरों द्वारा दी गयी नक़द सहायता की बदौलत १८६८ के वसंत में जेनेवा में निर्माण-कार्य करनेवाले ३,००० मज़दूरों की हड़ताल विजय की प्राप्ति के साथ समाप्त हुई। संघ की जनरल कौंसिल ने अप्रैल १८६९ में बेल्जियम में खान-मज़दूरों की हड़ताल की सहायता के लिए और व्यापक अभियान संगठित किया। वहां हड़ताली खान-मज़दूरों के ख़िलाफ़ फिर सैनिक भेजे गये और क़त्लेआम किया गया। मज़दूर आन्दोलन के बहुत से सक्रिय कार्यकर्ता तथा संघ की शाखा के सदस्य गिरफ़्तार किये गये। संघ की जनरल कौंसिल ने मार्क्स की अपील जारी की, जिसमें उन्होंने बेल्जियन सत्ताधारी हल्क़ों की भर्त्सना की और बुर्जुआ प्रेस में इंटरनेशनल के विरुद्ध कुत्सापूर्ण मुहिम को बेनक़ाब किया। उन्होंने समस्त देशों के मज़दूरों का आह्वान किया कि ज़ुल्म के शिकार बने लोगों के लिए धन जमा करें। अपील का उत्साहपूर्वक समर्थन किया गया और बहुत बड़ी धनराशि जमा की गयी।

एंटवर्प की सिगार फ़ैक्टरी के मज़दूरों के साथ, जिन्होंने मार्च

से लेकर सितम्बर १८७१ तक हड़ताल की थी, एकजुटता की लंबी मुहिम एक और शानदार घटना थी। संघ की जनरल कौंसिल ने हड़तालियों को सहायता देने के प्रश्न पर विचार करने के लिए कई बैठकें कीं। एंगेल्स ने जर्मनी के सामाजिक-जनवादियों के केन्द्रीय अखबार—'वोल्क्सस्टाट'—में जर्मन मज़दूरों के नाम एक अपील प्रकाशित की, जिसमें उनका आह्वान किया गया था कि वे हड़ताल-तोड़कों की भर्ती न होने दें तथा हड़तालियों की चंदा देकर सहायता करें। जर्मनी, अमरीका, इंगलैंड और हालैंड में जमा किये गये धन और इसके साथ ही पड़ोसी देशों में हड़तालतोड़कों के विरुद्ध लक्षित पगों ने कारखाना मालिकों का प्रतिरोध भंग कर दिया।

कुल मिलाकर गत शताब्दी के सातवें दशक के अन्त से लेकर आठवें दशक के आरम्भ तक हड़ताल-आन्दोलन में ज़बर्दस्त उभार आया और लगभग प्रतिमाह एकजुटता मुहिमें चलायी गयीं। नित्यप्रति की घटनाएं बन जाने पर उन्हें बहुत से मेहनतकश स्वाभाविक बात मानने लगे।

अत: एकजुटता ने अत्यन्त व्यावहारिक महत्व का होने के अलावा लाखों-लाख मज़दूरों को अन्तर्राष्ट्रीयतावाद की भावना में शिक्षित-दीक्षित किया। अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर संघ और उसके निकायों के सोद्देश्य तथा नियमित समर्थन की बदौलत मज़दूर वर्ग के स्वत:स्फूर्त अन्तर्राष्ट्रीयतावाद ने अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्कों के ठोस रूपों में अभिव्यक्ति पायी।

पेरिस कम्यून ने सर्वहारा एकजुटता के विचार के विकास में अनन्य भूमिका अदा की। उसके अस्तित्व के पहले ही दिनों में कम्यून के समर्थन में इंगलैंड, बेल्जियम, हालैंड और स्विट्ज़रलैंड के अनेकानेक नगरों में जनव्यापी प्रदर्शन हुए। १६ अप्रैल, १८७१ को लन्दन में हुए प्रदर्शन में दसियों हज़ार मेहनतकशों ने भाग लिया। स्विट्ज़रलैंड में अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर संघ के स्थानीय संगठनों ने कम्यूनवालों को अमली सहायता देने के लिए एक विशेष समिति क़ायम की। बेल्जियम में पहले इंटरनेशनल के संगठनों ने कम्यून के लिए धन जमा किया।

पेरिस कम्यून की त्रासदीभरी नियति का मज़दूर वर्ग की जन-चेतना में सर्वहारा एकजुटता के विचार के विकास पर गहन प्रभाव पड़ा। कम्यूनवालों पर प्रतिक्रांतिकारियों द्वारा ढाये गये नृशंस अत्याचार के कारण सर्वहाराओं के बीच उनके प्रति गहरी सहानुभूति पैदा हुई तथा विरोध की लहरें उठीं। प्रवासी कम्यूनवालों की और मृतकों तथा

निर्वासितों के परिवारों की सहायता करना अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर संघ तथा अन्य मज़दूर संगठनों के लिए चिंता का मुख्य विषय बन गया था। यह सहायता और भी ज़्यादा आवश्यक हो गयी थी, क्योंकि फ़्रांस की प्रतिक्रियावादी सरकार ने दूसरे राज्यों से उन कम्यूनवालों को वापस करने की मांग की, जो पेरिस और फ़्रांस से गुप्त रूप से निकल भागने में सफल हो गये थे।

इंगलैंड और स्विट्ज़रलैंड में, जहां प्रवासी बड़ी संख्या में पहुंच रहे थे, अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर संघ की जनरल कौंसिल और उसकी राष्ट्रीय शाखाओं ने धन जमा करने की व्यवस्था की और प्रतिक्रान्ति का शिकार बननेवालों के लिए उपयुक्त कामकाज और मकान ढूंढने में मदद दी। समस्त स्विस जनवादी शक्तियों के ज़बर्दस्त आग्रह के कारण अधिकारी शरणार्थियों को राजनीतिक आश्रय देने के लिए विवश हुए।

पेरिस कम्यून और साथ ही पहले इंटरनेशनल के बढ़ते प्रभाव से भयभीत होने के कारण अधिकांश यूरोपीय सरकारों ने अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर संघ और उसकी राष्ट्रीय शाखाओं के विरुद्ध अपने दमनकारी निकायों की पूरी ताक़त झोंक दी। पहले इंटरनेशनल के संगठन सर्वत्र ग़ैरक़ानूनी घोषित कर दिये गये। दरअसल अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर संघ १८७२ में विघटित हो गया, हालांकि औपचारिक रूप से उसके कुछ केन्द्रीय संगठन यूरोप से, मुक्ति के लिए सर्वहारा वर्ग के केन्द्र से बहुत दूर अमरीकी धरती पर १८७६ तक क़ायम रहे।

१८७५ के उपरान्त मेहनतकशों की वर्ग-एकजुटता का प्रसार तथा गहनीकरण सर्वहारा पार्टियों की स्थापना, मार्क्सवाद के संस्थापकों द्वारा विज्ञानसम्मत कम्युनिज़्म के सिद्धान्त के विकास तथा अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर आन्दोलन के अधिकाधिक व्यापक क्षेत्रों में उसकी समझ के साथ घनिष्ठ रूप में जुड़े हुए थे। उस समय तक मार्क्सवाद यूटोपियन समाजवाद की बहुत सी धाराओं पर विजयी हो चुका था, जो, फलस्वरूप, अपना प्रभाव खो बैठीं और पृष्ठभूमि में धकेल दी गयीं।

बहुत से यूरोपीय देशों में समाजवादी तथा सामाजिक-जनवादी पार्टियों के आविर्भाव ने सर्वहारा वर्ग तथा उसके संगठनों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के नये रूपों को जन्म दिया। ये रूप थे: बिरादराना पार्टियों की कांग्रेस में प्रतिनिधिमंडल भेजना, कांग्रेसों के सिलसिले में अभिनंदन संदेश भेजना, आदि। चुनाव अभियानों के दौरान किशोर सर्वहारा पार्टियों द्वारा एक-दूसरे की माली मदद पारस्परिक सहायता का एक ठेठ रूप थी।

पार्टियों और ट्रेड यूनियनों के बीच प्रत्यक्ष संबंधों के ज़रिये, मज़दूर वर्ग के प्रेस के ज़रिये, जिसका द्रुत गति से विकास हो रहा था, समाजवादी पार्टियों के पदाधिकारियों के बीच वैयक्तिक सम्पर्कों के ज़रिये वर्ग-संघर्ष के अनुभव का आदान-प्रदान किया गया, आन्दोलन की नयी समस्याओं पर विचार किया गया, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के नये रूप तैयार किये गये। इन सब चीज़ों ने मज़दूर आन्दोलन को गलतियों तथा भूलों पर क़ाबू पाने में मदद दी।

अपनी कृतियों में मार्क्स तथा एंगेल्स ने सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के आम सिद्धान्त विकसित किये, जिन्हें विशिष्ट कार्यभारों तथा परिस्थितियों के अनुकूल ढाला गया। विज्ञानसम्मत समाजवाद के सृजनकर्ता मज़दूर आन्दोलन के बहुत से नेताओं को, जो उनसे सलाह मांगते थे, सदैव अत्यधिक सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक सहायता देते रहे। वे अत्यधिक पत्र-व्यवहार करते रहे और नयी पार्टियों के नेताओं के साथ निजी सम्पर्क रखते थे। इससे अन्तर्राष्ट्रीय सर्वहारा सम्बन्धों के विकास में मदद मिली।

रूस भी अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर आन्दोलन में नयी प्रक्रियाओं से अलग खड़ा नहीं रहा। रूस के एक पहले मज़दूर संगठन—रूसी मज़दूरों के उत्तरी संघ—के कार्यक्रम (१८७८) में संघ के कार्यकलाप को समूचे अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी आन्दोलन का अभिन्न अंग माना गया था: "हमारे पश्चिमी भाई लाखों-लाख लोगों की मुक्ति का झंडा उठा चुके हैं—हमारे लिए बस उसमें शामिल होने का काम बाक़ी है। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे और हमारी बिरादराना एकता एक ही शक्तिशाली जुझारू शक्ति में विलय हो जायेगी..."

पहले रूसी सामाजिक-जनवादी ग्रुप—श्रम-मुक्ति—ने अपने कार्यक्रम (१८८४) में इस पर ज़ोर दिया कि "समस्त देशों की समाजवादी पार्टियां वर्तमानकालीन अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर आन्दोलन के अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप को स्वीकार करती हैं और उत्पादकों की अन्तर्राष्ट्रीय एकजुटता के सिद्धान्तों की उद्घोषणा करती हैं।" इन सिद्धान्तों का समर्थन करते हुए रूसी सामाजिक-जनवादियों ने "समपूर्ण सभ्य संसार के मेहनतकशों के हितों" की एकरूपता को स्वीकार किया।

अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर आन्दोलन में एकतावादी प्रक्रियाएं यूरोप के बहुत से देशों तथा अमरीका में हड़ताल-आन्दोलन के साथ-साथ विकसित हुईं। सर्वहारा एकजुटता बड़ी-बड़ी हड़तालों के लिए निरन्तर बढ़ते समर्थन में प्रतिबिम्बित हुई। इसका ठेठ उदाहरण था १८८६

के आरम्भ में फ़ांस के दक्षिण में खान-मज़दूरों के देकज़्विले नामक नगर में कोयला खान-मज़दूरों की हड़ताल। दो हज़ार खान-मज़दूरों ने काम और रहन-सहन की असह्य अवस्थाओं, जुर्मानों की प्रणाली, प्रशासन द्वारा सताये जाने के विरुद्ध हड़ताल कर दी। सरकार ने खान-मालिकों का समर्थन किया और हड़ताल को कुचलने के लिए सैनिक भेजे।

परन्तु खान-मज़दूरों का घुटने टेकने का कोई इरादा नहीं था। अन्य देशों के मेहनतकशों द्वारा दी गयी सहायता की बदौलत वे पांच माह तक हड़ताल जारी रखने में समर्थ रहे। देकज़्विले के खान-मज़दूरों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सर्वहारा एकजुटता ने यह ज्वलंत रूप में सिद्ध कर दिया कि बहुत से देशों में अधिकाधिक मेहनतकशों में अपने अन्तर्राष्ट्रीय कर्त्तव्य की, समस्त संसार के मेहनतकश जनगण के हितों की एकरूपता की चेतना जग गयी है।

गत शताब्दी के नौवें दशक में अधिक विकसित पूंजीवादी देशों में मज़दूर वर्ग की चेतना मज़दूर आन्दोलन के बढ़ते अन्तर्राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप लगभग एक ही स्तर पर पहुंच चुकी थी। अपनी एकसमान स्थिति के कारण मेहनतकश एक जैसी मांगें पेश करने लगे थे। मज़दूर वर्ग का शोषण बंद करने और उसे सामाजिक-आर्थिक अधिकार प्रदान करने की मांगों का व्यापक प्रसार हुआ। आठ घंटे के कार्य-दिवस ने इन मांगों में मुख्य स्थान प्राप्त कर लिया था। यह गत शताब्दी के नौवें दशक के आरम्भ तथा बाद के वर्षों में यूरोप तथा अमरीका के मज़दूर आन्दोलन का मुख्य नारा बन गया था।

ये एकसमान, ठोस मांगें सर्वहारा वर्ग की और अधिक अन्तर्राष्ट्रीय एकता को, नये अन्तर्राष्ट्रीय सर्वहारा संगठन के गठन के लिए पूर्वाधारों के निर्माण को सशक्त संवेग प्रदान किये बिना नहीं रह सकती थीं। दूसरा इंटरनेशनल ऐसा ही संगठन बना। इसी प्रसंग में सर्वहारा एकजुटता के अन्तर्राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मई दिवस के उद्भव पर विचार किया जाना चाहिए। यह उद्भव अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर आन्दोलन के विकास की केवल निश्चित तथा पर्याप्त मंज़िल पर ही और उसमें सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के विचारों का व्यापक प्रसार होने पर ही सम्भव हो सकता था। इसमें १८८६ की शिकागो की घटनाओं ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की, जिनके साथ पहली मई के पूर्व-इतिहास का अन्त हो गया और इस उत्सव के स्वयं इतिहास का समारम्भ हुआ।

२. संघर्ष में जन्म

अमरीका में सबसे पहले मई दिवस प्रदर्शन को और १८८६ की उन त्रासदीभरी घटनाओं को हुए सौ साल से अधिक बीत चुके हैं, जब शिकागो में ३ तथा ४ मई को पुलिस ने मेहनतकशों का ख़ून बहाया था। तबसे प्रत्येक नया मई दिवस मनाते समय मज़दूर वर्ग और पूरी दुनिया के मेहनतकश कभी नहीं भूलते कि उनकी एकजुटता के दिवस का और साथ ही सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर आन्दोलन का जन्म पूंजीवाद तथा उसके समर्थकों के विरुद्ध घोर संघर्ष में हुआ था।

गत शताब्दी के नौवें दशक के मध्य में अमरीका गहन सामाजिक विषमताओं का देश था। इस बात पर ज़ोर देना पर्याप्त है कि उस ज़माने में मेहनतकश दिन में १६ घंटे तक काम करता था। यह अमरीका के लिए ऐसी शर्मनाक स्थिति थी, जिसका समय के साथ कोई मेल नहीं था, क्योंकि अमरीका तब तक संसार का अग्रणी औद्योगिक राष्ट्र बन चुका था। इस स्थिति का कारण मुख्यतया यह था कि अमरीका में ट्रेड यूनियन आन्दोलन का अपेक्षाकृत क्षीण विकास हुआ था। और यह अपनी बारी में बहुत-कुछ उन विशेष परिस्थितियों का परिणाम था, जिनमें मज़दूर वर्ग का वहां गठन हुआ था। १८८० के दशक तक वहां पश्चिम में स्वामीहीन भूमि विद्यमान थी, जिसका स्वामी बनने की सम्भावना उपलब्ध रहती थी। इस चीज़ ने सर्वहारा की वर्ग-चेतना के विकास को अवरुद्ध किया। उस समय हुनरमंद मज़दूरों का बहुत बड़ा भाग पहले आंग्ल-सेक्सन आबादकारों के वंशज थे और समाज में उन्हें विशेष स्थिति प्राप्त थी, जो औद्योगिक इजारेदारियों के बढ़ने के साथ-साथ सुदृढ़ बनती चली गयी थी।

"मज़दूर अभिजात वर्ग" बहुधा सर्वहारा जनसाधारण के, जो बहुधा नये आप्रवासी थे, हितों का ख़याल नहीं रखना चाहता था। उधर आप्रवासी नस्ली, धार्मिक, भाषाई तथा राष्ट्रीय अवरोधों के कारण विभक्त थे। इस सब बातों और बुर्जुआ राज्य की सरकार की मज़दूर विरोधी नीति ने मिलकर अमरीका में जनव्यापी मज़दूर आन्दोलन की प्रगति की राह में बहुत बड़ी बाधा डाली।

कुछ भी हो, १८८१ में वहां एक मज़दूर संघ की स्थापना हुई। अमरीका और कनाडा के औद्योगिक तथा व्यापार ट्रेड यूनियन संघ ने, जिसका नाम १८८६ में बदलकर अमरीकी श्रम संघ रख दिया गया था, मज़दूर आन्दोलन में प्रमुख भूमिका अदा करना शुरू किया। उसने अक्तूबर

१८८६ में अपनी कांग्रेस में आठ घंटे का कार्य-दिवस लागू किये जाने के बारे में ऐतिहासिक प्रस्ताव स्वीकृत किया। ट्रेड यूनियनों को इस प्रस्ताव के अनुसार १ मई, १८८६ से क़ानून बनवाने के लिए कार्रवाई करने का मिशन सौंपा गया।

८ घंटे के कार्य-दिवस के बारे में क़ानून बनवाने की कार्रवाई करने की ट्रेड यूनियनों से की गयी मांग का अभिप्राय क्या था? इस मांग को अमली जामा पहिनाने की कार्यविधि का १८८५ में संघ की कांग्रेस में विशदीकरण किया गया। ट्रेड यूनियनों तथा उद्यमपतियों के बीच बातचीत की इस आशा के साथ योजना बनायी गयी कि इसके फलस्वरूप दोनों पक्षों के बीच करार पर हस्ताक्षर हो जायेंगे। बातचीत के विफल होने की सूरत में ट्रेड यूनियनों को पहली मई १८८६ से हड़ताल आरम्भ करनी थी और हड़ताल की तैयारी १८८४ के अन्त में शुरू की गयी थी।

अखिल अमरीकी मई दिवस हड़ताल तथा प्रदर्शनों की तैयारी सबसे बड़े पैमाने पर देश के औद्योगिक केन्द्र—शिकागो—में हुई, जो सक्रिय मज़दूर आन्दोलन तथा अपनी जुझारू परम्पराओं के लिए सुप्रसिद्ध था।

क्रान्तिकारी संघाधिपत्यवादियों ने शुरू में ८ घंटे के कार्य-दिवस के लिए आन्दोलन में शामिल होने से इन्कार कर दिया था। उनका नगर के मज़दूर संगठनों पर बहुत बड़ा प्रभाव था, उन्होंने कहा कि यह मांग तो इन आठ घंटों में मज़दूरों पर मालिकों के पूर्ण अधिकार को स्वीकार करने और उजरती श्रम की प्रणाली न्यायोचित ठहराने के बराबर है। परंन्तु १८८६ के आरम्भ होने के उपरान्त उन्होंने सर्वहारा जनसाधारण से अलग-थलग रहने की अनिच्छा छोड़ दी एवं खुलेआम आन्दोलन में शामिल हो गये और उन्होंने संघर्ष को अधिक आमूलगामी बनाने के लिए पूरी-पूरी कोशिश की।

दूसरी तरफ़ पूंजीपति भी पहली मई के सिलसिले में सचेत रूप से तैयारी कर रहे थे, विशेष रूप से शिकागो में, जो उनका काफ़ी बड़ा गढ़ था। नेशनल गार्ड, घुड़सवार सैनिक, पुलिस तथा शेरिफ़ के "सहायक" सब हथियारबन्द थे और आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे थे। "नागरिकों की समिति" की, जो व्यापारियों को लेकर बनी थी, अविराम बैठक चल रही थी।

बुर्जुआ प्रेस ने शिकागो में मज़दूर आन्दोलन के विरुद्ध घृणा की मुहिम छेड़ दी थी। इस तरह १ मई, १८८६ को 'शिकागो मेल' ने अपने

अग्रलेख में लिखा: दो खतरनाक हत्यारे, दो कायर, जो दूसरों की पीठ पीछे छुपे हुए हैं और गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं, नगर में आज़ाद घूम रहे हैं। उनके नाम हैं एल्बेर्ट पार्सन्स और अगस्त श्पीस। और अगर कोई गड़बड़ी शुरू हो जाती है, तो समस्त ईमानदार नागरिकों को दूसरों के लिए मिसाल के तौर पर उन्हें दबोच लेना चाहिए। शिकागो के अखबारों ने हड़तालों तथा प्रदर्शनों में भाग लेनेवालों को, "अव्यवस्था फैलानेवालों" को निर्ममतापूर्वक कुचल देने तथा बड़े पैमाने पर बर्ख़ास्त करने की धमकी दी।

यद्यपि पहली मई को शिकागो की सड़कें हथियारबन्द सैनिकों और पुलिसमैनों से भरी हुई थीं, प्रदर्शन एक युगांतरकारी घटना सिद्ध हुआ। उसकी लंबे समय से और बहुत अच्छी तरह तैयारी की गयी थी और दसियों हज़ार मेहनतकशों ने उसमें भाग लिया। इतिहास में पहली बार मेहनतकशों ने मज़दूर वर्ग के संयुक्त प्रदर्शन की ज़बर्दस्त शक्ति को अनुभव किया, जिसके विरुद्ध सत्ता बल-प्रयोग करने का साहस नहीं कर सकी। अमरीका में उस दिन एक भी ऐसा बड़ा नगर नहीं था, जहां सर्वहाराओं ने ८ घंटे के कार्य-दिवस के पक्ष में हड़ताल या प्रदर्शन न किये हों। कुल मिलाकर पांच लाख से अधिक लोगों ने हड़ताल की थी।

परन्तु दो दिन बाद, सोमवार तीन मई को शिकागो के उद्योगपतियों ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। शहर में कई कारखानों के मालिकों ने ऐलान किया कि उन सब लोगों को काम से हटा दिया जायेगा, जिन्होंने हड़ताल में भाग लिया था। मैक्कार्मिक हार्वेस्टर फ़ैक्टरी घटनाओं का केन्द्र बन गयी, जहां तीन सौ हड़तालतोड़क पुलिस के भारी संरक्षण में लाये गये थे। इसका मुक़ाबला करने के लिए मज़दूरों ने पास के लकड़ी के गोदामों के अपने हड़ताली साथियों के समर्थन से विरोध-प्रदर्शन आयोजित किया। पुलिस ने निहत्थे मज़दूरों पर गोली चला दी और चार व्यक्तियों को मार डाला।

यह अपराध, निस्सन्देह, पुलिस की उकसावाभरी कार्रवाई थी, उसका उद्देश्य यह था कि मज़दूर स्वत:स्फूर्त ढंग से विरोध करें और सोच-समझ के बिना कार्रवाई करें, ताकि इसका मज़दूर आन्दोलन को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जा सके। कुछ अराजकतावादी ग्रुप इस उकसावे के जाल में फंस गये। न्यायोचित रोष के वशीभूत होने के कारण उन्होंने पर्चे छापे और बांटे, जिनमें ख़ून का बदला ख़ून से लेने और सशस्त्र संघर्ष करने का आह्वान किया गया था।

फिर भी अगले दिन हेमार्केट चौक में एक सभा में पार्सन्स और उनके साथी श्पीस तथा फ़ील्डेन ने मज़दूरों को कोई स्वत:स्फूर्त विरोध-कार्रवाइयां न करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि हड़ताल-संघर्ष के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसकी संगठनबद्धता सफलता का सबसे महत्वपूर्ण पूर्वाधार है। शिकागो के मेयर हैरिसन ने, जो इस सभा में उपस्थित थे, बाद में अपनी गवाही में कहा कि न तो भाषणों और न सभा ने क़ानून तथा व्यवस्था का अतिक्रमण किया। परन्तु ठीक इसी चीज़ ने प्रतिक्रियावाद की शक्तियों को आग-बबूला कर दिया था।

उस रात दस बजे से भारी वर्षा होने लगी थी। पार्सन्स और श्पीस और साथ ही मेयर हैरिसन चौक से रवाना हो गये थे। फ़ील्डन मंच पर अपना भाषण ख़त्म करनेवाले थे। उसी समय १८० हथियारबन्द पुलिसमैनों का एक दस्ता चौक में घुसा। पुलिस कप्तान ने भीड़ को तितर-बितर होने का आदेश दिया। सहसा ठीक उसी घड़ी उकसावे की कार्रवाई करनेवाले किसी व्यक्ति ने एक बम फेंका, जो फट गया। उससे एक पुलिसमैन मर गया और पांच घायल हो गये, जिनमें से सब के सब बाद में मर गये। इस चीज़ ने रक्तपात का नंगा नाच शुरू करने के संकेत का काम किया, जिसके दौरान दस मज़दूर मारे गये और लगभग २०० घायल हो गये।

सात "षड्यंत्रकारी"—श्पीस, फ़ील्डन, फ़िशर, एंगेल, लाइंग, श्वाब तथा नेबे—शीघ्र पकड़ लिये गये। पार्सन्स आठवें "षड्यंत्रकारी" थे, जिन्हें पुलिस गिरफ़्तार करने में सफल नहीं हुई थी। परन्तु अपने साथियों के साथ सहानुभूति के कारण उन्होंने कुछ सप्ताह बाद आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत ने इस बात का ज़रा भी ख़याल नहीं रखा कि आठ प्रतिवादियों में से केवल फ़ील्डन चौक में उस समय उपस्थित थे, जब वहां बम फटा था। मेहनतकशों के संघर्ष के नेताओं को बदनाम करना और सज़ा देना, दूसरों को चेतावनी देने के लिए "षड्यंत्रकारियों" को मौत की सज़ा देना, फिर मज़दूर आन्दोलन को कुचल देना—यह था उकसावाभरे "फ़ौजदारी के मामले" के पीछे राजनीतिक मन्तव्य। २० अगस्त, १८८६ को सात को फांसी की सज़ा और एक को पन्द्रह साल की क़ैद की सज़ा दे दी गयी।

अन्तर्राष्ट्रीय सर्वहारा वर्ग, विभिन्न देशों के समाजवादियों, व्यापक जनवादी क्षेत्रों ने बन्दियों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय एकजुटता का आन्दोलन छेड़ दिया था। उन्होंने गढ़े गये मामले पर पुनर्विचार की मांग की।

उनके प्रयत्नों को आंशिक सफलता मिली, क्योंकि केवल फ़ील्डन तथा श्वाब का मृत्यु-दंड आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। लाइंग मौत की सज़ा कार्यान्वित होने से पहले ही जेल में मर गये थे। ११ नवम्बर, १८८७ पार्सन्स, श्पीस, फ़िशर तथा एंगेल को शिकागो की जेल के अहाते में फांसी दे दी गयी।

शिकागो में इस शर्मनाक नरबलि के साढ़े पांच साल बाद हेमार्केट के शहीदों, शिकागो के सर्वहाराओं के नेताओं के सम्मान में एक स्मारक का अनावरण किया गया। यह समारोह २५ जून, १८९३ को सम्पन्न हुआ। अगले दिन इलिनोइस राज्य के नये गवर्नर एल्टगेल्ड ने अदालत के निर्णय को अवैध घोषित किया, बाक़ी बन्दियों को रिहा कर दिया, जजों, जूरी के सदस्यों तथा झूठे गवाहों की कटु आलोचना की, इस बात पर ज़ोर दिया कि बन्दी फांसी पर चढ़ाये गये अपने साथियों की ही भांति अदालती स्वेच्छारिता के शिकार बने हैं।

इस प्रकार १ मई, १८८६ का दिन अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर आन्दोलन के इतिहास में एक देश में सर्वहारा के पहले विशाल प्रदर्शन के रूप में स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गया। ट्रेड यूनियनों के नेताओं ने तमाम अमरीकी मेहनतकशों से आठ घंटे के कार्य-दिवस के लिए लड़ने की अपील की। इस मांग की पूर्ति के हेतु इसी संघर्ष ने कई वर्षों तक बहुत से देशों के मेहनतकशों के पहली मई के अभियान की मुख्य अन्तर्वस्तु निर्धारित की थी।

१८८६ का मई दिवस इसलिए महत्वपूर्ण है कि बहुजातीय अमरीकी मज़दूर वर्ग ने सर्वहारा एकजुटता की बढ़ती शक्ति प्रदर्शित की। पहली मई आगे चलकर मेहनतकशों की अन्तर्राष्ट्रीय एकजुटता का दिवस घोषित कर दी गयी। यह सब अमरीका में १८८६ की मई की घटनाओं को मई दिवसीय समारोह के इतिहास का समारम्भ मानने का आधार प्रदान करता है, हालांकि अन्तर्राष्ट्रीय उत्सव के रूप में उसे पहली बार केवल १८९० में मनाया गया।

३. "जुझारू मज़दूर वर्ग की पहली अन्तर्राष्ट्रीय कार्रवाई"

मई दिवस प्रदर्शन के लिए व्यापक तैयारियां १८९० में आरम्भ हुईं। चूंकि सर्वहारा वर्ग ने समस्त पूंजीवादी देशों में पहले कभी एक साथ प्रदर्शन नहीं किये थे, इस कारण मज़दूर नेताओं के सामने सर्वथा

विभिन्न प्रश्न उठ खड़े हुए। ये प्रश्न थे: क्या सर्वहारा एकजुटता के विचारों को अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर मज़दूर वर्ग के व्यापक जनसमुदायों ने पर्याप्त मात्रा में हृदयंगम कर लिया है? प्रदर्शन कैसे इस प्रकार किये जायें कि विभिन्न देशों में विद्यमान विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखा जा सके और साथ ही वे समग्र रूप में अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर आन्दोलन के हितों के अनुरूप हों?

पहले अन्तर्राष्ट्रीय मई दिवस के समारोह की तैयारियों के आरम्भ में एक अनन्य महत्वपूर्ण घटना हुई, जिसने मज़दूर संगठनों में प्रदर्शन की तैयारी के लिए ज़बर्दस्त उत्साह पैदा किया। राइख़्स्टाग के नियमित चुनावों में जर्मन सामाजिक-जनवादी पार्टी को ऐसी सफलता प्राप्त हुई, जो समस्त आशाओं से कहीं अधिक शानदार सिद्ध हुई। उसे १४,००,००० से अधिक वोट मिले और इस सर्वोच्च विधायी निकाय में उसके ३५ सदस्य चुने गये। इस विजय का महत्व समाजवादी पार्टियों तथा अन्य मज़दूर संगठनों के समक्ष स्पष्ट हो गया। इस सफलता का अर्थ था समाजवादियों के विरुद्ध अनन्य क़ानून का मंसूख होना, बिस्मार्क सरकार की कठोर आन्तरिक नीति का धराशायी होना। जैसा कि एंगेल्स ने लिखा, इस विजय के "फलस्वरूप... पूरा संसार भौचक्का रह गया।"* इसकी बदौलत पहले अन्तर्राष्ट्रीय मई दिवस की तैयारी काफ़ी हद तक आशा से अधिक अनुकूल परिस्थितियों में हुई।

१ मई, १८९० को एंगेल्स 'कम्युनिस्ट घोषणापत्र' के नये जर्मन संस्करण की भूमिका लिखने के काम में व्यस्त थे। इसमें उन्होंने यह बात याद की कि केवल ४० वर्ष पहले बहुत कम लोग उनके तथा मार्क्स के इस आह्वान को स्वीकार करते: "दुनिया के मज़दूरो, एक हो!" हालांकि एंगेल्स उस समय मई दिवस समारोहों का मुख्य परिणाम नहीं जान सकते थे, फिर भी उन्होंने उसकी सफलता की विश्वासपूर्वक भविष्यवाणी की थी: "...आज जब मैं ये पंक्तियां लिख रहा हूं, यूरोपीय तथा अमरीकी सर्वहारा वर्ग अपनी जुझारू शक्तियों का, **एक ही** सेना में, **एक ही** झंडे तले, **एक ही** तात्कालिक ध्येय के हेतु, सामान्य आठ घंटे के कार्य-दिवस की स्थापना के हेतु लामबन्द अपनी जुझारू शक्तियों का पुनरावलोकन कर रहा है।... और आज का दृश्य समस्त देशों

---

* फ़े० एंगेल्स, 'तो आगे क्या होगा?', १८९०।

के पूंजीपतियों तथा ज़मींदारों को यह प्रदर्शित कर देगा कि आज तमाम देशों के मज़दूर सचमुच ऐक्यबद्ध हो गये हैं।"*

पूंजीवादी तथा बुर्जुआ सरकारों ने मई दिवस प्रदर्शनों में भाग लेनेवालों के विरुद्ध जवाबी कार्रवाइयां कीं। ख़ास तौर पर जर्मनी के मालिक संघ ने ऐलान किया कि उन तमाम मज़दूरों को बर्ख़ास्त कर दिया जायेगा, जो बिना अनुमति के काम छोड़ कर चले गये थे या सामान्यतया किसी विश्वसनीय कारण के बिना काम पर नहीं आये। जिन उद्यमों में हड़तालियों की संख्या मज़दूरों की आम संख्या के दो तिहाई से ज़्यादा होगी, वहां उन्हें बर्ख़ास्त नहीं किया जायेगा, परन्तु मालिक "जवाबी हड़ताल" करेंगे और अपने कारख़ानों को तीन सप्ताह के लिए बन्द कर देंगे।

भयभीत फ़्रांसीसी बुर्जुआ वर्ग ने, जिसने कुछ ही समय पहले पेरिस कम्यून के दिन झेले थे, ३० हज़ार सैनिकों के पेरिस गैरिज़न को पुख़्ता बनाने के लिए अतिरिक्त कुमुक लाने की मांग की। बुर्जुआ वर्ग की चिन्ता दूर करने के लिए फ़्रांसीसी सरकार ने और तीन रेजिमेंटें और आठ तोप-बटालियनें राजधानी भेजीं। इन पगों के बावजूद कुछ बैंकपतियों ने अपना धन फ़्रांसीसी बैंक में स्थानान्तरित करने का निर्णय किया, जहां मेयर के कार्यालय की भांति सैनिक तैनात कर दिये गये थे और जिसे एक तरह का क़िला बना दिया गया था।

प्रान्तों में अधिकारियों की मई दिवस विरोधी कार्रवाइयों का स्वरूप आतंकपूर्ण था। उदाहरण के लिए, रीकामारी नगर के मेयर के आदेश पर एक पर्चा खान-मज़दूरों के नगर की दीवालों पर १ मई, १८९० की पूर्ववेला में प्रकट हुआ, जिसमें कहा गया था कि मई दिवस प्रदर्शनों का उद्देश्य अव्यवस्था की सहायता से सरकार को हानि पहुंचाना है। इसलिए उसमें बताया गया कि अधिकारी प्रत्येक प्रदर्शनकारी को बेरहमी से कुचल डालेंगे।

बुर्जुआ वर्ग द्वारा फ़ौरन ढूंढ लिये गये "मई दिवस विरोधी पगों" में से एक था राष्ट्रीय घृणा तथा पूर्वाग्रहों को भड़काना। फ़्रांसीसी बुर्जुआ अख़बारों ने आठ घंटे के कार्य-दिवस की मांग को अपने पाठकों के समक्ष जर्मनी की खोज के रूप में प्रस्तुत किया जो फ़्रांसीसी भावना के प्रतिकूल थी। उदाहरण के लिए, 'प्तीत रेपूब्लिक' अख़बार ने लिखा कि यदि जर्मन मार्क्सवादियों के विचारों को अमली जामा पहिनाया गया,

---

* वही।

तो दुनिया एक विशाल, नीरस मशीन बन जायेगी, जहां सब लोग हर सुबह एक ही समय जगेंगे, ताकि हर रात एक ही समय सो सकें; जीवन की विविधता लुप्त हो जायेगी।

अन्धराष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काते हुए सत्ताधारी क्षेत्र मुक्ति आन्दोलन के ग़द्दारों को अपने हितों के लिए इस्तेमाल करने से बाज़ नहीं आये। मिसाल के तौर पर, भूतपूर्व कम्यूनार्ड और ब्लांकीवादी प्रोतोत ने एक पुस्तिका छापी (ज़ाहिर है, अपने पैसे से नहीं)। इसमें उन्होंने हतप्रभ आम नागरिकों को बताया कि मई दिवस प्रदर्शन की पहल करनेवाला और कोई नहीं, केवल जर्मन जनरल स्टाफ़ है। उसने ही प्रदर्शन संगठित करने का विचार एंगेल्स को "सुझाया", ताकि फ़्रांसीसी अर्थव्यवस्था को इस तरह कमज़ोर बनाया जा सके। पुस्तिका में दिये गये कार्टून में 'प्रशियाई' एंगेल्स को जर्मन सेना के अफ़सरों के संग दिखाया गया।

अधिकारियों ने मज़दूर कार्रवाइयों को "उकसावा देनेवालों" का पता लगाने और उन्हें अलग-थलग करने का फ़ैसला किया। ज़ाहिर है, वे बहुसंख्य प्रवासियों के बीच "मिल गये"। उनमें से बहुत से लोगों को फ़ौरन गिरफ़्तार कर लिया गया। दूसरों को गृह मामलों के मंत्री की यह चेतावनी मिली: जो कोई हड़ताल में भाग लेगा, उसे तुरन्त देश से निकाल दिया जायेगा।

दमनकारी निकायों ने १८८६ में शिकागो के मज़दूरों पर अत्याचार के अपने अनुभव को इस्तेमाल किया। पेरिस और अन्य मज़दूर केन्द्रों में घेरे की हालत घोषित करने का बहाना पा सकने के लिए फ़्रांसीसी अधिकारियों ने "दुस्साहसियों", "अराजकतावादियों" और "जासूसों" की तलाश शुरू कर दी। और बेशक बड़े मौक़े से सुआसी में बारूद के गोदाम की "खोज" कर ली गयी, जिसके बाद गिरफ़्तारियां शुरू कर दी गयीं।

पहले अन्तर्राष्ट्रीय मई दिवस की तैयारियों के दौरान बुर्जुआ राज्यों ने मज़दूर आन्दोलन के विरुद्ध संघर्ष के सारे संचित साधनों का पूरी तरह उपयोग किया। परन्तु उनके प्रयत्न बहुधा विफल ही नहीं रहे, अपितु उनका उलटा असर भी हुआ।

जर्मनी तक में, जहां राइख़्स्टाग में जर्मन सामाजिक-जनवादी धड़े ने एक विशेष प्रस्ताव यह सिफ़ारिश करते हुए पास किया कि मज़दूर पहली मई को अपने काम की जगह न छोड़ें और जहां सेना तथा पुलिस लड़ने की मुद्रा में थी, हड़ताल ने जनव्यापी स्वरूप ग्रहण कर लिया था।

हड़ताल में मज़दूरों की कुल संख्या के लगभग दस प्रतिशत ने भाग लिया। बड़ी तादाद में हुई सभाओं तथा प्रदर्शनों में कहीं ज़्यादा लोग शामिल हुए। होएस्ट में उस समय ख़ून-ख़राबी हुई, जब पुलिस ने हड़तालियों पर गोली चलायी।

जूल गेद के, जो फ़ांसीसी मज़दूर पार्टी की स्थापना करनेवालों में से एक थे, अनुमानानुसार लगभग दस लाख लोगों ने हड़तालों तथा प्रदर्शनों में भाग लिया। पाल लफ़ार्ग ने लिखा: "जिन्हें यह याद है कि सामाजिक प्रश्नों में जनसाधारण की दिलचस्पी पैदा करना कितना कठिन था, वे इस मामले में हाल के वर्षों में और ख़ास तौर पर १ मई, १८९० के उपरांत हुई तब्दीलियां देखकर चकित रह जायेंगे। सामाजिक प्रश्न पर मज़दूर वर्ग का ध्यान केन्द्रित हो गया है। फ़ांसीसी समाजवादियों के पास अब मज़दूर जनसाधारण पर प्रभाव डालने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए शक्तिशाली साधन है। यह है: मई दिवस प्रदर्शन।" बेल्जियम, आस्ट्रिया-हंगरी, इटली, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, स्कैंडिनेवियन देशों, रूमानिया और अमरीका में बड़े-बड़े प्रदर्शन हुए।

१८९० में रूसी साम्राज्य में भी मई दिवस प्रदर्शन हुए। वारसा में, जो उस समय रूसी साम्राज्य का हिस्सा था, सांशी इस्पात कारख़ाने, ओर्टवाइन कारख़ाने और वारसा-वियेना रेलवेलाइन के तीसरे तथा पांचवें खातों में काम रुक गया। लोगों के ग्रुप नगर के मज़दूर मोहल्लों तथा सेंट अलेक्सांद्र चौक में जमा हुए। चूंकि तमाम समाजवादी छापेघर नष्ट कर दिये गये थे, इस कारण पांच वर्ष तक निष्क्रिय रहने के बाद मई दिवस पर फिर पर्चे बांटे गये। पुलिस और सेना के गश्ती दस्तों ने उस दिन बहुत से लोगों को गिरफ़्तार किया।

१ मई, १८९० को "मज़दूर" हस्ताक्षर युक्त पर्चे की प्रतियां पीटर्सबुर्ग में बांटी गयीं। उसमें भविष्यवाणी की गयी थी कि "वह समय आयेगा, जब रूसी जनता अपनी सदियों की नींद से जाग उठेगी, वह शक्तिशाली रूसी घूंसे को झकझोर देगी और डाकुओं के गिरोह को, जिसे सरकार... कहा जाता है, नष्ट कर देगी। पिछले दशक ने रूसी सर्वहारा वर्ग की चेतना को इतना अधिक आगे बढ़ाया है कि हम निकट भविष्य में अपना मई दिवस मनाने की आशा कर सकते हैं।..."

मज़दूर आन्दोलन के इतिहास के कतिपय बुर्जुआ अनुसंधानकर्ता यह मानते हैं कि मज़दूर उत्सव के रूप में मई दिवस आरम्भ में केवल

यूरोपीय तथा उत्तर अमरीकी परिघटना था। परन्तु १८६० में ही मई दिवस प्रदर्शन मेक्सिको नगर तथा हवाना में हो चुके थे। क्यूबा की राजधानी में २० हज़ार लोगों की सभा में भाग लेनेवालों ने यूरोपीय तथा अमरीकी मेहनतकशों के लिए, जिन्होंने उसी दिन प्रदर्शन किये थे, अपने समर्थन की घोषणा की थी और उनके साथ अपनी एकजुटता की भी घोषणा की थी, जिन्हें स्वेच्छाचारी सरकारों ने इन प्रदर्शनों में भाग लेने के अधिकार से वंचित कर दिया था। मई दिवस सभाएं अर्जेंटीना के ब्यूनोस-आयर्स, ला-प्लाटा, सांटा-फ़े, मेंडोस तथा अन्य नगरों में हुईं।

परन्तु इंगलैंड में न तो हड़तालों का और न प्रदर्शनों का कोई आयोजन किया गया था। प्रदर्शन आयोजित करने की संगठन समिति ने अगले इतवार, ४ मई को हाइड पार्क में होनेवाली जन-सभा पर अपने प्रयत्न केन्द्रित करने का निर्णय किया था। कतिपय मज़दूरों ने इसे दूसरे इंटरनेशनल की पहली कांग्रेस के निर्णयों से विचलन ठीक ही माना। ३० अप्रैल को मज़दूर संगठनों के राष्ट्रीय संघ ने मेहनतकशों के नाम एक अपील जारी की, जिसमें कहा गया था कि मई दिवस प्रदर्शन चाहे छोटा हो या बड़ा, वह तमाम देशों के मज़दूरों के साथ एकजुटता तथा एकता के सिद्धान्त की अभिपुष्टि है। और ठीक यही चीज़ पहली मई को विश्व इतिहास में अनुपम दिवस बनाती है। हाइड पार्क में पहली मई को जमा दो हज़ार लोगों ने इस अपील का समर्थन किया।

४ मई के प्रदर्शनों के संगठनकर्ताओं ने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को प्रदर्शन में भाग लेने के लिए जमा किया, जो एक रेकार्ड था: उसमें पांच लाख ने हिस्सा लिया। इसका मुख्य कारण यह था कि प्रदर्शन का दिन रविवार था। टेम्स नदी के तट के साथ-साथ दो जलूस निकले, दोनों अपने-अपने मार्ग पर बढ़े और विपरीत दिशाओं से हाइड पार्क में पहुंचे। यहां पार्क के पन्द्रह चौकों में सभाएं हुईं।

कुछ ही समय पहले गठित दूसरे इंटरनेशनल के आह्वान पर बहुत से देशों में लाखों-लाख लोगों की प्रदर्शनों में शिरकत (उनमें से बहुतों ने इस हेतु काम रोक दिया था) ही इस बात का ज्वलंत प्रमाण है कि वर्ग-एकजुटता का विचार किस प्रकार व्यापक सर्वहारा संस्तरों में गहराई तक पैठ गया है। जैसा कि एंगेल्स ने उस समय लिखा था: "सर्वहारा वर्ग का मई दिवस प्रदर्शन मात्र अपने सार्विक स्वरूप की बदौलत ही युगान्तरकारी घटना नहीं है, जिसने उसे जुझारू मज़दूर वर्ग की पहली

अन्तर्राष्ट्रीय **कार्रवाई** बना दिया। उसने विभिन्न देशों में अति सुखद सफलता की सिद्धि की सम्भावना प्रदान की।"*

४. महान अक्तूबर समाजवादी क्रान्ति से पूर्व मई दिवस

फिर भी १८९० के मई दिवस प्रदर्शन आठ घंटे के कार्य-दिवस की मज़दूरों की मांग की किसी भी देश में पूर्ति कराने में सफल नहीं रहे। यद्यपि दूसरे इंटरनेशनल की पेरिस कांग्रेस ने सर्वहारा एकजुटता का यह दिन फिर से मनाने की कोई बात नहीं सोची थी, फिर भी एक के बाद दूसरी समाजवादी तथा सामाजिक-जनवादी पार्टियों की कांग्रेसों ने १८९१ में भी मई दिवस प्रदर्शनों के बारे में प्रस्ताव पास किये।

बहुत से देशों में द्वितीय मई दिवस ने अधिकाधिक राजनीतिक स्वरूप ग्रहण किया। उदाहरणतः, आस्ट्रिया-हंगरी तथा बेल्जियम में ऐसा ही हुआ, जहां मई दिवस प्रदर्शनों ने, जिनमें लगभग सवा लाख लोगों ने भाग लिया था, सार्विक मताधिकार के एक व्यापक आन्दोलन का समारम्भ कर दिया। आयरलैंड में देश के इतिहास में सबसे बड़ी सभा पहली मई को डबलिन में हुई। परन्तु ब्रिटेन और जर्मनी जैसे बड़े राष्ट्रों समेत कई देशों में पहली बार रविवार, ३ मई को प्रदर्शनों की योजना बनायी गयी थी।

१ मई, १८९१ को आर्देन पर्वतीय क्षेत्र में फ़्रांसीसी नगर फ़ूर्मे में अत्यन्त नाटकीय घटनाएं हुईं। शान्त प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाकर दस को मार डाला गया। यह १८८६ की शिकागो घटनाओं का फ़्रांसीसी रूपान्तर था। क़त्लेआम को न्यायोचित ठहराने के लिए अधिकारियों ने मज़दूर पार्टी के एक स्थानीय नेता तथा वैदेशिक मामलों से सम्बन्धित पार्टी सचिव पाल लफ़ार्ग को गिरफ़्तार कर लिया और उनपर "सशस्त्र कार्रवाई भड़काने" का आरोप लगाकर उन्हें क़ैद की सज़ा दिला दी।

काले नगर में गोलीकांड में मरनेवालों की अन्त्येष्टि में ३०,००० व्यक्तियों ने भाग लिया और उसके बाद विरोध-प्रदर्शन किया। विभिन्न

* फ़े० एंगेल्स, 'लन्दन में चार मई', १८९०।

देशों की समाजवादी पार्टियों तथा ट्रेड यूनियनों ने अधिकारियों की मनमानी कार्रवाइयों पर रोष तथा फ़्रांस के जुझारू सर्वहारा वर्ग के साथ एकजुटता प्रकट की।

रूस की तत्कालीन राजधानी पीटर्सबुर्ग* में सर्वहारा वर्ग ने मई माह के प्रथम रविवार को अपना पहला मई दिवस मनाया, जिसमें २०० व्यक्तियों ने भाग लिया। उनका नारा था: "दुनिया के मज़दूरो, एक हो!" और उन्होंने एकतंत्र का तख़्ता उलटने का आह्वान किया। जो लोग गुप्त सभाओं में बोले, उनके भाषण श्रम मुक्ति ग्रुप की एक पुस्तिका में प्रकाशित किये गये। युवक लेनिन ने इन भाषणों का अत्यंत उच्च मूल्यांकन किया और उन्हें राजनीतिक भाषण कहा।**

दूसरे इंटरनेशनल की दूसरी कांग्रेस (ब्रुसेल्स, १८९१) ने मई माह के दो दिवसों की घटनाओं का लेखा-जोखा लिया। वक्ताओं की सर्वसम्मत राय थी कि ये दो दिवस पूरे अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर आन्दोलन के लिए बहुत लाभप्रद रहे हैं और उन्होंने इस बात का आह्वान किया कि मई दिवस हर वर्ष मनाया जाये। कांग्रेस ने पहली मई को वार्षिक और सार्विक रूप से प्रदर्शन करने का निर्णय किया और सुझाव दिया कि उस दिन जहां कहीं सम्भव हो, काम रोक दिया जाये।

समाजवादी पार्टियों और उनकी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना और विभिन्न देशों में मई दिवस प्रदर्शन जैसी मेहनतकशों की एक साथ कार्रवाइयों को संगठित करने की ज़रूरत ने भिन्न-भिन्न देशों की बिरादराना पार्टियों की कार्रवाइयों के बेहतर समन्वय की आवश्यकता को जन्म दिया। अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय कार्यभारों को मिलाने की समस्या के प्रति सही रुख़ अधिकाधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा था।

एंगेल्स ने ऐसा रुख़ तैयार करने और जर्मन सामाजिक-जनवादी पार्टी की ग़लतियां सुधारने में बहुत बड़ा योग दिया। दूसरे इंटरनेशनल की ब्रुसेल्स कांग्रेस के उपरान्त इस पार्टी ने १८९२ के मई दिवस की कार्रवाइयों को प्रदर्शनों और सभाओं तक सीमित करने परन्तु तालाबन्दी के ख़तरे को ध्यान में रखते हुए काम न रुकवाने का फ़ैसला किया था।

---

* पीटर्सबुर्ग का नाम अगस्त १९१४ में बदलकर पेत्रोग्राद रख दिया गया था। १९२४ से वह लेनिनग्राद के नाम से विख्यात है।

** का० मार्क्स, 'विज्ञापनों पर कर।—रूस के कार्यकलाप।—हालैंड।—यूरोप के संयुक्त राज्य', १८५३।

इन नीति की एंगेल्स ने बहुत तीखी आलोचना की। उन्होंने इसे अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर आन्दोलन पर प्रहार माना, क्योंकि उसमें जर्मन सामाजिक-जनवादी हरावल थे।

आठ घंटे का कार्य-दिवस दस वर्षों से अधिक तक मई दिवस प्रदर्शनों में मुख्य मांग बना रहा, हालांकि गत शताब्दी के अन्तिम दशक तक यह स्पष्ट हो चुका था कि यह सदा के लिए सार्विक मांग नहीं बनी रह सकती, खास तौर पर इस कारण कि कुछ देशों में मेहनतकश अपनी यह मांग पूरी कराने में सफल हो चुके थे। इन परिस्थितियों में पहली मई मनाने के बारे में दूसरे इंटरनेशनल की ज़्यूरिख कांग्रेस (अगस्त १८९३) के प्रस्ताव का विशेष महत्व था। उसमें एकजुटता के मेहनतकशों के दिवस को राजनीतिक रूप देने की आवश्यकता स्वीकार की गयी थी। उसमें कहा गया: "आठ घंटे के कार्य-दिवस के लिए पहली मई के प्रदर्शन को साथ ही सामाजिक परिवर्तनों के ज़रिये वर्गगत भेदों को नष्ट कर देने के मेहनतकशों के सुदृढ़ संकल्प का प्रदर्शन बनना चाहिए।..."

निस्सन्देह, मई दिवस के इतिहास में उतार-चढ़ाव आते रहे, जो मुख्यतया वर्ग-संघर्ष के उतार-चढ़ावों से सम्बन्धित थे। इस तरह गत शताब्दी के नौवें दशक तक कुछ पूंजीवादी देशों में मई दिवस आम उत्सवों की भांति मनाया जाने लगा और बुर्जुआ वर्ग से बड़ी टक्करें विरल घटनाएं हो गयीं।

उदाहरण के लिए, जर्मनी में इस बात के बावजूद कि मई दिवस ने वहां अत्यन्त जनव्यापी स्वरूप ग्रहण कर लिया था, देश के बुर्जुआ वर्ग को, जो दुनिया में सबसे अधिक एकाश्म तथा संगठित था, इस बात में सफलता मिल गयी कि प्रदर्शन खुली जगहों में न हों। यह स्थिति वर्षों तक जारी रही। बेल्जियम में प्रदर्शन जल्द ही आम क़िस्म के उत्सव बन गये, जिनमें खेल-कूद, तमाशों, आतिशबाज़ी, यही नहीं, कार्निवालों का आयोजन होता था।

इंगलैंड में भी पहली मई का दिन समस्त मेहनतकशों की अन्तर्राष्ट्रीय एकजुटता के उत्सव के रूप में निर्धारित करने में सफलता नहीं मिली थी। मई दिवस मई के पहले इतवार को मनाया जाता था। और यद्यपि यह इतवार के दिन मनाया जाता था, उसमें भाग लेनेवालों की संख्या कभी एक लाख से अधिक नहीं बढ़ी। यह संख्या १८९० की तुलना में, जब पांच लाख लोगों ने भाग लिया था, निस्सन्देह, अत्यन्त कम थी। अंग्रेज समाजवादी मई दिवस को धीरे-धीरे श्रम तथा शान्ति के पर्व

के रूप में मनाने लगे, जिसमें लन्दन के पास क्रिस्टल पैलेस में बड़ा रंगमंचीय कार्यक्रम मुख्य आकर्षण हुआ करता था।

अमरीका में गोम्पर्स के, जो समाजवाद के विचारधारात्मक विरोधी थे, नेतृत्व में अमरीकी श्रम संघ का झुकाव वर्गों के बीच सहयोग की ओर हो गया था। इस चीज़ ने मई दिवस समारोह बड़े पैमाने पर मनाने की राह में बाधा डाली। यही नहीं, इस कारण अमरीकी श्रम संघ के यूरोपीय ट्रेड यूनियनों के साथ, जो सब आंग्ल ट्रेड यूनियनों को छोड़कर उजरती श्रम की प्रणाली मिटाने के पक्ष में थीं, सम्बन्ध वस्तुत: भंग हो गये थे।

मई दिवस आन्दोलन अधिकाधिक नये देशों में फैलता जा रहा था। १८९३ से यूनानी मज़दूर एकजुटता का यह दिवस मनाने लगे। १८९८ में सरकारी प्रतिबन्ध के बावजूद मई दिवस का जलूस बुल्गारिया की राजधानी सोफ़िया की सड़कों से गुज़रा।

रूस में पूंजीवाद का विकास तथा मज़दूर आन्दोलन की संवृद्धि, मार्क्सवाद का प्रसार तथा लेनिन के, जिनके नेतृत्व में १८९५ में मार्क्सवादी ग्रुप 'मज़दूर वर्ग की मुक्ति के लिए संघर्ष की लीग' में ऐक्यबद्ध हो गये थे, सक्रिय क्रान्तिकारी कार्य की शुरूआत, बहुत से औद्योगिक केन्द्रों में तथा देश के दूर-दराज़ के इलाक़ों में सामाजिक-जनवादी संगठनों का आविर्भाव — इन सबने मई दिवस आन्दोलन को तूफ़ानी गति से बढ़ाने में मदद दी।

१८९५ में मास्को की ३५ मिलों, कारख़ानों तथा वर्कशापों के ३०० प्रतिनिधियों ने राजधानी के उपनगर के पेरोवो रेलवे स्टेशन के समीप मास्कोवासी मज़दूरों की सबसे पहली ग़ैरक़ानूनी सभा आयोजित की थी। गत शताब्दी के अन्तिम दशक में रूस के क़रीब-क़रीब सभी बड़े औद्योगिक केन्द्रों में इस या उस रूप में मई दिवस प्रदर्शन होते रहे, जो, नियमत:, राजनीतिक स्वरूप के होते थे।

तत्कालीन मई दिवस प्रदर्शनों का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू था शान्ति के लिए तथा युद्ध के विरुद्ध संघर्ष के नारे का धीरे-धीरे उभरते जाना। दूसरे इंटरनेशनल की ब्रुसेल्स कांग्रेस (१८९१) और ज़्यूरिख़ कांग्रेस (१८९३) के प्रस्तावों ने पहली बार शान्ति के हेतु, सैन्यवाद और युद्ध के ख़तरे के विरुद्ध संघर्ष के साथ मई दिवस के अटूट सम्बन्ध की चर्चा की।

पूंजीवादी राज्यों की विदेश नीति पर तथा युद्ध और शान्ति के प्रश्नों के समाधान पर मज़दूर वर्ग और समस्त मेहनतकशों के प्रभाव की

समस्या लंबे अर्से से सर्वहारा आन्दोलन के नेताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती रही। गत शताब्दी के सातवें दशक में मार्क्स ने लिखा था कि विदेश नीति के क्षेत्र में प्रतिक्रियावादी क्षेत्रों के अपराधों ने "मज़दूर वर्ग को अन्तर्राष्ट्रीय नीति के रहस्यों को समझने, अपनी सरकारों की कूटनीतिक गतिविधियों पर नज़र रखने और ज़रूरत पड़ने पर अपने पास उपलब्ध सारे साधनों से उनके विरुद्ध कार्रवाइयां करने का कर्त्तव्य बताया है।"*

मार्क्स को यक़ीन था कि इतिहास के रंगमंच पर मज़दूर वर्ग के उद्भव के उपरान्त जनसाधारण विदेश नीति पर असर डाल सकते हैं। इसका प्रमाण उन्होंने ब्रिटिश सत्ताधारी क्षेत्रों को अमरीकी गृहयुद्ध में दक्षिण के दास-स्वामियों की ओर से हस्तक्षेप करने से रोकने में आंग्ल मेहनतकशों की संयुक्त कार्रवाइयों की सफलता में देखा। मार्क्स ने इस बात का उल्लेख करते हुए कि ब्रिटिश मज़दूर वर्ग ने "पश्चिमी यूरोप को अटलांटिक महासागर के उस पार दासता को बनाये रखने और उसका प्रचार करने के दुस्साहसिकताभरे शर्मनाक जेहाद में सीधे जा कूदने से" ** बचाया, उसकी कार्रवाइयों का बहुत ऊंचा मूल्यांकन किया। १८८६-१८८७ में फ़्रांसीसी-जर्मन युद्ध के ख़तरे के ख़िलाफ़ विश्व सर्वहारा वर्ग की कारगर संयुक्त कार्रवाइयों ने मार्क्स के शब्दों की सार्थकता पुन: सिद्ध कर दी।

जब पूंजीवाद ने विकास की साम्राज्यवादी मंज़िल में प्रवेश किया, तो मार्क्स द्वारा उजागर की गयी उसकी विशेषता और गहन बन गयी: अति मुनाफ़े बटोरने की ख़ातिर मानवजाति के विरुद्ध अपराधों समेत किसी भी तरह के अपराध करने की पूंजीवाद की तत्परता, और इसके साथ-साथ बुर्जुआ राज्यों की आन्तरिक तथा विदेश नीतियों में सैन्यवादी प्रवृत्तियों की संवृद्धि। साम्राज्यवादी क्षेत्रों का लालच और निर्ममता अब समस्त राष्ट्रों के अस्तित्व के लिए ख़तरा बन गये और समस्त श्रमजीवी तथा नेक लोगों की अन्तर्राष्ट्रीय एकजुटता ही उनका मुक़ाबला कर सकती थी।

यह अनुभव करते हुए १९०० में दूसरे इंटरनेशनल की पेरिस कांग्रेस ने राजनीतिक क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय एकजुटता के प्रदर्शनों से सक्रिय अन्तर्राष्ट्रीय कार्रवाइयों की, सैन्यवाद के विरुद्ध आम संघर्ष में संक्रमण करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। एक साल बाद दूसरे इंटरनेशनल

---

* का० मार्क्स, 'अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर संघ का संस्थापन-घोषणापत्र', १८६४।
** वही।

के अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी ब्यूरो ने तमाम देशों के मज़दूरों से सैन्यवाद तथा युद्ध के विरुद्ध प्रबल जनव्यापी एकजुटता प्रदर्शन करने का आह्वान किया। उसमें कहा गया था: "पूंजीवाद इससे पहले कभी इतनी उद्दंडता के साथ पेश नहीं आया था: उसने पूरी दुनिया को अपने भयावह पंजों से दबोच लिया है, वह दुनिया के तमाम भागों में युद्धों के बीज बो रहा है, ताकि ज़मीन और उत्पादन के साधन हथियाये जा सकें, अपने सीमाशुल्क युद्धों से वह जनगण के बीच भ्रातृघातक जनसंहार और नस्ली घृणा को भड़का रहा है। वह एशिया तथा अफ़्रीका के जनगण के साथ अनाचार कर रहा है और उन्हें लूट रहा है।... पूरे संसार में युद्ध हो रहा है; फ़ौजी बजट बढ़ते जा रहे हैं, अविराम राइफ़लों, तोपों तथा जलयानों के निर्माण पर, बैरकों के निर्माण तथा हज़ारों-हज़ार सैनिकों को हथियारबन्द करने पर विशाल धनराशियां भस्म की जा रही हैं, ताकि क़त्ल और विनाश किया जा सके।" मई दिवस की युद्धविरोधी परम्पराएं मई दिवस समारोहों का स्थायी कारक बन गयीं और आज तक बनी हुई हैं।

२०वीं शताब्दी के आगमन पर रूस में मई दिवस आन्दोलन में आम उभार आया। १९०० में ख़ारकोव नगर में एक बड़ी हड़ताल और एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। मज़दूरों ने "एकतंत्र मुर्दाबाद!" का नारा लगाते हुए राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग की। लेनिन ने इस घटना को असाधारण बताया, जिसने रूसी मज़दूरों की राजनीतिक क्षमता सिद्ध की: "हड़ताल में मज़दूरों की बड़ी पैमाने पर शिरकत, सड़कों पर विशाल जन-सभाएं, लाल झंडों का फहराया जाना, घोषणापत्रों में पेश मांगों का ऐलान किया जाना, इन मांगों का क्रान्तिकारी स्वरूप: आठ घंटे का कार्य-दिवस तथा राजनीतिक स्वतंत्रता। इस कपोल-कल्पना का कि रूसी मज़दूर अभी राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार नहीं हुए हैं,... ख़ारकोव के मई दिवस समारोह ने पूरी तरह खंडन कर दिया है।"*

क्रान्तिकारी मज़दूर आन्दोलन का केन्द्र खिसक कर रूस में आ पहुंचा था। लेनिनवादी अख़बार 'इस्क्रा' ('चिनगारी'), जिसका पहला अंक दिसम्बर १९०० में निकला था, जनसाधारण के संघर्ष का सफलतापूर्वक नेतृत्व कर रहा था। अख़बार ने १९०१ के मई दिवस की तैयारी में सक्रिय भाग लिया। १९०० की शरद ऋतु में लेनिन ने लिखा: "समय आ चुका है कि यथासम्भव अधिकाधिक केन्द्र इस समारोह की परिधि में लाये जायें, कि यह केवल शिरकत करनेवालों की संख्या

---

* व्ला० इ० लेनिन, 'ख़ारकोव में मई दिवस', भूमिका, १९००।

के मामले में ही नहीं, अपितु उनकी संगठनात्मकता, उनकी चेतनता, रूसी जनता की राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए और फिर सर्वहारा के वर्ग विकास और समाजवाद के लिए उसके खुले संघर्ष के वास्ते मुक्त क्षेत्र के लिए अरोध्य संघर्ष शुरू करने के संकल्प के मामले में भी यथासम्भव प्रभावोत्पादक हो।..."* इस मांग की पूर्ति के लिए रूसी सामाजिक-जनवादी मज़दूर पार्टी ने पहली मई से काफ़ी पहले पूरे रूस में पर्चे बांटे। फलस्वरूप १९०१ से लेकर १९०३ तक मई दिवस प्रदर्शन रूस में रूसी सामाजिक-जनवादी मज़दूर पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी पैमाने पर आयोजित हुए।

१९०५ की क्रान्ति के आरम्भ में मई दिवस ज़ारशाही के साथ ज़बर्दस्त टक्करों का दिवस था। ज़ार की खुफ़िया पुलिस ने मई दिवस प्रदर्शनों में मज़दूरों की व्यापक शिरकत न होने देने के लिए पहले ही गिरफ़्तारियां कर डालीं और कई सौ अग्रगामी मज़दूरों को पीटर्सबुर्ग से बाहर निकाल दिया। परन्तु इन पगों के बावजूद हज़ारों-हज़ार मेहनतकश रविवार, पहली मई को सड़कों पर उतर आये। अगले दिन हड़तालों की ज़बर्दस्त लहर आ गयी, जिनमें लगभग २०० नगरों में २,२०,००० व्यक्तियों ने भाग लिया। १९०६ के मई दिवस प्रदर्शन भी कम व्यापक नहीं थे। अकेले पीटर्सबुर्ग नगर में लगभग १,१०,००० लोगों ने हड़ताल की। १९०७ में भी, जब क्रान्तिकारी टकरावों में उतार आ गया था, पहली मई दिवस की हड़तालों में १,१५,००० मज़दूरों ने भाग लिया।

१९०५ की क्रान्ति के दौरान अन्य देशों के मज़दूरों और साथ ही उनके संगठनों के साथ रूसी सर्वहारा के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध सुदृढ़ बने। पश्चिम में एकजुटता आन्दोलन ३१ जनवरी, १९०५ को 'तमाम देशों के मेहनतकशों के नाम' शीर्षक घोषणापत्र दूसरे इंटरनेशनल द्वारा स्वीकृत किये जाने के बाद उल्लेखनीय रूप से सशक्त बना। उसमें दुनिया के मेहनतकशों का आह्वान किया गया था कि वे रूसी क्रान्ति की हर सम्भव तरीक़े से सहायता करें।

बेल्जियन समाजवादी तथा अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी ब्यूरो के सचिव क० ह्यूइस्मान्स की सहायता और साथ ही पश्चिम प्रशियाई सामाजिक-जनवादियों की सहायता से रूस में गुप्त रूप से हथियार पहुंचाये गये। डच ट्रेड यूनियनों ने भी बीस लाख कारतूस गुप्त रूप

---

* वही।

से रूस में पहुंचाये। ३१ जुलाई, १६०७ तक दूसरे इंटरनेशनल के रूसी कोश में कुल मिलाकर डेढ़ लाख फ़्रांक जमा हो चुके थे। अपने मई दिवस प्रदर्शनों तथा सभाओं में फ़्रांसीसी मज़दूरों ने क्रान्ति को कुचलने के लिए ज़ारशाही सरकार को सोना क़र्ज़े में देने के फ़्रांसीसी वित्तीय क्षेत्रों के इरादे की निर्णायक रूप से निन्दा की। वे जां ज़ोरेस द्वारा पेश नारा लगाते रहे: "ज़ारशाही को एक भी कौड़ी नहीं!" इसपर लेनिन ने लिखा: "रूसी सरकार के पास अपना अन्तर्राष्ट्रीय रिज़र्व है: जर्मनी, आस्ट्रिया तथा अन्य देशों की प्रतिक्रियावादी सरकारें। परन्तु हमारे पास भी शक्तिशाली अन्तर्राष्ट्रीय रिज़र्व है: यूरोप का समाजवादी सर्वहारा वर्ग। ..." *

रूस में क्रान्ति के कुचले जाने के बाद वहां पहली मई का उत्सव मनाने का स्वरूप कुछ वर्षों के लिए बदल गया था। प्रतिक्रियावाद की अवस्थाओं में राजनीतिक और आर्थिक हड़तालें कम हो गयी थीं, मई दिवस पर मज़दूरों की सभाएं फिर ग़ैरक़ानूनी करार दे दी गयीं। उनमें उपस्थिति अपेक्षाकृत कम होती थी। अक्सर वे विफल हो जाती थीं तथा अग्रणी मज़दूर गिरफ़्तार कर लिये जाते थे।

साथ ही अन्य पूंजीवादी देशों में विशेष रूप से रूसी क्रान्ति के फलस्वरूप मई दिवस प्रदर्शनों में नया उभार आया। पहली मई, १६०६ को फ़्रांस में मई दिवस के आयोजन ने नया संवेग प्रदान किया। वहां बीस वर्ष पहले के अमरीकी उदाहरण का अनुसरण करते हुए तैयारियां शुरू कर दी गयी थीं। १६०४ में आम श्रम संघ की कांग्रेस में बड़े पैमाने पर आन्दोलन शुरू करने का निर्णय किया गया था, ताकि मज़दूर पहली मई, १६०६ से प्रतिदिन आठ घंटे से अधिक काम करने से स्वयं इन्कार कर दें। मई दिवस से १८ माह पूर्व लाखों-लाख पर्चे बांटे गये तथा हड़ताल आन्दोलन निश्चित दिन से पहले ही शुरू हो गया था।

परन्तु क्लेमांसो की सरकार ने जवाबी कार्रवाई की। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए फ़्रांसीसी घुड़सवार सेना को सावधान कर दिया गया था। पेरिस तथा उन अन्य नगरों में घेरेबन्दी की स्थिति घोषित कर दी गयी थी, जहां प्रदर्शनों की आशा की जा रही थी।

१८८६ में शिकागो की ही भांति सरकार अराजकतावादियों के षड्यंत्र का पता लगाने में "सफल हो गयी थी"। कहा गया कि अर्ज़ांतेई पुल के नीचे रखे बारूद का "पता लगा है"। इस चीज़ ने पेरिस

---

* व्ला० इ० लेनिन, 'प्रतिक्रियावादियों के षड्यंत्र और दंगाइयों की धमकियां', १६०६।

में मई दिवस को ८०० व्यक्तियों को गिरफ़्तार करने का बहाना मुहैया किया, जिनमें आम श्रम संघ के नेता भी थे। यद्यपि हड़ताल अगले दिन भी जारी रही, उसमें भाग लेनेवालों की संख्या घट गयी थी। १९०६ में फ़्रांस का मई दिवस वह पैमाना हासिल नहीं कर सका, जो उसके संगठनकर्ताओं ने सोचा था। फिर भी उसने सर्वहारा एकजुटता की जुझारू परम्पराओं को पुनरुज्जीवित करके केवल फ़्रांस में ही नहीं, अपितु अन्यत्र भी पहली मई के उत्सव में नयी शक्ति का संचार किया।

आगे चलकर नाना देशों में मई दिवस प्रदर्शन सभा-कक्षों से शहरों की सड़कों तथा चौराहों में स्थानान्तरित हो गये। उदाहरण के लिए, जर्मनी में १९१० में मई दिवस समारोहों ने तूफ़ानी स्वरूप अपनाया। बर्लिन में दस लाख मज़दूरों ने हड़ताल की, डेढ़ लाख ने प्रदर्शनों में भाग लिया। दो लाख व्यक्तियों ने हैम्बुर्ग तथा एक लाख ने म्यूनिख़ की सड़कों में जलूस निकाले।

मई दिवस आन्दोलन ने लैटिन अमरीका में भी ज़ोर पकड़ा, जो उस समय पूंजीवाद का सुदूरवर्ती अंचल था। चिली में १९०७ में सान्तियागो, वाल्पाराइसो तथा कोयला-खान नगर इकीके में पहली बार मई दिवस मनाया गया। अर्जेंटाइना में मई दिवस प्रदर्शनों के दौरान उनमें भाग लेनेवालों तथा पुलिस के बीच कई बार रक्तपातपूर्ण टक्करें हुईं। अधिकारियों के दमनचक्र के फलस्वरूप मज़दूर आन्दोलन की तमाम शाखाओं में एकजुटता की लहर पैदा हो गयी। १९०९ में मई दिवस प्रदर्शन के अवसर पर गोलीकांड के बाद आम हड़ताल भड़क उठी थी, जिसमें दो लाख व्यक्तियों ने भाग लिया था।

रूस की लेना नदी पर सोना-खानों में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियों की बौछार ने देश में मज़दूर आन्दोलन के विकास को ज़बर्दस्त संवेग प्रदान किया। यह घटना सर्वहारा एकजुटता दिवस के कुछ ही समय पूर्व, ४ अप्रैल, १९१२ को हुई थी।

ज़ारशाही की इस अत्याचारपूर्ण कार्रवाई ने समस्त मेहनतकश जनगण में क्रोध की आग भड़का दी थी। उस वर्ष अप्रैल में ही ७०० राजनीतिक हड़तालें हुईं और मई दिवस विरोध-आन्दोलन का शिखर बन गया था। ५० रूसी गुबेर्नियाओं* में एक हज़ार हड़तालें हुईं, जिनमें चार लाख लोगों ने भाग लिया। इन प्रदर्शनों में अधिकांश राजनीतिक थे और हड़तालों के साथ-साथ, नियमत: सड़कों पर प्रदर्शन होते थे।

---

* गुबेर्निया-- ज़ारकालीन रूस में प्रशासनिक तथा क्षेत्रीय इकाई।

हड़तालियों के उल्लेखनीय भाग को अपनी मांगों की पूर्ति कराने में सफलता मिली। रूस ही नहीं, अपितु शेष संसार ने भी ऐसा मई दिवस पहले कभी नहीं देखा था। पहले विश्वयुद्ध के पूर्व वर्षों में सर्वहारा एकजुटता के इस दिवस की घटनाएं सचमुच तूफ़ानी स्वरूप की थीं।

१९१५ का पहली मई दिवस एक सर्वथा नयी स्थिति में मनाया गया। यूरोप में पहले विश्वयुद्ध की आग की लपटें धधक रही थीं। बोल्शेविक* आरम्भ से ही युद्ध के कट्टर विरोधी थे। बुलगारियाई मज़दूर सामाजिक-जनवादी पार्टी (तेस्न्याकी), सेर्बियाई सामाजिक-जनवादी पार्टी, जर्मन सामाजिक-जनवादी पार्टी के वामपंथ ने भी क्रान्तिकारी, अन्तर्राष्ट्रीयतावादी स्थिति से युद्ध का विरोध किया। परन्तु तटस्थ देशों तक में समाजवादी नेताओं की बहुसंख्या युद्धरत देशों में से इस या उसका अब भी समर्थन कर रही थी।

समाजवादी पार्टियों तथा ट्रेड यूनियनों को सर्वहारा एकजुटता के पर्व के प्रति अपना सिद्धान्तनिष्ठ रुख़ निर्धारित करना था, हालांकि घोषणाओं में वे, नियमतः, कह रही थीं कि वे अपना अन्तर्राष्ट्रीय कर्त्तव्य नहीं भूली थीं, परन्तु व्यवहार में उन्होंने सभाओं, जलूसों, यही नहीं, हड़तालों से भी अपने को अलग रखने का निर्णय किया, (हड़तालें, उनकी राय में, "युद्ध प्रयासों को मानो शिथिल करतीं")। केवल तटस्थ स्विट्ज़रलैंड में मई दिवस प्रदर्शन हुए थे।

युद्धरत देशों में से अकेला रूस अपवाद था। ज़ारशाही पुलिस के पुरालेखागारों में उन प्रतिष्ठानों की, जिनमें पहली मई, १९१५ को हड़ताल हुई थी, लंबी सूचियां तथा ज़ब्त किये हुए पर्चे संरक्षित थे। ऐसे एक पर्चे में ये भव्य शब्द लिखे हुए थे: "यदि पश्चिम यूरोपीय देशों के सर्वहाराओं ने क्रान्ति का झंडा नीचे गिरा दिया है, तो हम, रूसियों को उसे ऊपर उठाना, और आगे ले जाना है।"

पहली मई, १९१६ तक स्थिति कुछ बदल गयी। सर्वाधिक विनाशकारी युद्ध को खिंचते हुए २१ माह बीत चुके थे। तीस लाख

---

* रूसी सामाजिक-जनवादी मज़दूर पार्टी की दूसरी कांग्रेस (१९०३) में व्ला० इ० लेनिन के गिर्द एकजुट क्रान्तिकारी मार्क्सवादियों को केन्द्रीय निकायों के लिए चुनाव में बहुमत मिला और इस तरह वे "बोल्शेविक" कहलाये जाने लगे (यह शब्द "बोल्शिंस्त्वो" से बना है, जिसका अर्थ "बहुमत" है); कांग्रेस के डेलीगेटों में अवसरवादी अल्पसंख्या में रहे और तबसे वे "मेंशेविक" (यानी "अल्पसंख्य") कहलाये जाने लगे। १९१२ में प्राग में पार्टी के छठे सम्मेलन में अवसरवादियों को पार्टी से निकाल दिया गया।

व्यक्ति हताहत हो चुके थे और नर-संहार का अन्त नज़र नहीं आ रहा था। जनगण के धैर्य का बांध टूटने लगा था। उन्हें युद्धविरोधी संघर्ष में खींचने की नयी सम्भावना पैदा हो गयी थी। परन्तु दूसरे इंटरनेशनल ने किसी भी युद्धरत देश के समाजवादियों के नाराज़ होने के भय से आगामी मई दिवस के लिए घोषणापत्र जारी किया, जिसने उसका घोर पतन दर्शा दिया। तमाम देशों के समाजवादियों को, वस्तुत:, "सबको मान्य निर्णय होने तक" एक दूसरे का क़त्ल करते रहने की सलाह दी गयी थी।

परन्तु मज़दूर आन्दोलन के अन्दर युद्धविरोधी, अन्तर्राष्ट्रीयतावादी शक्तियों ने १ मई, १९१६ को पूरी ताक़त के साथ अपनी आवाज़ बुलंद की। उत्सव की पूर्ववेला में वामपंथी जर्मन सामाजिक-जनवादियों के स्पार्ताकुस ग्रुप ने बर्लिनवासियों का आह्वान किया कि वे नगर के केन्द्र में पोट्सडम चौक में विशाल प्रदर्शन में शामिल हों। जर्मन राजधानी में घेरेबन्दी की स्थिति तथा प्रदर्शन का निषेध करनेवाले एक विशेष आदेश के बावजूद लगभग दस हज़ार व्यक्तियों ने प्रदर्शन में भाग लिया। कार्ल लीब्कनेख़्त ने आवेगपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीयतावादी भाषण किया। पुलिस न तो सभा को और न जर्मन वामपंथियों के नेता के भाषण को रोकने में सफल रही।

१९१७ में मई दिवस नयी परिस्थितियों में मनाया गया। रूस में फ़रवरी बुर्जुआ-जनवादी क्रान्ति ने ज़ारशाही राज का तख़्ता उलट दिया था। मेहनतकशों को बहुत से अधिकार प्राप्त हुए, जिनमें मई दिवस स्वतंत्र रूप से मनाने का अधिकार भी था। सैनिकों तथा मज़दूरों के प्रतिनिधियों की सोवियतों ने सर्वहारा एकजुटता का पर्व मनाने की तैयारियों का काम अपने हाथों में ले लिया था। १९१७ की पहली मई पेत्रोग्राद में सर्वाधिक उत्साहपूर्वक मनायी गयी। मुख्य घटना मार्स मैदान में हुई, जहां फ़रवरी क्रान्ति के नायकों को जस्त की बनी १८० शव-पेटिकाओं में दफ़नाया गया और उनके सम्मान में तोपों से गोले दागे गये।

प्रदर्शन उसी ढंग से हुआ था, जिस ढंग से लन्दन के प्रदर्शन हुए थे। चूंकि विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधियों के लिए मंच खड़े रखने का समय नहीं मिल पाया था, इसलिए बहुत से लोगों ने ट्रकों में खड़े होकर उपस्थित जनों के समक्ष भाषण किये। सबसे ज़्यादा दिलचस्पी बोल्शेविकों के भाषणों और विशेष रूप से लेनिन के भाषण ने पैदा की। मंच के चारों ओर सटकर खड़े मज़दूरों, सैनिकों तथा नौसैनिकों

ने पहली मई के महत्व तथा रूसी क्रान्ति के कार्यभारों के बारे में लेनिन का भाषण एकाग्रचित्त होकर सुना । उसी शाम को लेनिन ने फिर भाषण किया। इस बार उनके श्रोता बारूद तैयार करनेवाले कारख़ाने के मज़दूर और चांदमारी की स्थली के सैनिक थे।

कुल मिलाकर लगभग ६ लाख व्यक्तियों ने पेत्रोग्राद के मई दिवस प्रदर्शनों में भाग लिया, जब कि पूरे देश में प्रदर्शनों में भाग लेनेवालों की संख्या कई लाख थी। उनके हाथों में झंडों पर इस तरह के नारे अंकित थे: "दुनिया के मज़दूरो, एक हो!", "साम्राज्यवादी युद्ध मुर्दाबाद!", "सारी सत्ता सोवियतों को!"।

रूस में फ़रवरी क्रान्ति ने विश्व सर्वहारा वर्ग की एकजुटता को जन्म दिया। यह उसके मई दिवस प्रदर्शनों में पूरी तरह उजागर हुई। इस तरह, इस दिन आस्ट्रिया-हंगरी के सर्वहाराओं ने साम्राज्यवादी युद्ध के विरुद्ध तथा रूसी सर्वहारा वर्ग के साथ एकजुटता के लिए संघर्ष के नारों के साथ प्रदर्शन किये। अधिकारियों तथा दक्षिणपंथी समाजवादियों के विरोध के बावजूद कल-कारख़ानों में कम ठप हो गया। आस्ट्रिया-हंगरी के राष्ट्रीय क्षेत्रों के सर्वहारा लोग विशेष रूप से सक्रिय थे। प्राग, ब्रनो, पेल्सेन, एडामोव, विट्कोवीत्सी, मारीबोर्ग, ज़ागोर्ये, ट्रीस्ट, ल्वोव, क्राकोव, आदि में प्रदर्शन हुए।...

पेरिस और फ़्रांस के अन्य औद्योगिक केन्द्रों में समाजवादी पार्टी तथा आम श्रम संघ के विरोध के बावजूद मज़दूर सड़कों पर उतर आये। उनके हाथों में झंडों पर लिखा हुआ था: "युद्ध मुर्दाबाद!", "रूसी क्रान्ति ज़िन्दाबाद!" जर्मनी में कई हड़तालें हुईं। सर्वाधिक प्रभावशाली मई दिवस प्रदर्शन स्वीडन में संगठित हुआ था, जो ६ घंटे तक जारी रहा। उसमें डेढ़ लाख व्यक्तियों ने भाग लिया। यह उस समय देश का सबसे बड़ा प्रदर्शन था। इस तरह उस वर्ष मई दिवस समारोह विजय-ध्वनि के साथ समाप्त हुए। विश्व इतिहास अपने विकास में युगान्तरकारी घड़ी के पास आ रहा था।

५. मई दिवस तथा विश्व क्रान्तिकारी प्रक्रिया

७ नवम्बर, १९१७ को मानवजाति के इतिहास में एक नूतन युग का आरम्भ हुआ। महान अक्तूबर समाजवादी क्रान्ति सामाजिक मुक्ति

की विश्वव्यापी ऐतिहासिक प्रक्रिया का प्रस्थान-बिन्दु बन गयी। उसने एक अडिग-अटल प्रक्रिया—पूंजीवाद के स्थान पर एक नयी सामाजिक-आर्थिक विरचना की प्रतिस्थापना—का सूत्रपात करके विश्व-विकास की आधारभूत प्रवृत्तियों की आम दिशा निर्धारित की।

रूस में समाजवादी क्रान्ति के प्रभाव के अन्तर्गत अधिकांश पूंजीवादी देशों में लेनिनीय क़िस्म की कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन हुआ। समकालीन कम्युनिस्ट आन्दोलन का जन्म हुआ। सफल सर्वहारा क्रान्ति ने उपनिवेशों तथा पराधीन देशों के जनगण के राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनों के विकास की रफ़्तार तेज़ करके पूरब को भी जाग्रत किया और साम्राज्यवाद की औपनिवेशिक प्रणाली के संकट की शुरूआत की।

महान अक्तूबर क्रान्ति ने मेहनतकशों के अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के नये रूपों को जन्म दिया, सर्वहारा एकजुटता के अन्तर्य को समृद्ध किया। मूलगामी ऐतिहासिक परिवर्तनों ने इस एकजुटता को इतनी गहनता तथा व्यापकता प्रदान की, जो विश्व रंगमंच पर पूंजीवाद के एकच्छत्र प्रभुत्व के समय असम्भव थीं।

अक्तूबर सशस्त्र विद्रोह की तैयारी करते समय बोल्शेविकों ने उसके अन्तर्राष्ट्रीय महत्व को पूरी तरह ध्यान में रखा। तुरन्त सत्ता पर अधिकार करने की आवश्यकता की चर्चा करते हुए लेनिन ने पार्टी तथा समस्त रूसी सर्वहाराओं का आह्वान किया कि वे अपने राष्ट्रीय कार्यभारों के समाधान को अन्तर्राष्ट्रीय कर्त्तव्यों की पूर्ति के साथ घनिष्ठ रूप में सूत्रबद्ध करें। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि केवल इसी तरह बोल्शेविक विश्व क्रान्ति और साथ ही रूसी क्रान्ति तथा मोर्चे में फंसे हज़ारों-लाखों लोगों के जीवन की रक्षा कर पायेंगे।*

नवजात सोवियत राज्य की पहली विधायी कार्रवाई शान्ति की आज्ञप्ति थी। वह युद्धरत पक्षों की सरकारों को ही नहीं, उनके जनगण को भी संबोधित थी। ब्रिटेन, फ़्रांस तथा जर्मनी के सर्वहाराओं को संबोधित करते हुए सोवियत सरकार ने अपना यह दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि अपनी अन्तर्राष्ट्रीय एकजुटता के सिद्धान्तों के प्रति वफ़ादार रहते हुए इन देशों के मज़दूर शान्ति के हेतु अपने उत्साहपूर्ण कार्यकलाप से युद्ध ख़त्म करने के काम में मदद देंगे।

---

* व्ला० इ० लेनिन, 'केन्द्रीय समिति, मास्को समिति, पेत्रोग्राद समिति और मास्को व पेत्रोग्राद की सोवियतों के बोल्शेविक सदस्यों को पत्र', १९१७।

सुसंगत अन्तर्राष्ट्रीयतावाद तुरन्त सोवियत राज्य की व्यावहारिक नीति बन गया। ३१ दिसम्बर, १९१७ को सोवियत सरकार ने फ़िनलैंड की स्वतंत्रता को मान्यता दी। जनवरी १९१८ को जन-कमिसार परिषद ने ईरान से रूसी सैनिक हटाने का कार्यक्रम मंजूर किया। २९ अगस्त, १९१८ को सरकार ने पोलिश जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार की स्वीकृति विषयक आज्ञप्ति प्रकाशित की। सोवियत रूस के इन तथा अन्य पगों ने अन्तर्राष्ट्रीय सर्वहारा एकजुटता सुदृढ़ बनाने में मदद दी, जो नये ऐतिहासिक युग में पहले मई दिवस — १९१८ में — की तैयारियों के दौरान उजागर हो गयी थी।

पश्चिमी सामाजिक-जनवादी पार्टियों के नेताओं की बहुसंख्या खुलेआम अक्तूबर क्रान्ति तथा सोवियत राज्य के विरुद्ध थी। परन्तु वे इस बात की उपेक्षा नहीं कर सके कि सर्वहारा वर्ग का बड़ा भाग भले ही सचेतन रूप में न सही रूस में सर्वहारा क्रान्ति का समर्थन कर रहा था और उनका अपना अन्धराष्ट्रवाद तथा संशोधनवाद अधिकाधिक अलोकप्रिय होते जा रहे थे। इसी कारण दूसरे इंटरनेशनल की पार्टियों के नेता १९१८ की पहली मई के समारोहों का सीधे विरोध नहीं कर पाये। अत: फ़्रांस की समाजवादी पार्टी के नेताओं ने प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी। जर्मनी तथा आस्ट्रिया-हंगरी में बड़ी हड़तालें हुईं। युद्धविरोधी स्वरूप के और रूसी क्रान्ति के समर्थन में नारे अत्यन्त लोकप्रिय रहे।

सोवियत रूस में मई दिवस समारोहों ने पूरे अन्तर्राष्ट्रीय सर्वहारा वर्ग का ध्यान आकृष्ट किया। मेंशेविकों तथा उनके कतिपय अन्य साथियों ने इस दिन को शोक-दिवस में परिणत करने, सोवियत सत्ता के विरुद्ध अपने विरोध के प्रतीकस्वरूप सड़कों पर न आने के लिए मज़दूरों के बीच मुहिम चलायी। विदेशी हस्तक्षेप, देश के अन्दर प्रतिक्रान्तिकारी कार्रवाइयां, तोड़-फोड़, तबाही-बर्बादी — इन सबने मई दिवस को तपे-मंजे लेनिनवादियों के लिए गंभीर राजनीतिक परीक्षा बना दिया था। और वे इसमें सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुए। अकेले पेत्रोग्राद में समारोही जलूस ६ घंटे से अधिक तक जारी रही। पूरे देश में प्रदर्शन नवजात सोवियत सत्ता में मेहनतकशों के विश्वास की अभिव्यक्ति थे। ऐसा था पहली मई दिवस का उत्सव, जिसे रूस के मज़दूर वर्ग ने शोषित वर्ग के रूप में नहीं, अपितु सत्ताधारी वर्ग के रूप में मनाया। इस अन्तर ने उत्सव का नया गुणगत स्वरूप निर्धारित किया।

नवजात सोवियत जनतंत्र के विरुद्ध एंटेंट तथा अन्य पूंजीवादी राज्यों के हस्तक्षेप की अवस्थाओं में नाना देशों में जनव्यापी एकजुटता आन्दोलन उभर आया, जिसका रूसी क्रान्ति के विकास पर ज़बर्दस्त प्रभाव पड़ा। लेनिन ने लिखा: "रूसी मज़दूर की नैतिक शक्ति यह थी कि यूरोप के समस्त अग्रगामी देशों के सर्वहारा वर्ग ने उसे इस संघर्ष में जो सहायता दी, उसे उसका ज्ञान था, उसे वह अनुभव करता था, उससे अवगत था।"*

लाल सेना की क़तारों में चेकों और स्लोवाकों, हंगरियाइयों तथा आस्ट्रियाइयों, सेर्बियाइयों और ख़ोरवातियों, बुल्गारियाइयों और पोलों, रूमानियाइयों और फ़िनों, जर्मनों और मंगोलियाइयों, कोरियाइयों और चीनियों ने सोवियत रूस की जातियों के प्रतिनिधियों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ाइयों में हिस्सा लिया।

रूस में क्रान्ति को उन सैकड़ों हज़ार मेहनतकशों के अन्तर्राष्ट्रीयतावाद का ठोस समर्थन प्राप्त हुआ, जिन्होंने "सोवियत रूस से दूर हटो!" नारे के साथ आन्दोलन में भाग लिया। यह आन्दोलन विशेष रूप से फ़्रांस में फैला हुआ था। आंरी बरब्यूस ने अपने देशवासियों को आवेगमय शब्दों से संबोधित किया। उन्होंने उनसे कहा कि रूसी सत्य की रक्षा करके आप मानवजाति के सत्य की रक्षा कर रहे हैं। रूसी क्रान्ति के हेतु अपने जीवन की बलि देनेवाली फ़्रांसीसी नारी जां ल्याबुर्ब, जाक सादुल, रेमों लेफ़ेव्र तथा दर्जनों फ़्रांसीसी सैनिकों तथा नौसैनिकों के, जिन्होंने फ़्रांसीसी हस्तक्षेप का विरोध किया था, नाम सोवियत जनों के स्मृति-पटल पर अमिट-अमर रहेंगे।

जब आंग्ल-फ़्रांसीसी हस्तक्षेपकारी रूस के उत्तर तथा दक्षिण से अपने सैनिक हटाने लगे, तो लेनिन ने न्यायोचित रूप से यह कहा कि यह "हमारी पहली तथा मुख्य विजय है, क्योंकि यह केवल सैनिक विजय नहीं है, यही नहीं, सैनिक विजय कदापि नहीं है, अपितु यह तो वस्तुतः मेहनतकशों की उस **अन्तर्राष्ट्रीय एकजुटता की विजय है, जिसके नाम पर हमने सारी क्रान्ति आरम्भ की थी।...**"** (शब्दों पर ज़ोर लेखक द्वारा)। पूंजीवादी देशों के सर्वहारा वर्ग ने १६१६ तथा १६२० के मई

---

* व्ला० इ० लेनिन, यातायात मज़दूरों की अखिल रूसी कांग्रेस में भाषण, १६२१।

** व्ला० इ० लेनिन, सोवियतों की सातवीं अखिल रूसी कांग्रेस में भाषण, ५ दिसम्बर, १६१६।

दिवस प्रदर्शनों में सोवियत रूस के साथ अपनी पूर्ण एकजुटता प्रकट की थी।

तीसरे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना (१६१६) सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयतावाद को सुदृढ़ बनाने के पथ पर विराट पग थी। नवजात कम्युनिस्ट पार्टियां बुर्जुआ आतंक, सामाजिक-जनवाद की सुधारवादी नीतियों के विरोध की विषम परिस्थितियों में विकसित हो रही थीं। वे केवल सुसंगत अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा पारस्परिक सहायता के आधार पर मज़बूत बन सकती थीं। उनकी आरम्भिक निर्बलता, अनुभवहीनता, कम संख्या एक ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना का तकाज़ा कर रही थीं, जो तमाम देशों के कम्युनिस्टों को ऐक्यबद्ध कर सकता। कोमिंटर्न ऐसा ही संगठन बन गया था। अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन आन्दोलन में सुसंगत वर्गगत दृष्टिकोण के विकास के लिए १६२१ में ट्रेड यूनियनों के लाल इंटरनेशनल—प्रोफ़िंटर्न—के गठन का अत्यधिक महत्व था।

इस शताब्दी के तीसरे दशक में अकालग्रस्त रूस की सहायता के लिए संगठित मुहिम सर्वहारा एकजुटता की शानदार अभिव्यक्ति थी। इस उद्देश्य के लिए अगस्त १६२१ में बर्लिन में एक विशेष समिति गठित की गयी, उसे अक्तूबर १६२४ में अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर राहत संगठन में परिणत कर दिया गया। यह कोमिंटर्न से संलग्न एक ग़ैरपार्टी सर्वहारा एकजुटता संगठन था। अपने समक्ष उसने हड़ताली मज़दूरों को, प्राकृतिक विपदाओं के समय मेहनतकशों को भौतिक तथा नैतिक सहायता देने, अन्तर्राष्ट्रीय एकजुटता के मुहिम चलाने के कार्यभार निर्दिष्ट किये। संगठन बड़ी तेज़ी से बड़ा होता गया। जहां १६२५ में उसके सदस्यों की संख्या ३० लाख से कुछ ही ज़्यादा थी, वहां १६३१ में उसकी सदस्य-संख्या बढ़कर १ करोड़ ८० लाख तक पहुंच गयी। यह सदस्यता व्यक्तिगत तथा सामूहिक, दोनों प्रकार की थी।

पश्चिमी सर्वहारा एकजुटता ने रूस के अकालग्रस्त क्षेत्रों में दसियों हज़ार व्यक्तियों के प्राण बचाये। प्राप्त भौतिक सहायता ने १०० से अधिक बाल अनाथालयों को चलाना सम्भव बनाया। लेनिन ने लिखा कि अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर वर्ग द्वारा भूख-पीड़ितों को दी गयी सहायता ने सोवियत रूस को पिछले वर्ष के अकाल के पीड़ादायी दिनों को सहन करने और उनपर क़ाबू पाने में बड़ी हद तक मदद दी।*

---

* व्ला० इ० लेनिन, 'अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर राहत संगठन के सचिव, साथी म्यून्त्सेन्बेर्ग को', २ दिसम्बर, १६२२।

सोवियत मज़दूर वर्ग भी अपना ऋण चुकाने में पीछे नहीं रहा। जब १६२३ में फ़ांसीसी और बेल्जियन सेनाओं ने रूर पर कब्ज़ा कर डाला और जर्मनी भुखमरी के शिकंजे में आ गया, तो सोवियत मेहनतकशों ने अपने जर्मन साथियों को १३,००० टन अनाज, अन्य खाद्यपदार्थ तथा पांच लाख स्वर्ण मार्क से अधिक नक़द धन भेजा। जर्मनी को अनाज भेजने के बारे में सोवियत ट्रेड यूनियनों की अपील में कहा गया था: "यद्यपि रूस अब भी ग़रीब है, यद्यपि वह अपनी अर्थव्यवस्था को बहाल करने के लिए अभी पहले ही पग उठा रहा है, फिर भी रूसी सर्वहारा वर्ग अपना यह कर्त्तव्य मानता है कि वह केवल रूस के अकाल और दुख-पीड़ा के बारे में ही न सोचे।..."

क्रान्ति के योद्धाओं के लिए सहायता-संगठन अन्तर्राष्ट्रीय सर्वहारा एकजुटता का एक दूसरा संगठन था। वह पूंजी के दमन के शिकार बननेवाले तमाम लोगों को भौतिक तथा नैतिक सहायता प्रदान करता था। वह राजनीतिक बन्दियों तथा उनके परिवारजनों को भौतिक मदद देता था, मुक़दमों के दौरान बचाव के लिए वकीलों की व्यवस्था करता था, उनकी रिहाई की मांग करता था, नाना देशों में विभिन्न राजनीतिक तथा ट्रेड यूनियन संगठनों द्वारा एक साथ जनव्यापी पैमाने पर विरोध-प्रदर्शनों का आयोजन करता था। केवल १६२५ तथा १६३४ के बीच इस संगठन ने २५१ अन्तर्राष्ट्रीय तथा १,१८५ राष्ट्रीय आन्दोलनों का आयोजन किया, जिनमें दसियों लाख लोगों ने भाग लिया।

सर्वहारा एकजुटता के ऐसे शक्तिशाली संगठनों के गठन तथा कार्यकलाप ने सम्पूर्ण विश्व में पहली मई के प्रदर्शनों पर ज़बर्दस्त छाप डाली।

इसके साथ ही इस शताब्दी के तीसरे दशक के आरम्भ में आन्दोलन ने एकसमान कठिनाइयां अनुभव कीं, जिन्होंने जुझारू मई दिवस प्रदर्शनों की राह में बाधा डाली। बहुत से देशों की सरकारों ने यदि सभी प्रतिष्ठानों में नहीं, तो कम से कम समस्त सरकारी प्रतिष्ठानों में मई दिवस के अवसर पर एक दिन की छुट्टी देकर प्रदर्शनों को प्रभावहीन बनाने का प्रयास किया। यही नहीं, बहुत से देशों में आठ घंटे के कार्य-दिवस के बारे में क़ानून पास किये गये, जबकि आठ घंटे के कार्य-दिवस की मांग लंबे अर्से तक मई दिवस प्रदर्शनों की अभिप्रेरक शक्ति बनी रही। और अन्ततः, मज़दूर आन्दोलन पार्टी तथा ट्रेड यूनियन, दोनों स्तरों पर दो प्रवृत्तियों में—सुधारवादी तथा क्रान्तिकारी प्रवृत्तियों में—बंट गया था, जिसके फलस्वरूप इन धड़ों

ने बहुधा अलग-अलग ढंग से ही नहीं, अपितु एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण ढंग से भी मई दिवस प्रदर्शन शुरू कर दिये।

जर्मनी में १६२० में केवल बड़े-बड़े नगरों में ही नहीं, अपितु उन स्थानों में भी विशाल संयुक्त प्रदर्शन हुए, जहां मई दिवस पहले कभी नहीं मनाया गया था। इसकी १६२२ में पुनरावृत्ति हुई। परन्तु १६२४ में अधिकारियों के कहने पर सामाजिक-जनवादी मई दिवस उत्सव सभा-कक्षों में मनाने के लिए सहमत हो गये। सरकारी प्रतिबन्ध के बावजूद कम्युनिस्टों ने खुली सड़कों पर प्रदर्शन किये। प्रशा, ऊपरी सिलेसिया और रूर में पुलिस के साथ टकरावों में मज़दूर मारे गये।

१६२६ का मई दिवस उस समय बहुत बड़ी त्रासदी बन गया, जब बर्लिन के पुलिस प्रेज़ीडेंट सामाजिक-जनवादी त्सेर्गीबेल ने नगर में मई दिवस समेत सभी प्रदर्शनों पर पाबन्दी लगा दी थी। कम्युनिस्ट तथा बहुत बड़ी संख्या में मज़दूर प्रतिबन्ध तोड़ते हुए सड़कों पर पहुंच गये। पुलिस ने गोली चला दी। तीन मई तक टक्करें होती रहीं, जिनमें ३३ व्यक्ति मारे गये तथा २०० से अधिक घायल हुए। इन रक्तपातपूर्ण कार्रवाइयों के कारण फ़ासिस्ट ख़तरे के विरुद्ध संघर्ष में मज़दूर वर्ग की संयुक्त कार्रवाइयां और कठिन हो गयीं।

१६२२ में इटली में फ़ासिस्टों के सत्तारूढ़ होने पर वहां तीन वर्ष तक मई दिवस प्रदर्शन जारी रहे। परन्तु हर गुज़रते वर्ष के साथ दमन-चक्र अधिकाधिक क्रूर होता गया। १६२६ के बाद देश में मई दिवस प्रदर्शन असम्भव हो गये थे।

इसके साथ ही मई दिवस के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना यह थी कि उसने एशिया तथा उत्तरी अफ़्रीका को भी अपने दायरे में लेना शुरू कर दिया था। वाम्पोआ (इंडोनेशिया) ने १६१७ में ही मई दिवस मनाया था। यह एशिया का पहला मई दिवस था। १६२० में चीन ने भी अपना पहला मई दिवस मनाया। १६२४ के प्रदर्शन में, जिसमें सुन यातसेन उपस्थित थे, दो लाख व्यक्ति शामिल हुए। जापान में मई दिवस पहली बार १६२२ में मनाया गया। १६२२ से लगातार तीन वर्षों के दौरान काहिरा और सिकंदरिया में मिस्रवासियों ने बड़े पैमाने पर मई दिवस प्रदर्शन किये। १६२३ में ईरान तथा तुर्की के मेहनतकशों ने अन्तर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस बहुत बड़े पैमाने पर मनाया। भारत में पहले मई दिवस प्रदर्शन १६२७ में बंबई में और फ़िलीपिन में १६३० में हुए। इस तरह सर्वहारा का एकजुटता दिवस धीरे-धीरे अधिकाधिक देशों में मनाया जाने लगा।

जर्मनी में १६२६-१६३३ के आर्थिक संकट की अवस्थाओं में इजारेदार पूंजी फ़ासिज़्म पर अपनी आशाएं अधिकाधिक केन्द्रित करने लगी थी। ३० जनवरी, १६३३ में फ़ासिज़्म के विजयी हो जाने के बाद एक क़ानून पास कर मई दिवस को "राष्ट्रीय श्रम का उत्सव", "जर्मन जनता का उत्सव" घोषित किया गया, उसे "श्रम का सम्मान, मज़दूरों का आदर हो!" के झंडे के नीचे मनाया जाना था। फ़ासिस्टों का इससे क्या आशय था, यह जल्द स्पष्ट हो गया, हिटलर के प्रति ट्रेड यूनियन नेताओं के सचमुच मेल-मिलापभरे रुख़ के बावजूद २ मई १६३३ को नाज़ी सहायक पुलिस के सैनिकों ने ट्रेड यूनियन सदरमुकाम पर छापा मारा। वहां कार्यकर्त्ताओं को गिरफ़्तार कर लिया गया और ट्रेड यूनियनों की कई करोड़ की संपत्ति ज़ब्त कर ली गयी। राबर्ट ले नामक एक नाज़ी नेता ने कहा कि ट्रेड यूनियन नेता हिटलर के सामने जितना चाहें, उतना पाखंड कर सकते हैं, परन्तु उन्हें जेल के सीख़चों के पीछे बन्द रखना कहीं ज़्यादा सुरक्षित होगा।

नाज़ियों की इस और इस तरह की अन्य कार्रवाइयों के उत्तर में संसार में भिन्न-भिन्न राजनीतिक आस्थाओंवाले मेहनतकशों का संघर्ष तथा फ़ासिज़्म के विरुद्ध संयुक्त आन्दोलन विकसित हो गया। १६३५ में कोमिंटर्न की सातवीं कांग्रेस ने युद्ध के ख़तरे तथा फ़ासिज़्म के विरुद्ध संघर्ष के अनुभव का पूरी तरह विश्लेषण किया। उसने मज़दूर आन्दोलन की एकता की प्रक्रिया तेज़ करने के लिए कम्युनिस्टों की दूरगामी नीति तैयार की। उसमें मई दिवस प्रदर्शनों को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी थी।

कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की कार्य-समिति की मई दिवस अपील (१६३६) में कहा गया था: "संसार को बहुत भारी ख़तरा है... फ़ासिस्ट शासक मानवजाति को किसी भी क्षण एक नये विश्वयुद्ध की अकल्पनीय विपदा के मुंह में धकेल सकते हैं... युद्ध भड़कानेवालों का रास्ता रोकने में अभी बहुत देरी नहीं हुई है... शान्ति बनाये रखने के लिए जनगण के व्यापकतम मोर्चे का गठन इस समय सर्वहाराओं तथा शान्ति के अन्य मित्रों का केन्द्रीय कार्यभार है।..."

१८ जुलाई, १६३६ को स्पेन में फ़ासिस्ट विद्रोह के आरम्भ की ख़बर से संसार को ज़बर्दस्त धक्का लगा। इटली तथा जर्मनी के फ़ासिस्ट फ़ौरन फ़्रांको की सहायता के लिए पहुंचे। इन परिस्थितियों में स्पेनी जनतंत्र के साथ एकजुटता के आन्दोलन ने इतना बड़ा आकार ग्रहण

किया, जितना "सोवियत रूस से दूर हटो!" आन्दोलन के बाद देखने में नहीं आया था।

यह बात मई दिवस प्रदर्शनों में भी प्रतिबिम्बित हुई। फ़ासिज़्म तथा युद्ध के विरुद्ध संघर्ष के नारे अब स्पेन की घटनाओं के साथ अधिकाधिक जुड़ने लगे। इस तरह, पोलैंड में १९३७ के मई दिवस प्रदर्शनों में एक लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया, जो मज़दूर आन्दोलन की मुख्य धाराओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। यहां लगाये गये नारों में सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय वे थे, जो स्पेनी जनतंत्र के समर्थन में लगाये गये थे।

दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान मई दिवस कहीं भी पहले जितने बड़े पैमाने पर नहीं मनाया जा सका। हिटलर द्वारा अधिकृत देशों में कठपुतली सरकारों ने नाज़ी जर्मनी की नक़ल करते हुए पहली मई को श्रम तथा पूंजी के बीच मेल-मिलाप के सरकारी उत्सव का स्वरूप देने का प्रयास किया। परन्तु मई दिवस का किसी भी प्रकार का विकृतीकरण, घोर से घोर दमन भी मेहनतकशों का मनोबल नहीं तोड़ सका। मज़दूर संगठनों के भूमिगत अख़बार विशेष मई दिवस अंक निकालते रहे। मई दिवस सर्वत्र, बन्दी शिविरों तथा जेलों तक में ग़ैरक़ानूनी ढंग से मनाया जाता था।

कम्युनिस्टों ने फ़ासिस्ट विरोधी संघर्ष में विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वे अथक रूप से समझाते रहे कि पूरी मानवजाति के भाग्य का सोवियत-जर्मन मोर्चे पर निर्णय हो रहा है, उन्होंने प्रतिरोध आन्दोलन के संगठन में भाग लिया, अन्तर्राष्ट्रीय सर्वहारा एकजुटता के महत्व तथा समस्त जनगण के सच्चे राष्ट्रीय हितों के साथ उसकी एकरूपता पर सफलतापूर्वक प्रकाश डाला।

एशिया के पराधीन देशों तथा उपनिवेशों के जनगण ने भी जर्मन फ़ासिज़्म और जापानी सैन्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में अपना योग दिया, जिन्होंने जापानी आधिपत्यकारियों के विरुद्ध अडिग संघर्ष (बहुधा कम्युनिस्टों के नेतृत्व में) चलाया।

मुक्ति-युद्ध में विजयी जनगण ने १९४५ में व्यापक मई दिवस प्रदर्शनों में अपना हर्षोल्लास प्रकट किया, जब जर्मनी का आत्मसमर्पण चन्द ही दिन बाद और जापान का चन्द ही माह बाद होनेवाला था। उदाहरण के लिए, २५ अप्रैल को स्वतंत्र किये गये मिलान नगर के दुओमो चौक में लाखों लोग १ मई को समारोह मनाने के लिए जमा हुए, जिन्होंने बीस वर्ष तक यह उत्सव नहीं मनाया था। और यह सब उस

समय हुआ, जब उन स्थानों में, जो नगर से बहुत दूर नहीं थे, लड़ाई अभी चल ही रही थी।

पहले यूरोप तथा एशिया के और फिर अमरीकी महाद्वीप के कई देशों में शोषकों की सत्ता उलट दिये जाने के फलस्वरूप समाजवाद, जो पहले सोवियत संघ में यथार्थ रूप ग्रहण कर चुका था, विश्व प्रणाली बन गया। विश्व इतिहास के पूरे प्रवाह ने सिद्ध किया कि रूस में अक्तूबर क्रान्ति रूस के राष्ट्रीय विकास में कोई सांयोगिक घटना नहीं थी। जनगण का राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन द्रुत गति से बढ़ता जा रहा था। युद्धोत्तर काल में उनमें से कई अपने को उपनिवेशवाद की बेड़ियों से स्वतंत्र करने में सफल हो गये थे। नाना जनवादी संगठन—ट्रेड यूनियनें, युद्धविरोधी, नारी तथा युवा संगठन—अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकट हुए।

१९४६ में यूरोप में नाज़ी आधिपत्य तथा प्रतिक्रियावादी शासनों से स्वतंत्र नाना देशों ने मई दिवस मनाया। पोलैंड, बुल्गारिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, रूमानिया, युगोस्लाविया, अल्बानिया में विशाल मई दिवस प्रदर्शन हुए, जिनमें हज़ारों-हजार लोग शामिल हुए। पूंजीवादी देशों में भी बहुत बड़े प्रदर्शन हुए। अकेले पेरिस के उपनगरों में हुए एक प्रदर्शन में लगभग पन्द्रह लाख व्यक्ति शामिल हुए।

परन्तु जब साम्राज्यवादी राज्यों ने "शीतयुद्ध" छेड़ दिया, तो पूंजीवादी विश्व में मई दिवस प्रदर्शन आयोजित करने की अवस्थाएं बहुत तीक्ष्णतापूर्वक परिवर्तित होने लगीं। बहुत से देशों में अधिकतर औपनिवेशिक तथा पराधीन देशों में (चीन, ईरान, अफ़्रीकी देश) मई दिवस प्रदर्शनों पर तरह-तरह के बहानों की आड़ में शीघ्र ही पाबन्दी लगा दी गयी।

इटली में स्थिति इतनी बिगड़ गयी थी कि १ मई, १९४७ को सिसिलियन माफ़िया ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दीं। १९५० में ब्रिटिश सरकार ने ऐलान किया कि लन्दन तथा उसके आसपास पहली मई के किसी भी तरह के समारोहों को ग़ैरक़ानूनी माना जायेगा। फ़्रांस में भी १९५५ से १९६८ तक मई दिवस प्रदर्शनों पर ऐसी ही पाबन्दी पूरे देश में लागू रही। अमरीका में भी १९५३ में मई दिवस ग़ैरक़ानूनी घोषित कर दिया गया।

कुल मिलाकर पांचवें तथा छठे दशकों में मई दिवस समारोह वास्तविक विश्वव्यापी स्वरूप ग्रहण नहीं कर सके। एक पूरा महाद्वीप—अफ़्रीका—मई दिवस समारोहों के क्षेत्र के बाहर रहा। पहले

की भांति वह उपनिवेशवादियों के शिकंजे में था। कुछ देशों में मई दिवस प्रदर्शन नियमित रूप में नहीं होते थे। विभिन्न महाद्वीपों, देशों तथा राष्ट्रों में मेहनतकशों का सच्चा अन्तर्राष्ट्रीयतावाद समस्त जनगण की स्वाधीनता, समानता के बिना अकल्पनीय है। "राष्ट्रीय स्वतंत्रता," एंगेल्स ने ज़ोर देकर लिखा, "सब तरह के अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की आधारशिला है।"* मई दिवस सातवें दशक में अफ़्रीका में उपनिवेशवाद के अन्तिम गढ़ के ढह जाने पर ही वास्तविक रूप में विश्वव्यापी समारोह बना।

* फ़्रे० एंगेल्स, कार्ल काउत्स्की को पत्र, ७ फ़रवरी, १८८२।

अध्याय २

वर्तमान काल में मई दिवस

१. मज़दूर वर्ग का शक्तिशाली अस्त्र

एकजुटता मज़दूर वर्ग में सदैव अन्तर्निहित रही है। परन्तु सर्वहारा एकजुटता की भूमिका तथा महत्व मज़दूर आन्दोलन के विकास की हर नयी मंज़िल में निरन्तर बढ़ते गये।

अक्तूबर क्रान्ति से पहले सर्वहारा वर्ग की एकजुटता पूंजी पर सीधे प्रहार करने की उसकी तैयारी का विद्यालय रही है। वह राष्ट्रीय तथा साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर मज़दूरों की पारस्परिक सहायता तथा समर्थन में व्यक्त होती रही। अक्तूबर क्रान्ति की विजय के उपरान्त सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयतावाद ने नया गुण ग्रहण कर लिया: वह राजकीय शक्ति बन गयी। पूंजीवादी देशों में मज़दूर आन्दोलन अब केवल अपने ही राष्ट्रीय दस्तों पर नहीं, अपितु प्रथम सोवियत राज्य पर भी भरोसा कर सकता था। अपनी बारी में नवजात सोवियत राज्य को अन्य देशों के मज़दूर वर्ग का समर्थन प्राप्त हो रहा था। अक्तूबर क्रान्ति के प्रभाव में राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन का संवर्द्धन इस नये नारे में प्रतिबिम्बित हुआ: "समस्त देशों के सर्वहाराओ तथा उत्पीड़ित जनगण, एक हो!" मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टियों तथा ट्रेड यूनियनों का गठन हुआ, जो सुसंगत वर्ग-नीति और सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के सिद्धान्तों का पालन कर रही थीं।

यूरोप, एशिया और अमरीका के कई देशों में समाजवाद की विजय ने सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयतावाद की भूमिका और महत्व में और वृद्धि कर दी। विश्व प्रणाली बन चुकने पर समाजवाद ने एक नयी, अपूर्व क़िस्म के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को जन्म दिया, जो समाजवादी राज्यों के बीच समाजवादी अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के आधार पर विकसित होते हैं। समाजवादी अन्तर्राष्ट्रीयतावाद की अपनी ठोस नींव है। उसमें ये

शामिल हैं: एकसमान सामाजिक-आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था; मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारधारा; वर्ग-एकजुटता; मैत्री, सहयोग तथा नये समाज के निर्माण तथा उसकी रक्षा के कार्यभारों के समाधान में पारस्परिक सहायता; शान्ति, अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा तथा सामाजिक प्रगति के लिए संघर्ष; प्रत्येक राज्य के लिए समानाधिकार तथा उसकी स्वतंत्रता तथा प्रभुसत्ता का आदर। इस समय न केवल एक समाजवादी राज्य, अपितु पूरी विश्व समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी देशों तथा राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनों का स्वाभाविक साथी बन गयी है।

अन्तर्राष्ट्रीय एकजुटता मौजूदा मंज़िल में उत्तरोत्तर ऊंचे स्तर पर पहुंचती जा रही है, नयी व्यापकता प्राप्त करती जा रही है। सामाजिक विकास की सभी प्रमुख चालक शक्तियों — विश्व समाजवाद, मज़दूर और कम्युनिस्ट आन्दोलन, नवस्वतंत्र राज्यों के जनगण, व्यापक जनवादी आन्दोलन — की अन्योन्यक्रिया साम्राज्यवाद, आक्रामकता तथा उत्पीड़न की उसकी नीति के विरुद्ध, शान्ति, जनवाद तथा सामाजिक प्रगति के हेतु संघर्ष में शक्तिशाली बनती जा रही है। मेहनतकशों की अन्तर्राष्ट्रीय एकजुटता को कमज़ोर बनाने का प्रयत्न करते हुए साम्राज्यवाद राष्ट्रीय अहंवाद, अन्धराष्ट्रवाद और नस्लवाद की तथा दूसरे जनगण के अधिकारों तथा हितों, उनकी राष्ट्रीय सांस्कृतिक-ऐतिहासिक धरोहर के प्रति घृणा की आग भड़काता और उकसाता है।

परन्तु ये तिकड़में विश्व घटना-प्रवाह के अन्तर्विरोधों की मौजूदा प्रणाली की क्रियाशीलता को नहीं मिटा सकतीं, जो पूंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण के युग के रूप में हमारे युग की अन्तर्वस्तु को पूर्ण रूप में प्रतिबिम्बित करती है। फलस्वरूप दो सामाजिक-आर्थिक विरचनाओं के राज्यों के बीच, समाजवाद तथा पूंजीवाद के बीच अन्तर्विरोध इस प्रणाली में, उनकी अन्योन्यक्रिया तथा विरोधों में निर्णायक, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वे नाना देशों में समाजवादी क्रान्ति की विजय के बाद और शेष संसार में पूंजीवादी व्यवस्था के क़ायम रहते हुए श्रम तथा पूंजी के बीच अन्तर्विरोधों पर क़ाबू पाने के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में उत्पन्न हुए।

विश्व समाजवाद का अस्तित्व तथा नीति वर्ग-संघर्ष को बढ़ाने में मदद देते हुए, पूंजी के गढ़ों में समाजवादी कायापलटों को मज़दूर आन्दोलन के लिए अधिक आकर्षक बनाते हुए पूंजीवाद में निहित अन्तर्विरोध के — श्रम तथा पूंजी के बीच अन्तर्विरोध के — विकास पर गहरी छाप डालते हैं।

परन्तु पूंजीवादी विश्व के अन्य आन्तरिक विरोध भी सर्वहारा एकजुटता के महत्व को निरन्तर बढ़ाते रहते हैं, जो मेहनतकशों का शक्तिशाली और जांचा-परखा अस्त्र है। पूंजीवादी उत्पादन के अन्तर्राष्ट्रीयकरण की रफ़्तार तेज़ हुई है। उसके साथ-साथ अनियमित आर्थिक संवृद्धि होती है, जिसमें साम्राज्यवाद के अन्तर्गत देशों के असमान आर्थिक तथा राजनीतिक विकास का नियम उजागर होता है। यह समकालीन साम्राज्यवाद के तीन बुनियादी केन्द्रों—अमरीका, जापान तथा पश्चिमी यूरोप—के पारस्परिक सम्बन्धों में प्रतिबिम्बित होता है। अभी हाल में अमरीका आर्थिक, वित्तीय तथा टेक्नालाजिकल मामलों में अपने साझीदारों से आगे था। परन्तु अब वह नवीनतम तकनीकी साज़सामान के उत्पादन के क्षेत्र तक में अपनी यह जगह खो बैठा है।

अमरीका पश्चिमी यूरोप तथा जापान के बुर्जुआ जनों से अक्सर आपसी संघर्ष शिथिल करने की अपील करता है। परन्तु ऐसी अपीलों का पाखंड यह तथ्य विश्वसनीय ढंग से प्रदर्शित करता है कि वाशिंगटन के तत्त्वावधान में होनेवाले समझौते आम तौर पर अमरीकी पक्ष के लिए लाभप्रद होते हैं। इन परिस्थितियों में विकसित पूंजीवादी देशों की आबादी की व्यापक श्रेणियों के सामने अपरिहार्य रूप से यह प्रश्न उठ खड़ा होता है: क्या उनके हित अमरीका को पूंजीवादी विश्व का राजनीतिक नेता स्वीकार करने से मेल खाते हैं?

दूसरी ओर, साम्राज्यवादी राज्यों के अन्तर्विरोधों पर भी विश्व समाजवाद का, समस्त प्रगतिशील शक्तियों के संघर्ष का प्रभाव पड़ रहा है। बड़ी-बड़ी इजारेदारियां समकालीन सामाजिक विकास के अन्तर्राष्ट्रीयकरण के विभिन्न पहलुओं को अपने राजनीतिक निकायों की गतिविधियों के सुदृढ़ीकरण तथा समन्वयन के लिए उपयोग में लाती हैं। हाल के वर्षों की घटनाएं बताती हैं: किसी भी सम्बद्ध पूंजीवादी देश में बुर्जुआ वर्ग जितना कमज़ोर होता जाता है, उतने ही ज़ोरदार ढंग से वह अपने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का सहारा लेने का प्रयास करता है। इस या उस देश में क्रान्तिकारी अथवा महज़ गहन जनवादी स्वरूप के महत्वपूर्ण परिवर्तनों की सूरत में पूंजी का अन्तर्राष्ट्रीय संघ तुरन्त ही उसके मामलों में विभिन्न रूपों में निर्लज्जतापूर्वक हस्तक्षेप करता है।

प्रमुख साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच गहरे होते जा रहे अन्तर्विरोधों के बावजूद वे अब भी विधिवत रूप से संयुक्त राजनीतिक निर्णय करते हैं, उदाहरण के लिए, पश्चिमी सैनिक-राजनीतिक गुटों,

सर्वोपरि नाटो के ढांचे के अन्तर्गत। पिछले चन्द वर्षों में इस सम्बन्ध में "बड़े सात" राज्यों—अमरीका, जापान, जर्मन संघात्मक गणराज्य, फ़्रांस, ब्रिटेन, कनाडा तथा इटली—के प्रमुखों की बैठकों ने विशेष महत्व ग्रहण कर लिया है, जिनमें वस्तुत: पूंजीवादी देशों की अन्तर्राष्ट्रीय नीति की एकसमान लाइन तैयार की जाती है। यह सब विकसित पूंजीवादी देशों के मेहनतकशों के हितों का मेल निर्धारित करता है और नवस्वतंत्र राज्यों के जनगण के साथ उनकी सक्रिय एकजुटता और साथ ही सहयोग को आवश्यक बनाता है। यह आवश्यकता इस तथ्य से भी जन्म लेती है कि ट्रांसनेशनल कार्पोरेशन अक्सर दोनों को ही लूटते हैं। पिछले चन्द दशकों में ट्रांसनेशनल कार्पोरेशनों तथा अलग-अलग राष्ट्रों के प्रभुसत्तासम्पन्न सामाजिक-राजनीतिक हितों के बीच अन्तर्विरोधों की एक नयी गुत्थी पैदा हुई है। ट्रांसनेशनल कार्पोरेशन विकासमान देशों और विकसित पूंजीवादी देशों, दोनों की आर्थिक, यही नहीं, राजनीतिक स्वतंत्रता तक को संकुचित करते हैं।

ट्रांसनेशनल कार्पोरेशनों का छठे दशक के अन्त से विशेष रूप से व्यापक विकास हुआ है। विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के पैमाने पर उत्पादन की पूरी की पूरी शाखाएं तथा क्षेत्र इस समय उनकी परिधि में आ चुके हैं। इस दशक के आरम्भ में पूंजीवादी विश्व में औद्योगिक उत्पादन का परिमाण एक-तिहाई से अधिक, सम्पूर्ण विदेश व्यापार का आधे से अधिक, नये उपस्करों तथा टेक्नालाजी के पेटेंटों का लगभग ८० प्रतिशत उनके हिस्से में था। वे राजकीय-इजारेदारी विनियमों का सक्रिय रूप से उपयोग करते हैं, जब वे उनके लिए लाभप्रद होते हैं, और उस समय इनकी उपेक्षा करते हैं, जब वे बुर्जुआ सरकारों के कार्यकलाप में अपने मुनाफ़ों के लिए लेशमात्र ख़तरा देखते हैं।

ट्रांसनेशनल कार्पोरेशनों की गतिविधियां पूंजीवादी राज्यों को आर्थिक विकास पर प्रभाव डालने के उन अल्प प्रभावी उत्तोलकों तक से वंचित कर देती हैं, जिन्हें इस्तेमाल करने की सम्भावना पहले उनके पास होती थी। इसलिए ट्रांसनेशनल कार्पोरेशनों के बढ़ते प्रभाव का अर्थ है नये आर्थिक धक्के, संकट, उत्पादन की बढ़ती अराजकता, जो मेहनतकशों के कन्धों पर भारी बोझ हैं। ट्रांसनेशनल कार्पोरेशनों के विरुद्ध कारगर संघर्ष केवल अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर ही सम्भव है। इसीलिए लेनिन के ये शब्द आज विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं: "केवल

हर वहशीपनभरे तथा मूर्खतापूर्ण पूर्वाग्रह का त्याग करके, केवल तमाम राष्ट्रों के मज़दूरों को एक संघ में ऐक्यबद्ध करके ही मज़दूर वर्ग एक ताक़त बन सकता है, पूंजी को मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। ...''*

साम्राज्यवाद तथा विकासमान देशों और जनगण के बीच नये, संजटिल तथा परिवर्तनशील अन्तर्विरोधों ने जन्म लिया। समाजवाद तथा पूंजीवाद के बीच संघर्ष ने उपनिवेशस्वामी देशों तथा उपनिवेशों के बीच अन्तर्विरोधों के ऐतिहासिक विकास पर भी गहरी छाप डाली, जिसके आधार पर राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन काफ़ी हद तक अक्तूबर क्रान्ति और दूसरे विश्वयुद्ध के बाद विश्व समाजवाद के प्रभावान्तर्गत जन्मा और विकसित होता जा रहा है। भूतपूर्व उपनिवेशों और अर्द्ध-उपनिवेशों की स्वतंत्रता पूंजीवादी प्रणाली पर ज़बर्दस्त राजनीतिक और विचारधारात्मक प्रहार थी। फलस्वरूप एक ओर, साम्राज्यवाद और नव-उपनिवेशवाद की शक्तियों और दूसरी ओर, राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष का पथ अपनानेवाले और राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त कर चुके देशों के बीच अन्तर्विरोधों का आविर्भाव हुआ।

मौजूदा हालत में राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन अभी इस स्थिति में नहीं है कि वह अपनी निजी ताक़त के आधार पर इन अन्तर्विरोधों का समाधान कर सके। केवल अन्य साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों—समाजवादी देशों के जनगण, पूंजीवादी जगत के मज़दूरों तथा व्यापक जनवादी आन्दोलनों—के साथ संघबद्ध होकर इन ध्येयों की सफलतापूर्वक पूर्ति हो सकती है।

भूमंडलीय पैमाने के अन्तर्विरोधों का, जो विद्यमान सभ्यता की ठीक नींव को ही स्पर्श करते हैं, समकालीन विश्व घटना-प्रवाह के आधारभूत अन्तर्विरोधों के समुच्चय में महत्वपूर्ण स्थान है। यहां तात्पर्य पर्यावरण, वायु तथा महासागरों के प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों के कम होते जाने की प्रक्रिया तथा अन्य भूमंडलीय समस्याओं से है, जो पिछले दशकों में अत्यन्त तीक्ष्ण बन गयी हैं। पूरी मानवजाति की इन समस्याओं को एक राज्य या राज्यों के ग्रुप की शक्तियों से हल नहीं किया जा सकता। विश्वव्यापी पैमाने पर देशों तथा जनगण के संयुक्त प्रयास, सहयोग की आवश्यकता है, जो सुगमतापूर्वक सम्पन्न किये जा सकते हैं, अगर इस समय हथियारबन्दी पर ताक़त तथा साधनों की बर्बादी बन्द कर दी जाये।

---

* व्ला० इ० लेनिन, 'यहूदी स्कूलों का राष्ट्रीयकरण', १९१३।

पूंजीवादी प्रणाली, जिसका लक्ष्य अधिकतम मुनाफ़ों की प्राप्ति है, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम दोहन करके पर्यावरण को और बर्बाद कर रही है। अपेक्षाकृत सीमित क्षेत्रों तक में प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा अयुक्तियुक्त उपयोग ऐसे नकारात्मक परिणामों को जन्म दे सकता है, जिनके बारे में पहले से कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। यह चीज़ और इसके साथ साम्राज्यवाद द्वारा छेड़ी गयी हथियारों की दौड़ भूमंडलीय समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष में भाग लेनेवालों को इस निष्कर्ष पर पहुंचाती हैं कि गंभीर सामाजिक परिवर्तन आवश्यक हैं, जिनके बिना जटिल तथा मानवजाति के भविष्य को ख़तरे में डालनेवाली समस्याओं का समाधान नितान्त असम्भव है।

अत:, समकालीन विश्व घटनाप्रवाह के मुख्य अन्तर्विरोधों के घनिष्ठ पारस्परिक सम्बन्ध, उनके एक दूसरे पर पड़नेवाले प्रभाव से मेहनतकशों, समस्त जनवादी शक्तियों के हितों का वह साम्य निर्धारित होता है, जो साम्राज्यवाद विरोधी एकजुटता के विकास की नींव है।

हमारे युग का अभिलाक्षणिक गुण है ग़ैरसमाजवादी जगत में व्यापक जनवादी आन्दोलनों का उभार। पूंजीवादी देशों में इजारेदारियों तथा आबादी की विशाल बहुसंख्या के बीच वैरभाव गहन होते जा रहे हैं। इजारेदारियों के आधिपत्य, सत्ताधारी वर्गों की प्रतिक्रियावादी नीति के विरुद्ध संघर्ष में बुद्धिजीवी, दफ़्तर-कर्मचारी, कृषक, शहरी टुटपुंजिया वर्ग और अल्पसंख्यक जातियों के प्रतिनिधि, महिला संगठन, नौजवान तथा छात्र अधिकाधिक सक्रियतापूर्वक शामिल हो रहे हैं। विभिन्न राजनीतिक रुझानों के लोग समाज के सैन्यीकरण, युद्ध तथा आक्रामकता की नीति, नस्ली तथा जातीय भेदभाव, महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन, नौजवानों की बिगड़ती स्थिति, भ्रष्टाचार, इजारेदारियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की लूट तथा पर्यावरण के प्रदूषण का अन्त करने की मांग कर रहे हैं। इसलिए सर्वहारा एकजुटता का सामाजिक-राजनीतिक आधार भी अपरिहार्य रूप से फैल रहा है, जो समस्त जनवादी शक्तियों की ऐक्यबद्धता की नींव के रूप में अपने को प्रकट करता है।

ध्यान रहे, इसी आधार पर यह कहा जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीयतावाद की अब विशुद्ध "सर्वहारा" अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के रूप में व्याख्या नहीं की जा सकती। उसका अर्थ कहीं अधिक व्यापक होना आवश्यक है। परन्तु सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयतावाद की अवधारणा की उत्पत्ति के समय मार्क्स

तथा एंगेल्स का अभिप्राय कदापि यह नहीं था कि सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयतावाद केवल मज़दूर वर्ग में अन्तर्निहित हो सकता है। मार्क्स ने अपने समय की घटनाओं का विश्लेषण करते समय लिखा था : "मज़दूर तब तक एक भी पग आगे नहीं बढ़ा सकते थे, बुर्जुआ व्यवस्था का बाल भी बांका नहीं कर सकते थे, जब तक क्रान्ति का प्रवाह सर्वहारा वर्ग तथा बुर्जुआ वर्ग के बीच खड़े राष्ट्र के जनसमुदाय, किसानों और टुटपुंजियों को इस व्यवस्था के विरुद्ध, पूंजी के प्रभुत्व के विरुद्ध उठ खड़ा न करता और उन्हें अपने अग्रगामी योद्धाओं के रूप में सर्वहारा के साथ जोड़ न देता।" *

सर्वहारा एकजुटता के क्षेत्र का मौजूदा विस्तार काफ़ी हद तक मेहनतकशों की राष्ट्रीय तथा सामाजिक मुक्ति के लिए संघर्ष में मज़दूर आन्दोलन की सफलताओं का फल है। दूसरी ओर, ग़ैरसर्वहारा जनवादी शक्तियों के उपनिवेशवाद विरोधी, पूंजीवाद विरोधी रुझानों का कारण यह है कि वे मज़दूर वर्ग की विचारधारा तथा नीति को सक्रियतापूर्वक अंगीकार करती हैं।

यह तथ्य कि सर्वथा भिन्न-भिन्न सामाजिक श्रेणियों-ग्रुपों के प्रतिनिधि बहुत अक्सर सर्वहारा एकजुटता आन्दोलनों में भाग ले रहे हैं, सिद्ध करता है कि सर्वहारा और उनका हरावल अपने कार्यक्रम के आधार पर समस्त साम्राज्यवाद विरोधी, युद्धविरोधी, जनवादी शक्तियों को ऐक्यबद्ध करने के पथ पर अग्रसर होते जा रहे हैं, भले ही इसे उनके अलग-अलग प्रतिनिधि अनुभव न करते हों। प्रतिक्रियावादी साम्राज्यवादी क्षेत्रों की नीति के विरुद्ध लक्षित व्यापक जनवादी आन्दोलन शान्ति तथा सामाजिक प्रगति के संघर्ष की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय एकजुटता अपने आप अथवा स्वत:स्फूर्त ढंग से नहीं बढ़ सकती। इसे मूर्त रूप देने के पूर्वाधार केवल राष्ट्रवाद, अन्धराष्ट्रवाद, नस्लवाद के विरुद्ध संघर्ष में, कम्युनिस्ट तथा मज़दूर पार्टियों, सुसंगत रूप से वर्गोन्मुख ट्रेड यूनियनों तथा अन्य प्रगतिशील पार्टियों के व्यावहारिक कार्यकलाप में निहित हैं। एकता अपने आप नहीं आती, उसे तो अडिग, सतत प्रयासों से हासिल करना पड़ता है।

मज़दूर वर्ग हमारे युग का सदैव प्रमुख क्रान्तिकारी वर्ग रहा है और अब भी है। पूंजी की दुनिया में वह ऐसी प्रमुख शक्ति है, जो शोषक वर्गों

---

* का० मार्क्स, 'फ़्रांस में वर्ग-संघर्ष', १८५०।

का तख़्ता उलटने और नये समाज का निर्माण करने का प्रयास करने के लिए संघर्षरत है। उसकी सामाजिक भूमिका भी निरन्तर बढ़ती जा रही है। उत्पादन में नयी वैज्ञानिक उपलब्धियों का समावेश उसकी कतारों में उच्च योग्यताप्राप्त कर्मियों से अनुपूर्ति करता जा रहा है। वर्गगत लड़ाइयों में मज़दूर वर्ग और अधिक पुख़्ता बनता जा रहा है तथा पूंजीवाद के विरुद्ध उसके आर्थिक, राजनीतिक तथा विचारधारात्मक संघर्ष का पैमाना फैलता जा रहा है, इसके रूप विविधतापूर्ण बनते जा रहे हैं तथा उसकी अन्तर्वस्तु समृद्ध होती जा रही है। मज़दूर वर्ग की क्रान्तिकारी पार्टियां, जो अपने देश के राष्ट्रीय हितों के सच्चे पैरवीकार तथा अडिग रक्षक हैं, मेहनतकश जनता के अधिकारों तथा आकांक्षाओं के पक्ष में खड़ी होती हैं। वे बुर्जुआ समाज की संकटपूर्ण स्थिति से बाहर निकलने के तरीक़े लक्षित करती हैं, शोषक व्यवस्था का वास्तविक विकल्प पेश करती हैं, वर्तमान काल के मूल प्रश्नों का आशावादिता से परिपूर्ण उत्तर देती हैं।

कम्युनिस्ट बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि समाजवादी ध्येयों की पूर्ति का पथ आम जनवादी कार्यभारों के अनिवार्य समाधान के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। वे सर्वहारा एकजुटता को जनवाद और अन्य आम मानवतावादी प्रक्रियाओं से कभी अलग-थलग नहीं करते। शून्य में उपदेश देना मार्क्सवाद-लेनिनवाद के लिए विजातीय वस्तु है। कम्युनिस्ट आन्दोलन आम जनवादी एकजुटता की फलप्रदता तथा व्यावहारिक औचित्य का बहुत उच्च मूल्यांकन करता है। परन्तु विभिन्न वर्गगत मूलवाले और विश्वदृष्टिकोणवाले व्यापक जनसाधारण के बीच अन्तर्राष्ट्रीयतावादी चेतना की संवृद्धि सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयतावाद तथा सर्वहारा एकजुटता के महत्व को कदापि नहीं घटाती। ये अवधारणाएं उसकी परम्पराओं के प्रति मज़दूर वर्ग और उसके हरावल की वफ़ादारी प्रतिबिम्बित करती हैं। इन अवधारणाओं को नकारना उतना ही अविवेकपूर्ण होगा, जितना कि उदाहरण के लिए, प्रख्यात नारे—"दुनिया के मज़दूरो, एक हो!"—को इस आधार पर नकारना कि समाजवादी देशों में सर्वहारा वर्ग नहीं है, अपितु मज़दूर वर्ग, नये समाज की अग्रणी सामाजिक तथा राजनीतिक शक्ति है।

यही बात मई दिवस उत्सव मनाने के बारे में कही जा सकती है। वह वैसा ही बना रहेगा, जैसा कि पहले था—मेहनतकशों की अन्तर्राष्ट्रीय एकजुटता का उत्सव, हालांकि वह उन देशों में भी मनाया जाता है, जहां मज़दूर वर्ग अब भी अल्पसंख्य है और प्रदर्शनों में सर्वथा

भिन्न-भिन्न सामाजिक श्रेणियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। लेनिन ने मई दिवस के विचारों तथा मांगों का "जनता की उन तमाम श्रेणियों के बीच, जो मज़दूरों के सम्पर्क में आती हैं..."* प्रसार करने की आवश्यकता की चर्चा की थी। उनके इस आह्वान में सर्वहारा एकजुटता की भूमिका की समझ प्रतिबिम्बित होती है, जो सबसे अग्रगामी तथा क्रान्तिकारी वर्ग के हित व्यक्त करती है और साथ ही समस्त मेहनतकशों की जीवन्त आवश्यकताओं से मेल खाती है।

अन्तर्राष्ट्रीय मई दिवस का वर्ग स्वरूप इस तथ्य से ज़रा भी नहीं बदलता कि विभिन्न महाद्वीपों के देशों में, जिनकी सामाजिक-आर्थिक प्रणालियां एक जैसी नहीं हैं, ऐसे नारे तथा आह्वान जारी किये जा सकते हैं, जो भिन्न-भिन्न होते हुए भी परस्परविरोधी नहीं होते। लेनिन ने वर्तमान शताब्दी के आरम्भ में ही कह दिया था कि मई दिवस मनाते समय अन्तर्राष्ट्रीय मांगें ऐसी मांगों से मिलायी जानी चाहिए, जो राष्ट्रीय कार्यभारों को हल करने की आवश्यकता से उत्पन्न होती हैं।** मई दिवस समारोहों की तैयारी करते समय और उसे मनाते समय मज़दूर आन्दोलन की अग्रगामी शक्तियां इस विचार को अपना प्रस्थान-बिन्दु बनाते हुए कि जनवाद के लिए संघर्ष समाजवाद के लिए संघर्ष का अभिन्न अंग है, वर्गों के सहबन्धों को व्यापक बनाती हैं, मेहनतकशों के आर्थिक हितों तथा राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ती हैं। यहां भी मज़दूर वर्ग का अन्तर्राष्ट्रीयतावाद तथा उसकी शक्तियों का एकीकरण समस्त जनवादी तथा युद्धविरोधी आन्दोलनों की व्यापक एकता का आधार हैं।

२. भविष्य की ओर लक्षित उदाहरण

विश्व समाजवाद अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर वर्ग की उच्चतम उपलब्धि है और वह साम्राज्यवाद के विरुद्ध खड़ी वर्तमान काल की प्रमुख शक्ति है। समाजवादी देशों में मई दिवस के मुख्य लक्षण क्या हैं?

शान्ति तथा सामाजिक प्रगति की नियति आज पहले से कहीं अधिक

---

* व्ला० इ० लेनिन, 'खारकोव में मई दिवस', भूमिका, १६००।

** व्ला० इ० लेनिन, 'रूसी सामाजिक-जनवादी मज़दूर पार्टी के उत्तरी संघ' को पत्र, १६०२।

विश्व समाजवादी प्रणाली के आर्थिक तथा राजनीतिक विकास की गत्यात्मकता से जुड़ी हुई है। इस तरह की गत्यात्मकता जनगण की सुख-समृद्धि की चिन्ता करना आवश्यक बना देती है। परन्तु युद्ध के ख़तरे को टालने की दृष्टि से भी वह समाजवादी जगत के लिए ज़रूरी है। अन्ततः, इसमें समाजवादी जीवन-पद्धति की सम्भावनाएं प्रदर्शित होती हैं। समाजवादी जगत के मित्रों तथा शत्रुओं की नज़रें, विकासमान देशों की विशाल, विविधतापूर्ण दुनिया की नज़रें उसपर टिकी हुई हैं। यह विकासमान दुनिया अपने पथ की तलाश कर रही है, चयन करना चाहती है और यह चयन कैसा होगा, यह बहुत हद तक समाजवाद की सफलताओं पर, उस द्वारा युग के आह्वान के उत्तर की विश्वसनीयता पर निर्भर करता है।

समाजवादी जगत के देशों में मई दिवस समाजवाद के निर्माण में प्राप्त सफलताओं की समीक्षा का, उनके बीच घनिष्ठ तथा चहुंमुखी सहयोग, पूंजीवादी जगत में मज़दूर तथा जनवादी आन्दोलनों के साथ, राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन के साथ उनकी एकजुटता के प्रदर्शन का दिवस बन गया है।

अक्तूबर क्रान्ति से पूर्व, जब संसार पर पूंजीवाद का पूरा बोलबाला था, क्रान्तिकारी शक्तियों का सर्वोपरि कार्यभार पुरानी दुनिया को नष्ट कर देना था। रूस में समाजवादी क्रान्ति के विजय के उपरान्त नये जीवन के निर्माण की समस्याओं ने, सर्वप्रथम आर्थिक समस्याओं ने सबसे महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लिया। इस बात ने सोवियतों के देश में मई दिवस समारोह मनाने की नयी परम्पराओं को जन्म दिया, जिनकी जीवन-शक्ति को अन्य समाजवादी देशों में भी मई दिवस समारोहों का अनुभव प्रदर्शित करता है।

१९२० से सोवियत जनतंत्र में मई दिवस समाज के कल्याणार्थ सृजनशील, सचेतन श्रम का दिवस बन गया। कम्युनिस्ट पार्टी की नौवीं कांग्रेस के एक निर्णयानुसार उस वर्ष मई दिवस अखिल रूसी सुब्बोत्निक * दिवस घोषित कर दिया गया, जिसे मई दिवस के जोरदार प्रदर्शनों का चरम बिन्दु बनना था। इस प्रकार मई दिवस पुनः संघर्ष और उत्सव को जोड़नेवाला सूत्र बन गया। परन्तु यह संघर्ष रचनात्मक कार्यकलाप का, जनव्यापी श्रम-पराक्रम का संघर्ष था। उस वर्ष के मई

---

* सुब्बोत्निक — समाज के कल्याणार्थ सोवियत मेहनतकशों द्वारा बिना पारिश्रमिक के स्वेच्छया किया जानेवाला काम।

दिवस पर अकेले मास्को में ४,२५,००० से अधिक लोगों ने सुब्बोत्निक में भाग लिया।

कम्युनिस्टों ने श्रम का उदाहरण प्रस्तुत किया। सुब्बोत्निक में लेनिन ने भी भाग लिया। क्रेमलिन सैनिक विद्यालय के छात्रों के साथ मिलकर उन्होंने क्रेमलिन के अहाते से निर्माण-सामग्री का मलबा हटाया। उसके बाद उन्होंने कार्ल मार्क्स के स्मारक और साथ ही मुक्त श्रम के स्मारक की आधारशिला रखते हुए भाषण किया।

१६२१ में पहली मई ने श्रम-नायकों का सम्मान करने की परम्परा आरम्भ की। इस अवसर पर भव्य कंसर्टों, खेल-कूद कार्यक्रमों, आदि का आयोजन किया गया।

मौजूदा परिस्थितियों में आर्थिक क्षेत्र अब भी दो परस्पर विरोधी सामाजिक प्रणालियों के बीच संघर्ष का मुख्य अखाड़ा बना हुआ है। पहले की तरह आज भी लेनिन की यह थीसिस सार्थक बनी हुई है कि "अब हम अपनी आर्थिक नीति के ज़रिये अन्तर्राष्ट्रीय क्रान्ति पर अपना मुख्य प्रभाव डाल रहे हैं।... इस क्षेत्र में संघर्ष विश्वव्यापी पैमाने पर हो रहा है। इस कार्यभार का समाधान करने पर हम अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर यक़ीनन और अन्तिम रूप में विजयी हो जायेंगे।"*

समाजवादी जगत के मेहनतकशों के पास यह मानने का पूरा-पूरा आधार है कि श्रम में उनकी सफलताएं अन्तर्राष्ट्रीय कर्त्तव्य की पूर्ति की सर्वप्रथम शर्त है, अन्तर्राष्ट्रीय सर्वहारा एकजुटता के सुदृढ़ीकरण में उनका योगदान है।

उन्हें इस बात पर गर्व है कि पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद के सदस्य-देशों का, जहां इस समय पृथ्वी की आबादी का दस प्रतिशत बसा हुआ है, विश्व की राष्ट्रीय आय में भाग एक चौथाई से अधिक तथा विश्व के औद्योगिक उत्पादन में भाग लगभग एक तिहाई है। कुल मिलाकर समाजवादी देशों की संवृद्धि दर पूंजीवादी देशों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है।

पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद के सदस्य-देशों के विकास ने बुर्जुआ प्रचार के इस तर्क का खण्डन कर दिया है कि समाजवादी व्यवस्था सामूहिक श्रम के आधार पर कृषि अर्थव्यवस्था को आधुनिक स्तर पर पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। ये देश, जिनके पास विश्व की

---

* व्ला० इ० लेनिन, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) के दसवें अखिल रूसी सम्मेलन में समापन-भाषण, २ जून, १६२१।

कृषियोग्य भूमि का केवल १६ प्रतिशत है और जहां मौसम की अवस्थाएं बहुत अनुकूल नहीं हैं, प्रति व्यक्ति अनाज इतनी मात्रा में पैदा करते हैं, जो विश्व के औसत स्तर से लगभग दो गुना ऊपर है। विश्व कृषि उत्पादन का लगभग पांचवां हिस्सा समाजवादी समुदाय के देशों में पैदा होता है।

आजकल उद्योग में विज्ञान तथा तकनीक की नवीनतम उपलब्धियों के समावेश का सर्वाधिक महत्व है। बुर्जुआ, ख़ास तौर पर, अमरीकी प्रचार इस क्षेत्र में समाजवादी जगत की उपलब्धियों का सर्वथा अन्तर्विरोधपूर्ण मूल्यांकन करता है। उदाहरण के लिए, जब अमरीकी सैनिक व्ययों में वृद्धि का औचित्य सिद्ध करना होता है, तो सोवियत संघ की कल्पनातीत तकनीकी उपलब्धियों की तथा अमरीका के पिछड़ जाने की बातें की जाती हैं। लेकिन जब समाजवादी देशों के साथ व्यापार पर प्रतिबन्ध के पगों को उचित ठहराना होता है, तो सोवियत संघ को घने, पिछड़े हुए गांव के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसके साथ व्यापार या सहयोग का अर्थ उसे आधुनिक सैनिक टेक्नालाजी मुहैया करना तथा अमरीकी राष्ट्रीय सुरक्षा की ज़ड़ खोदना है।

परन्तु सोवियत संघ ने बहुत पहले ही, अक्तूबर क्रान्ति की विजय के उपरान्त अपनी टेक्नालाजिकल आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली थी। इस चीज़ ने उसके लिए द्वितीय विश्वयुद्ध में विजयी होना, सबसे पहले अन्तरिक्ष के प्रवेश-द्वार खोलना, अन्तरिक्ष का बड़े पैमाने पर शान्तिपूर्ण ढंग से अनुसंधान शुरू करना, विश्वसनीय रक्षा-क्षमता सुनिश्चित करना, कुल मिलाकर उत्पादक शक्तियों का सफलतापूर्वक विकास करना सम्भव बनाया। समग्र रूप में पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद के पास ज़बर्दस्त वैज्ञानिक-तकनीकी क्षमता है। पेटेंटों के लिए विश्व में कुल अर्ज़ियों में ४० प्रतिशत तथा विश्व के पेटेंटों का लगभग २० प्रतिशत हिस्सा पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद का है।

सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में उन समाजवादी देशों की उपलब्धियां भी बहुत बड़ी हैं, जो पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद में नहीं हैं। उदाहरण के लिए, चीन लोक जनतंत्र में, जहां आबादी एक अरब से ऊपर है, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रो में गहन परिवर्तन हुए हैं। छठे पंचवर्षीय योजनाकाल (१९८१-१९८५) में, जब ख़ास तौर पर कृषि उत्पादन अत्यन्त द्रुत गति से बढ़ा, उसके कुल औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन में औसत वार्षिक वृद्धि ११ प्रतिशत रही। किसानों की औसत वार्षिक शुद्ध आय में वृद्धि लगभग १४ प्रतिशत थी तथा मज़दूरों

एवं कर्मचारियों के परिवारों के प्रति सदस्य के लिए यह वृद्धि ७ प्रतिशत थी।

यहां पश्चिम में प्रचलित कतिपय राजनीतिक अटकलबाज़ियों की चर्चा करना आवश्यक है, जिनमें "विश्व समाजवाद" तथा "समाजवादी समुदाय" की अवधारणाओं की ग़लत व्याख्या की जाती है। इस सिलसिले में समाजवादी जगत में फूट, उसमें किसी "विशेषाधिकारप्राप्त ग्रुप" की विद्यमानता के बारे में बात की जाती है। जैसा कि सुविदित है, "विश्व समाजवादी प्रणाली" की अवधारणा के अन्तर्गत समस्त समाजवादी देश आ जाते हैं। परन्तु "समाजवादी समुदाय" की अवधारणा अधिक संकुचित है, जो अधिकांश समाजवादी राज्यों के सम्बन्धों के स्वरूप, विशेष रूप से, पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद तथा वारसा संधि जैसे बहुपक्षीय संगठनों की उनकी सदस्यता पर, उनके बीच घनिष्ठ और विविधतापूर्ण पारस्परिक सम्पर्कों पर आधारित है, जो समाजवादी अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के सम्बन्धों को सच्चे अर्थों में अपनी परिधि में लाते हैं। परन्तु प्रत्येक समाजवादी देश समुदाय के प्रति अपना सम्बन्ध मुक्त रूप से निर्धारित करता है। वह आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में समाजवादी समुदाय के साथ अधिक घनिष्ठ सम्बन्धों का प्रश्न पेश कर सकता है, जो उसकी इच्छा तथा तत्परता पर निर्भर करता है।

समुदाय के देश यह नहीं मानते कि किसी भी तरह के अवरोध उन्हें दूसरे समाजवादी देशों से अलग करते हैं। वे विश्व समाजवादी प्रणाली के समस्त राज्यों के साथ ईमानदारीभरे, खुले सम्बन्धों के पक्ष में, साथीपन की भावना में विचार-विनिमय के पक्ष में हैं। अत: सोवियत संघ और सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी मुख्यतया उसे ध्यान में रखने का प्रयास करते हैं, जो समाजवादी जगत को ऐक्यबद्ध करता है। इसी कारण वे समाजवादी राज्यों को एक दूसरे के समीप लानेवाले प्रत्येक पग का, उनके बीच सम्बन्धों में प्रत्येक सकारात्मक परिवर्तन का सहर्ष स्वागत करते हैं।

जाहिर है, सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी इस ओर से आंखें नहीं मूंदती कि मतभेद क़ायम हैं—ख़ास तौर पर अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर। परन्तु वह दूसरी बात पर ध्यान देती है—यह है तीसरे देशों के हितों को कोई आंच पहुंचाये बिना कई मामलों में समानाधार पर मिलकर काम करने की सम्भावना।

समाजवादी समुदाय अन्तरिक्ष के सैन्यीकरण के विरुद्ध चीन के रुख़

का, नाभिकीय शस्त्रास्त्रों का पहले उपयोग न करने के उसके संकल्प का स्वागत करता है। पिछले कुछ वर्ष सोवियत संघ तथा चीन के बीच उभयपक्षीय सम्बन्धों के विकास के लिए अत्यन्त उल्लेखनीय रहे। दो देशों के बीच संसदीय प्रतिनिधिमंडलों, उच्च स्तरीय सरकारी यात्राओं का विनिमय हुआ है, व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई है, सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक आदान-प्रदान ने सक्रिय रूप धारण किया है। दो महान समाजवादी देशों के सहयोग के दृढ़ीकरण में आगे प्रगति—और सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की २७वीं कांग्रेस में इसपर ज़ोर दिया गया था—सोवियत तथा चीनी जनगण के गहन हितों से, एशिया और सारे संसार में शान्ति तथा सुरक्षा के हितों से पूरी तरह मेल खाती है।

अपने सकारात्मक उदाहरण के बल पर समाजवादी देश संसार के ग़ैरसमाजवादी भाग के मेहनतकशों को सामाजिक प्रगति और पूर्ण राष्ट्रीय मुक्ति के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं, उनकी चेतना के विकास पर गहरी छाप डालते हैं। अक्तूबर क्रान्ति से पूर्व मेहनतकशों की समाजवादी चेतना मज़दूर आन्दोलन के हरावल द्वारा मार्क्सवादी सिद्धान्त तथा समाजवाद के आदर्शों के प्रचार के आधार पर बनती थी। परन्तु उस समय तक ऐसे ठोस तथ्य नहीं थे, जो नयी व्यवस्था की श्रेष्ठता सिद्ध कर सकते, स्वयं ऐसी व्यवस्था अभी उपस्थित नहीं थी। अक्तूबर क्रान्ति की विजय के उपरान्त ग़ैरसमाजवादी देशों के मेहनतकशों को उस प्रणाली के बारे में अपने विचार बनाने की सम्भावना प्राप्त हुई, जिसे पूंजीवाद का स्थान ग्रहण करना है।

पूंजीवाद ने समाजवाद के जन्म को इतिहास की एक "ग़लती" माना, जिसे "सुधारना" आवश्यक था। इस हेतु क़ानून और नैतिकता का कोई खयाल रखे बिना समस्त साधनों को न्यायोचित ठहराया गया। ये साधन थे: सशस्त्र हस्तक्षेप, आर्थिक नाकाबन्दी, विध्वंसकारी गतिविधियां, प्रतिबन्ध, "दंड," सहयोग से इन्कार। परन्तु नयी व्यवस्था की स्थापना को, अस्तित्वमान रहने के उसके अधिकार को कुछ भी नहीं रोक सका।

आरम्भ में सोवियत संघ में और फिर अन्य देशों में समाजवाद के निर्माण ने इतिहास की रचना करने तथा समाज के जीवन का स्वतंत्र रूप से नेतृत्व कर सकने की सर्वहारा वर्ग की "असमर्थता" के बारे में बुर्जुआ प्रचार द्वारा फैलायी जानेवाली कपोल-कल्पनाओं का पूर्णत: खण्डन कर दिया है। वास्तविक समाजवाद मेहनतकशों को शोषण, उत्पीड़न, सामाजिक तथा राष्ट्रीय असमानता के सब रूपों के विरुद्ध

विरोध की भावना में शिक्षित-दीक्षित करता है। समाजवादी देशों की सफलताएं ग़ैरसमाजवादी देशों के मेहनतकशों को अपनी स्थिति को नये ढंग से देखने, अपने हितों की ख़ातिर संघर्ष में नये, प्रगतिशील विचार ग्रहण करने में मदद देती हैं।

समाजवादी जगत में मई दिवस में भाग लेनेवालों के हाथों में झंडे तथा पोस्टर उनकी सफलताओं तथा उपलब्धियों को ही प्रतिबिम्बित नहीं करते, अपितु इन देशों के चहुंमुखी सहयोग को दृढ़ बनाने तथा उसका विस्तार करने का भी आह्वान करते हैं।

समाजवादी देशों के जनगण द्वारा अपने अन्तर्राष्ट्रीयतावादी कर्त्तव्य की सफल पूर्ति पारस्परिक, समन्वित प्रयासों का अधिकाधिक तकाज़ा करती है। जीवन ने लेनिन के इस निष्कर्ष की पूर्ण रूप से पुष्टि कर दी है कि समाजवादी देशों के व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के फलस्वरूप "...समस्त राष्ट्रों के सर्वहाराओं द्वारा एक अविभाज्य, एक समान योजना के अनुसार विनियमित विश्व अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा। यह प्रवृत्ति अभी ही पूंजीवाद के अन्तर्गत पूर्ण एवं स्पष्ट रूप में उजागर हो चुकी है और समाजवाद के अन्तर्गत वह बिनाशर्त आगे विकसित होगी और पूर्ण परिणति तक पहुंचेगी।" *

पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद के सदस्य-देशों का आर्थिक शिखर सम्मेलन (मास्को, जून १९८४) सहयोग का आगे प्रसार करने में एक बहुत बड़ा पग था। इस सम्मेलन ने आर्थिक विकास के मूल प्रश्नों पर गहरा तथा चहुंमुखी ढंग से विचार किया। उसने कार्रवाई की दीर्घकालीन योजना तैयार की, जिसका लक्ष्य समाजवादी आर्थिक एकीकरण का पैमाना बढ़ाना तथा उसकी कारगरता का स्तर ऊपर उठाना था। सम्मेलन ने पार्टी तथा राज्यों के नेताओं की सर्वोच्च स्तर पर नियमित रूप से बैठकें करने का औचित्य स्वीकार किया। इन बैठकों का उद्देश्य यह है कि बड़ी-बड़ी आर्थिक समस्याओं के समाधान तथा विज्ञान, तकनीक और भौतिक उत्पादन के क्षेत्रों में सीधी अन्योन्यक्रिया के उपाय निर्धारित किये जायें।

सन् २००० तक की अवधि के लिए वैज्ञानिक-तकनीकी प्रगति के वृहद कार्यक्रम को, जिसे पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद के सदस्य-देशों ने दिसम्बर १९८५ में अपने ४१वें (असाधारण) अधिवेशन में अनुमोदित किया था, बिरादराना समाजवादी देशों की

---

* व्ला० इ० लेनिन, 'कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की दूसरी कांग्रेस के लिए थीसिसें', १९२०।

सामाजिक-आर्थिक प्रगति की रफ़्तार तेज़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना है। समाजवादी समुदाय के देशों की अर्थव्यवस्था द्वारा विकास के गहन पथ में संक्रमण ने इस कार्यक्रम का विशदीकरण करना वस्तुगत रूप से आवश्यक बना दिया था। इस समय तक ये देश विज्ञान, तकनीक, उत्पादन की अलग-अलग समस्याओं का संयुक्त रूप में समाधान करने का काफ़ी अनुभव अर्जित कर चुके हैं। वृहद कार्यक्रम को स्वीकार करने के साथ पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद के सदस्य-देशों ने वैज्ञानिक-तकनीकी प्रगति के व्यवहारत: सभी क्षेत्रों में व्यापक एकीकरण में संक्रमण किया है।

वृहद कार्यक्रम ने नाना प्राथमिकताप्राप्त दिशाओं का चयन किया है (अर्थव्यवस्था का इलेक्ट्रोनीकीकरण, बड़े पैमाने पर स्वचालन, परमाणु ऊर्जा, नयी सामग्रियों तथा टेक्नालाजियों का निर्माण, जैव-प्रौद्योगिकी), जिनमें आधारभूत वैज्ञानिक विचारों को ठोस अग्रगामी टेक्नालाजियों में परिणत किया जायेगा, नयी पीढ़ी की उच्च कारगर मशीनों का निर्माण किया जायेगा। यह कार्यक्रम ऐसे सतत नियोजन के सिद्धान्तों पर आधारित है, जो वैज्ञानिक विचारों से शुरू करके, टेक्नालाजियों से गुज़रते हुए नवाचारों के बड़े पैमाने पर प्रचलन तक पहुंचेगा। समस्याओं के समाधान में सहयोग तथा विशेषीकरण समय तथा संसाधनों की बचत करेंगे तथा वैज्ञानिक-तकनीकी प्रगति और उत्पादन के विश्व-स्तरों पर पहुंचना सम्भव बनायेंगे।

वृहद कार्यक्रम में यह परिकल्पना की गयी है कि सन् २००० तक पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद के देशों की श्रम-उत्पादकता कम से कम दुगुनी हो जायेगी, ऊर्जा तथा कच्चे माल की खपत में तेज़ी से कमी होगी, नवीनतम वैज्ञानिक उन्नति का उपयोग करते हुए और अधिक उत्पाद तैयार किये जायेंगे। इससे पूंजीवाद के साथ शान्तिपूर्ण प्रतियोगिता में समाजवाद की स्थिति दृढ़ बनेगी, साम्राज्यवाद की वैरभावपूर्ण कार्रवाइयों से, पूंजीवाद में अन्तर्निहित संकट तथा अन्य नकारात्मक प्रक्रियाओं के प्रभाव से समुदाय की तकनीकी-आर्थिक रक्षा को मज़बूत बनाया जा सकेगा।

फिर भी समाजवादी समुदाय के देश श्रम के विश्व-विभाजन में सक्रिय रूप से भाग लेने तथा पूंजीवादी देशों समेत समस्त देशों के साथ वैज्ञानिक-तकनीकी सहयोग करने की अपनी तत्परता पर ज़ोर देते हैं। वे विज्ञान, प्रविधि तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में प्रतिबन्धों तथा

भेदभाव की नीति के कट्टर विरोधी हैं, जिसे अमरीका तथा कुछ अन्य देशों के शासक क्षेत्र अमल में ला रहे हैं। पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद के सदस्य-देश यह मानते हैं कि यह नीति समग्र रूप में अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों को हानि पहुंचाती है तथा उसका वैज्ञानिक-तकनीकी प्रगति की, जिसके दायरे में आज पूरा संसार आ गया है, अन्तर्वस्तु के साथ मेल नहीं है।

वृहद कार्यक्रम पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद के चौखटे के अन्दर वैज्ञानिक-तकनीकी प्रगति में उभार लाने की आवश्यकता की समाजवादी देशों की समझ प्रतिबिम्बित करता है। इस समय वैज्ञानिक-तकनीकी प्रगति को त्वरित करने की समस्या काफ़ी हद तक राजनीतिक समस्या भी है, क्योंकि उसके समाधान पर समाजवाद की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की स्थिरता निर्भर करती है। पश्चिम के आक्रामक क्षेत्र समाजवादी देशों को टेक्नालाजियों की विश्व मंडी से अलग-थलग करते समय इस बात पर दांव लगाते हैं कि समाजवादी समुदाय विज्ञान तथा तकनीक का स्वयं गत्यात्मक विकास नहीं कर सकेगा और आत्मनिर्भरता के आधार पर अपनी रक्षा-क्षमता को सुदृढ़ नहीं बना सकेगा।

इन परिस्थितियों में वर्गविरोधी की चुनौती का केवल ठोस अमली कार्रवाई से ही उत्तर दिया जा सकता है: अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का विकास करना, ताकि संयुक्त प्रयासों से आगे बढ़ने की गति तेज़ की जा सके, बाहरी राजनीतिक दबाव की फलहीनता सिद्ध की जा सके।

पहली मई को समाजवादी जगत के मेहनतकश ऐसे नारे उद्घोषित करते हैं, जो पूंजीवादी विश्व में मज़दूर आन्दोलन के साथ और इजारेदारियों के विरुद्ध तथा जनवाद और सामाजिक प्रगति के हेतु संघर्षरत समस्त जनवादी शक्तियों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हैं।

प्रमुख सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समस्याओं के समाधान में समाजवादी देशों की सफलताओं ने, समाजवाद के जनवादी तथा मानवीय स्वरूप की संसार में बढ़ती लोकप्रियता ने इजारेदार बुर्जुआ वर्ग को पूंजीवादी देशों में मज़दूर वर्ग की मांगों के फैलते दायरे के समक्ष अधिक लचीला बनने तथा श्रम के विरुद्ध अपने प्रत्याक्रमण में विश्व शक्ति-संतुलन को ध्यान में रखने के लिए बाध्य किया है।

विश्व समाजवाद की स्थिति का सुदृढ़ीकरण पूंजीवादी देशों

के मज़दूर आन्दोलन के हरावल को सत्ता की उपलब्धि के शान्तिपूर्ण रूपों की दिशा में उन्मुख करता है, समाजवाद में संक्रमण करने के ऐसे पथों की खोज करने की सम्भावनाओं के द्वार खोलता है, जो राष्ट्रीय परम्पराओं तथा मज़दूर आन्दोलन के विकास के स्तर को ध्यान में रखने में अधिकतम सहायक हों। यदि विश्व शक्ति-संतुलन साम्राज्यवाद के पक्ष में होता, तो समाजवाद की ओर जनवादी पथ के प्रश्न को व्यावहारिक सतह पर रखना शायद ही सम्भव होता।

पूंजीवादी विश्व में व्यापक बेरोज़गारी की परिस्थितियों में हज़ारों-लाखों मेहनतकशों के लिए समाजवादी देशों के साथ बाह्य आर्थिक सम्बन्धों के विकास का अत्यधिक महत्व है, जो आम लोगों के लिए काम पाने की सम्भावना सुनिश्चित करते हैं। जहां पश्चिमी देश, जिनमें अमरीका सर्वोपरि है, अपनी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति में हुक्मशाही की भाषा से काम लेते हैं, वहां समाजवादी देशों का ध्येय समस्त राष्ट्रों के बीच ऐसे सम्बन्धों की स्थापना करना है, जिनके अन्तर्गत हर तरह का शोषण, भेदभाव, प्रभुसत्तासम्पन्न देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप के साधन के रूप में आर्थिक लीवरों का उपयोग वर्जित होते हैं।

पश्चिम के संघर्षरत सर्वहारा वर्ग के साथ समाजवादी मज़दूर वर्ग की एकजुटता की प्रत्यक्ष कार्रवाइयों का भी बहुत अधिक महत्व है। इसका ज्वलन्त उदाहरण वह विविधतापूर्ण समर्थन है, जो समाजवादी देशों की ट्रेड यूनियनों ने अंग्रेज़ खान-मज़दूरों को १९८४-१९८५ में उनकी लंबी हड़ताल में प्रदान किया था।

समाजवादी देशों में पहली मई के नारों में उन नारों को प्रमुख स्थान प्राप्त होता है, जो साम्राज्यवाद, नव-उपनिवेशवाद, तानाशाही हकूमतों, नस्लवाद और पृथग्वासन के विरुद्ध, आर्थिक स्वतंत्रता तथा न्यायपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के हेतु नवस्वतंत्र देशों के जनगण के संघर्ष में उनके साथ एकजुटता को सुदृढ़ बनाने का आह्वान करते हैं।

औपनिवेशिक तथा पराधीन देशों के जनगण की सहायता सोवियत राज्य के जन्म के समय से ही उसके मज़दूर वर्ग की सर्वहारा एकजुटता की परम्परागत अभिव्यक्ति बनी हुई है। लेनिन ने लिखा: "यह बात निर्विवाद है कि अग्रगामी देशों का सर्वहारा वर्ग पिछड़े हुए देशों के मेहनतकश जनसाधारण की सहायता कर सकता है और उसे अवश्य करना चाहिए, कि पिछड़े हुए देश विकास की अपनी मंज़िल से उस समय

बाहर निकल सकते हैं, जब सोवियत जनतंत्रों का विजयी सर्वहारा वर्ग इन जनसाधारण की ओर सहायता का हाथ बढ़ायेगा और उन्हें समर्थन देने की स्थिति में होगा।" *

स्वयं यह तथ्य कि समाजवादी राज्य अस्तित्वमान हैं, राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन के नाना दस्तों की कार्रवाइयों के अन्तर्य, रूपों तथा सामाजिक-आर्थिक दिशा पर गहरी छाप डालता है। राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके जनगण को विश्व समाजवाद पिछड़ेपन पर क़ाबू पाने, सामाजिक-आर्थिक प्रगति हासिल करने का विश्वसनीय पथ प्रदर्शित करता है। काफ़ी हद तक विश्व समाजवाद के उदाहरण के प्रभावान्तर्गत बहुत से विकासमान राज्यों ने अर्थव्यवस्था में राजकीय नियोजन विषयक निर्णय किया। अभी अपने विकास का पथ चुन रहे अथवा समाजवाद की दिशा में ले जानेवाले मार्ग पर निकल पड़े जनगण के लिए उस ग़ैरपूंजीवादी पथ के सिद्धान्त तथा व्यवहार के अध्ययन का बहुत बड़ा महत्व है, जो भूतपूर्व ज़ारशाही रूस के सीमावर्ती जातीय क्षेत्रों तथा मंगोलिया में ज्वलंत रूप से मूर्त रूप ग्रहण कर चुका है।

समाजवादी देश आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में जितने ज़्यादा मज़बूत बनते चले गये, उनके लिए राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनों को और विदेशी अतिक्रमणों से अपनी स्वतंत्रता तथा स्वाधीनता की रक्षा करनेवाले विकासमान देशों को चहुंमुखी सहायता देने की सम्भावनाएं उतनी ही ज़्यादा बढ़ती गयीं। समाजवादी समुदाय ने साम्राज्यवादियों को प्रतिक्रान्ति का निर्यात करने से कई बार विश्वसनीय ढंग से रोका। यही अंगोला, अफ़ग़ानिस्तान, वियतनाम, कम्पूचिया, इथियोपिया और लाओस में हुआ। विकासमान देशों में राष्ट्रीय मुक्ति तथा क्रान्तिकारी शक्तियों के विरुद्ध साम्राज्यवाद जो स्थानीय संघर्ष छेड़ता है, उनमें उसे मिलनेवाली सीमित सफलताएं तक भी अब निरन्तर घटती जा रही हैं।

सोवियत संघ और समाजवादी समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ नवस्वतंत्र देशों के सम्बन्धों का इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण में अत्यधिक महत्व है। ये सम्बन्ध निरन्तर विस्तारित होते जा रहे हैं, मज़बूत बनते जा रहे हैं, क्योंकि वे सही अर्थों में न्यायपूर्ण तथा समानतापूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों पर आधारित हैं। इस तरह समाजवादी समुदाय की आर्थिक तथा तकनीकी सहायता से १००

* व्ला० इ० लेनिन, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की दूसरी कांग्रेस में जातीय व औपनिवेशिक प्रश्न पर रिपोर्ट, २६ जुलाई, १९२०।

से अधिक विकासमान देशों में लगभग ४,००० परियोजनाओं का निर्माण हो चुका है। इसके अलावा १२० विकासमान देशों के दसियों हज़ार नौजवान इस समय समाजवादी समुदाय के राज्यों के उच्च या माध्यमिक शिक्षा संस्थानों में ज्ञानार्जन कर रहे हैं तथा ७० देशों के १५,००० से अधिक व्यक्ति पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद के देशों में उत्पादन-प्रशिक्षण पा रहे हैं। अकेले सोवियत संघ की सहायता से अफ़्रीकी महाद्वीप में ३३० से अधिक परियोजनाएं निर्मित और चालू हो चुकी हैं, जबकि ३०० अन्य परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। अफ़्रीकी देशों के लिए सोवियत संघ की सहायता से ४,५०,००० से अधिक विशेषज्ञ तथा हुनरमन्द मज़दूर तैयार किये गये हैं। सोवियत संघ अफ़्रीकी नौजवानों के लिए एक विश्वविद्यालय बन गया है: अफ़्रीका के २२,००० छात्र उसके शिक्षा संस्थानों में पढ़ रहे हैं।

समाजवादी देश संसार का विशेष रूप से "अमीर उत्तर" तथा "ग़रीब दक्षिण" में विभाजन करने पर आधारित झूठे सिद्धान्त की मदद से राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन को अपने स्वाभाविक साथी—समाजवादी समुदाय—से अलग-थलग करने की विभिन्न शक्तियों के, जिनमें मज़दूर आन्दोलन के अन्दर मौजूद शक्तियां भी शामिल हैं, प्रयासों का विरोध करते हैं।

शान्ति, जनवाद, राष्ट्रीय स्वतंत्रता तथा सामाजिक प्रगति का समर्थन करने की विश्व समाजवाद की सच्ची अन्तर्राष्ट्रीयतावादी नीति साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में समस्त देशों के मेहनतकशों के हितों की एकता सुनिश्चित करती है। यह नीति समाजवादी देशों में पहली मई दिवस के उत्सवों में सुस्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित होती है, जो संसार के समक्ष समाजवाद के इन विशिष्ट गुणों को प्रदर्शित करता है: सामूहिकता, साथियों की भांति पारस्परिक सहायता, स्वतंत्रता तथा मानवतावाद। समाजवाद समस्त मानवजाति के समक्ष एक प्रत्यक्ष यथार्थता, भविष्य की ओर लक्षित एक भव्य उदाहरण है।

३. पूंजीवाद के क़िलों में मई दिवस

पूंजीवादी देशों के मेहनतकशों की सर्वहारा एकजुटता उनकी इजारेदार विरोधी कार्रवाइयों में अधिकाधिक वज़नदार कारक बनती जा रही है। इन कार्रवाइयों में मई दिवस भी शामिल है। हाल के वर्षों

में इस उत्सव के समय होनेवाले प्रदर्शनों में लगाये जानेवाले नारे सर्वशक्तिशाली इजारेदारियों के विरुद्ध, काम पाने के अधिकार को मूर्त रूप देने, बुनियादी राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक अधिकार सुनिश्चित करने, मेहनतकशों की उपलब्धियों की रक्षा के लिए संघर्ष करने, इस संघर्ष में एकजुटता के लिए आह्वान करते हैं। और यह कोई संयोग की बात नहीं है।

इस शताब्दी के सातवें तथा आठवें दशक में ही अनुकूल आर्थिक अवस्थाओं की बदौलत मेहनतकशों ने अपनी स्थिति में कुछ सुधार हासिल करने में सफलता पायी। परन्तु आठवें दशक के मध्य में पूंजीवाद ने प्रत्याक्रमण शुरू कर दिया, मेहनतकशों को उनकी सामाजिक उपलब्धियों के एक महत्वपूर्ण भाग से वंचित कर दिया। इसके साथ ही उनका जीवन-स्तर घट कर कई वर्ष पीछे जा पहुंचा। आज जितनी बेरोज़गारी है, उतनी पूरे युद्धोत्तर काल में पहले कभी नहीं थी। छोटे-बड़े किसानों की हालत काफ़ी बिगड़ी है। कुछ फ़ार्म उजड़ गये हैं और उनके पुराने मालिक उजरती मज़दूरों की क़तारों में शामिल हो गये हैं। दूसरे बड़ी कृषि-इजारेदारियों और बैंकों के बन्धनों में कसते जा रहे हैं। सामाजिक स्तरीकरण बहुत तेज़ रफ़्तार से हो रहा है। अमरीका में, उदाहरण के लिए, सबसे ज़्यादा अमीर परिवारों के एक प्रतिशत के पास उन ८० प्रतिशत परिवारों की कुल दौलत से लगभग ढाई गुना अधिक दौलत है, जो सामाजिक पिरामिड का सबसे निचला भाग हैं।

सत्ताधारी साम्राज्यवादी क्षेत्र यह समझे बिना नहीं रह सकते कि ऐसी स्थिति राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक विस्फोटों के ख़तरे से भरी हुई है। परन्तु इसने उनकी नीति को अधिक विवेकसम्मत नहीं बनाया है। इसके विपरीत पिछले कुछ वर्षों में सत्ताधारी वर्ग के सबसे अधिक अडिग, प्रतिक्रियावादी क्षेत्रों का कई देशों में पलड़ा भारी होता रहा है। इस अवधि का लक्षण रहा है मेहनतकशों के अधिकारों पर इजारेदारियों का विशेष रूप से व्यापक तथा प्रचंड प्रहार।

पूंजीवाद साधनों के पूरे संचित शस्त्रागार का उपयोग करता है। ट्रेड यूनियनों को सताया जाता है तथा आर्थिक ब्लैकमेल का शिकार बनाया जाता है। मज़दूर विरोधी क़ानून लागू किये जाते हैं। वामपंथी तथा तमाम प्रगतिशील शक्तियों का पीछा किया जाता है। लोगों के विचारों तथा आचरण पर नियंत्रण, अधिक सटीक शब्दों में, निगरानी रखना एक आम नियम बन गया है। व्यक्तिवाद का तथा "जिसकी लाठी,

उसकी भैंस" के क़ानून का अभूतपूर्व बड़े पैमाने पर प्रसार किया जा रहा है।

"फूट डालो और राज करो!"—इस पुराने नारे का अनुसरण करते हुए शासक क्षेत्र मेहनतकशों को एक दूसरे से अलग करने, मज़दूर वर्ग में फूट गहन बनाने में मदद देनेवाले वस्तुगत तथा आत्मगत कारकों का उपयोग करते हैं।

मार्क्स ने पहले ही यह बता दिया था कि पूंजीवादी उत्पादन का सर्वहारा की चेतना पर दुहरा प्रभाव पड़ता है। एक ओर, वह सर्वहारा एकजुटता के विकास की भौतिक नींव का काम देता है, और दूसरी ओर, उसमें मज़दूर वर्ग के बीच "आन्तरिक प्रतियोगिता" का आर्थिक कारण अन्तर्निहित होता है, क्योंकि सर्वहारा वर्ग "प्रतियोगिता के सभी उतार-चढ़ावों"* से प्रभावित होता है।

मौजूदा हालात में मज़दूर वर्ग में "आन्तरिक प्रतियोगिता" की ओर रुझान को नयी उर्वर भूमि प्राप्त हुई है। पहली चीज़, बेरोज़गारी की दर में बहुत तेज़ी से वृद्धि के कारण कामगारों की अलग-अलग श्रेणियों के बीच, रोज़गारशुदा लोगों तथा बेरोज़गार लोगों के बीच तनाव बढ़ा है। दूसरी चीज़, अधिकांश विकसित पूंजीवादी देशों में प्रतिक्रियावादी शक्तियां विदेशी मज़दूरों के बहुत बड़े दस्तों का उपयोग करती हैं, ताकि विभिन्न जातियों के मज़दूरों के बीच प्रतियोगिता तीक्ष्ण बनाकर, अन्धराष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काकर मेहनतकशों द्वारा बेरोज़गारी के विरोध का रुख दूसरी ओर मोड़ा जा सके और इस तरह मज़दूर वर्ग में फूट को गहन बनाया जा सके। तीसरी चीज़, ट्रांसनेशनल कार्पोरेशन भी अपने प्रतिष्ठानों को उन देशों में, जहां मज़दूरी का स्तर नीचे है, स्थानान्तरित करके राष्ट्रवादी भावनाएं उत्तेजित करते हैं।

"एकजुटता विरोधी" प्रवृत्तियों को बुर्जुआ वर्ग और कभी-कभी सामाजिक-सुधारवादी राजनीतिज्ञ तथा विचारधारानिरूपक पोषित करते हैं। कामगारों को इस बात का कायल किया जाता है कि वे संकट के, सर्वप्रथम, बेरोज़गारी के विनाशकारी परिणामों से अपने को व्यक्तिगत अथवा निगम-कार्रवाइयों से बचा सकते हैं, भले ही ये कार्रवाइयां समग्र रूप में मज़दूर वर्ग के हितों के प्रतिकूल हों। दक्षिणपंथी प्रचार इस बात का बहुत अधिक इच्छुक है कि मेहनतकश अपनी कठिनाइयों का स्रोत

---

* का० मार्क्स, फ़े० एंगेल्स, 'कम्युनिस्ट घोषणापत्र', १८४८।

किसी भी सूरत में इजारेदारियों की स्वार्थपूर्ण नीति में नहीं, अपितु किन्हीं वस्तुगत कारणों—संकट, मौजूदा संरचनात्मक और टेक्नालाजिकल पुनर्गठन—में देखें।

सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यक्रम (नया संस्करण), जिसे १६८६ में २७वीं पार्टी कांग्रेस में स्वीकृत किया गया था, ऐसे निरर्थक प्रयत्नों का स्पष्ट उत्तर देता है: "वैज्ञानिक-तकनीकी क्रान्ति की उपलब्धियों को किन लक्ष्यों की सिद्धि करनी चाहिए, यह प्रश्न वर्तमानकालीन सामाजिक-राजनीतिक संघर्ष में मुख्य प्रश्नों में से एक बन गया है। हमारे युग में विज्ञान तथा तकनीक पृथ्वी पर सुख-समृद्धि का प्राचुर्य सुनिश्चित करने, समाज के फलने-फूलने के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए भौतिक अवस्थाओं का निर्माण करने की सम्भावना प्रदान करते हैं। परन्तु मनुष्य के मस्तिष्क तथा हाथों की इन सृजन-कृतियों को वर्गगत स्वार्थों के कारण, पूंजीवादी जगत में सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग को समृद्ध बनाने की ख़ातिर स्वयं उसके विरुद्ध लक्षित किया जा रहा है। यह है वह ज्वलन्त अन्तर्विरोध, जो २१वीं शताब्दी की देहरी पर मानवजाति के समक्ष उपस्थित है।"

व्यापक रूप से फैलाया जा रहा यह विचार भी कि नयी टेक्नालाजियों तथा तकनीकों के प्रचलन के फलस्वरूप श्रम-शक्तियों की बचत से मानो रोज़गार की गत्यात्मकता तथा उसके उलटे पहलू—बेरोज़गारी—का आधार निर्धारित होता है, स्पष्टतः "एकजुटता विरोधी" प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करता है। सारतः, यह "नवलुडिटी" दृष्टिकोण का प्रसार है, क्योंकि उसके आधार में भी लुडिटों का ही विचार निहित है, जिन्होंने १८वीं शताब्दी में मशीनों को नष्ट किया था, मानो नयी मशीनें मज़दूर वर्ग के स्वयं अस्तित्व को मिटा देती हैं। ज़ाहिर है, जिन मज़दूरों के दिमाग़ में इस तरह का विचार घर कर जाता है, वे वर्ग-संघर्ष में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि उनके लिए इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता: अगर पूरा वर्ग ही मिट रहा है, तो फिर अपने न्यूनाधिक खुशहाल अस्तित्व की रक्षा के लिए ही क्यों संघर्ष किया जाये। ठीक यही विचार बुर्जुआ प्रचार मेहनतकशों के दिमाग़ में बिठाने का प्रयास करता है।

परन्तु स्वयं ऐतिहासिक व्यवहार इस तरह के विचार का विश्वसनीय ढंग से खण्डन करता है और सर्वहारा एकजुटता के बढ़ते महत्व की पुष्टि करता है। यह बात कि नयी टेक्नालाजियों तथा मशीनों के प्रचलन

से श्रम की बचत होती है, एक सर्वविदित तथ्य है, जो हर काल के लिए सच है। परन्तु वैज्ञानिक-तकनीकी विकास चाहे क्रमिक ढंग से हुआ हो अथवा अनियमित ढंग से, श्रम-मंडी की प्रवृत्ति कतिपय डांवांडोलपन के बावजूद सदैव सतत विकास की रही है, जिससे नये-नये मेहनतकश लाखों की संख्या में उत्पादन की ओर आकृष्ट होते रहते हैं। तकनीकी नवाचारों के प्रचलन को बेरोज़गारी में वृद्धि का प्रमुख कारण मानना संकीर्ण मनोवृत्ति तथा संकीर्ण दृष्टिकोण को उजागर करना है, क्योंकि नयी तकनीक तो पूंजीवाद के अन्तर्गत रोज़गार को निर्धारित करनेवाले प्राचलों में से केवल एक है।

पूंजीवादी विश्व में बेरोज़गारी में तीव्र गति से वृद्धि का कारण यह है कि एक ओर, मेहनतकशों की व्यक्तिगत, समूहगत, सामाजिक तथा विश्वव्यापी आवश्यकताओं की काफ़ी पूर्ण रूप से पूर्ति की सम्भावनाएं प्रस्तुत करनेवाली नयी विराट प्रगति और दूसरी ओर, इन आवश्यकताओं तथा सम्भावनाओं के विकास पर इजारेदार पूंजी द्वारा कृत्रिम ढंग से लगाये जानेवाले अंकुश के बीच तीक्ष्ण अन्तर्विरोध है, जिससे उत्पन्न स्थिति का इजारेदार पूंजी मेहनतकशों की उपलब्धियों पर व्यापक प्रहार करने के लिए उपयोग करती है।

पूंजीवाद के अन्तर्गत बेरोज़गारी की वृद्धि में इजारेदारियों की भूमिका पर पर्दा डालने, तथा समाजवादी समुदाय के देशों के, जहां कोई बेरोज़गारी नहीं है, उदाहरण की आकर्षण शक्ति का महत्व घटाकर पेश करने का प्रयत्न करते हुए बुर्जुआ प्रचार यह कहता है कि पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद के सदस्य-देशों में पूर्ण रोज़गार का कारण उनके तकनीकी स्तर का पिछड़ेपन तथा निम्न श्रम-उत्पादकता है। जहां तक समाजवादी देशों के टेक्नालाजिकल "पिछड़ेपन" और इस मामले में पश्चिम पर उनकी "आश्रितता" का सम्बन्ध है, इसकी पहले ही चर्चा की जा चुकी है।

परन्तु यहां इस बात पर ज़ोर देना आवश्यक है कि समाजवाद श्रम-उत्पादकता में किसी भी वृद्धि के अन्तर्गत पूरे रोज़गार को क़ायम रखना सम्भव बनाता है, क्योंकि इस सामाजिक व्यवस्था में उत्पादन का उद्देश्य मुट्ठीभर लोगों के मुनाफ़ों में वृद्धि करना नहीं है, अपितु सबकी सुख-समृद्धि में निरन्तर उभार लाना, सबका चहुंमुखी विकास करना है। जब भौतिक तथा आत्मिक आवश्यकताओं की राह में शोषक वर्गों की सोद्देश्य नीति बाधक नहीं बनती, वे सदैव अपनी पूर्ति की सम्भावनाओं से आगे रहती हैं।

पूंजीवाद के अन्तर्गत हथियारों की दौड़ को तेज़ करने के लिए नयी वैज्ञानिक-तकनीकी सम्भावनाओं के उपयोग के विनाशकारी स्वरूप के कारण रोज़गार सम्बन्धी संकट तीक्ष्ण बनता है। युद्ध-उद्योग पर अधिकाधिक धन लगाया जाता है और इसका अर्थ श्रम-स्थानों का उन्मूलन है। जैसा कि सुविदित है, इसका युद्ध-उद्योग और पूरे समाज, दोनों में रोज़गार के स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

पूंजीवादी जगत में रोज़गार की गतिकी यह दर्शाती है कि मौजूदा हालात में श्रम के अधिकार के हेतु प्रत्यक्ष संघर्ष को शान्ति तथा निरस्त्रीकरण, व्यापक जनसमुदाय की क्रय-शक्ति में वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा के विकास, उजरत की दर को पूरी तरह बरकरार रखते हुए काम के घंटों में कमी, विश्राम-मनोरंजन की बेहतर सुविधाओं, शिक्षा-प्रणाली में जनवादी सुधार, पर्यावरण की रक्षा, आदि के हेतु संघर्ष के साथ मिलाना बहुत आवश्यक है।

बेरोज़गारी के विरुद्ध, जो करोड़ों लोगों के लिए त्रासदी है, व्यापक तथा बहुमुखी संघर्ष मज़दूर वर्ग, समस्त मेहनतकशों की एकजुटता, उनके द्वारा इजारेदार विरोधी कार्यकलाप, विशेष रूप से ट्रांसनेशनल कार्पोरेशनों के विरुद्ध लक्षित कार्यकलाप की अपेक्षा करता है।

ट्रांसनेशनल कार्पोरेशनों की शक्ति तथा उनकी शाखा-प्रशाखामय संरचना उन्हें शोषण बढ़ाने की विभिन्न अतिरिक्त सम्भावनाएं प्रदान करती हैं और इस तरह उजरती कामगारों के जीवन तथा श्रम की अवस्थाएं बिगाड़ी जाती हैं। ये कार्पोरेशन बहुधा इन विभिन्न अधिकारों तथा उपलब्धियों की उपेक्षा करते हैं, जिन्हें भिन्न-भिन्न देशों के मेहनतकशों ने हासिल किया। ट्रांसनेशनल कार्पोरेशनों के हाथों में एक हथियार है, जिसे वे मज़दूर आन्दोलन, अन्तर्राष्ट्रीय एकजुटता के विरुद्ध उपयोग में लाते हैं। यह हथियार है पूंजी का बड़े पैमाने पर तथा अप्रत्याशित रूप से एक देश से दूसरे देश को स्थानान्तरण, कल-कारखानों को हटाकर वहां पहुंचाना, जहां वर्ग-संघर्ष कम तीक्ष्ण है।

केन्द्रीयकृत प्रबन्ध ट्रांसनेशनल कार्पोरेशनों को सर्वहारा के राष्ट्रीय दस्तों में फूट डालने की सामाजिक नीति को अमल में लाने, उसमें अपने हितार्थ जोड़-तोड़ करने की सम्भावना प्रदान करता है। अति मुनाफ़ों की प्राप्ति तथा प्रभुसत्तासम्पन्न देशों में "क़ानूनी उपस्थिति" उन्हें राजनेताओं तथा ट्रेड यूनियन नेताओं को रिश्वत देकर, षड्यंत्र कर और बलात सत्ता-परिवर्तन कर इन राज्यों की नीति पर सक्रिय प्रभाव डालने की सम्भावना देती हैं।

आज ट्रांसनेशनल कार्पोरेशन ग़ैरसमाजवादी जगत में मज़दूर आन्दोलन का सबसे शक्तिशाली तथा सबसे ज्यादा ख़तरनाक विरोधी हैं। उनके विरुद्ध संघर्ष में निर्णायक सफलता केवल पूंजीवादी सामाजिक सम्बन्धों पर क़ाबू पाकर ही सम्भव है। परन्तु पूंजी के प्रभुत्व की परिस्थितियों में भी मेहनतकशों के संगठनों को उनका प्रभाव कमज़ोर बनाने, उनकी गतिविधियों के सर्वाधिक नकारात्मक परिणाम मिटाने की सम्भावना उपलब्ध रहती है। सब कुछ स्वयं इन संगठनों की शक्ति तथा उनके जुझारूपन पर निर्भर करता है।

इस सम्बन्ध में इस बात का उल्लेख किये बिना नहीं रहा जा सकता कि यद्यपि ट्रांसनेशनल कार्पोरेशनों की गतिविधियों का उद्देश्य उनके स्वार्थपूर्ण लक्ष्यों की पूर्ति ही है, फिर भी वे सर्वहारा वर्ग की एकजुटता को दृढ़ बनाने में मदद देती हैं: एकजुटता सर्वहारा वर्ग का सबसे अधिक शक्तिशाली तथा जांचा-परखा शस्त्र है। वस्तुगत परिस्थितियां मेहनतकशों के संगठनों को एक ही देश के पैमाने पर और साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रांसनेशनल कार्पोरेशनों के विरुद्ध संघर्ष की रणनीति तैयार करने के लिए बाध्य करती हैं। इन संगठनों की अधिकाधिक संख्या ट्रांसनेशनल कार्पोरेशनों की नीति के मुक़ाबले में सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के समाधान का वैकल्पिक कार्यक्रम प्रस्तुत करती है, उनके विरुद्ध कार्रवाइयों की मुख्य दिशा निर्धारित करती है।

मज़दूर आन्दोलन का सुधारवादी पक्ष भी अपने हितों की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर रक्षा करने की आवश्यकता अनुभव करने लगा है। पूंजीवादी यूरोप की ट्रेड यूनियनें अपने बीच सहयोग को गहन बनाते हुए ट्रांसनेशनल कार्पोरेशनों को संयुक्त रूप से मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपनी कार्रवाइयों को अधिकाधिक समन्वित कर रही हैं। वे संघर्ष के ये रूप निश्चित करती हैं: किसी देश में मज़दूर वर्ग पर ट्रांसनेशनल कार्पोरेशनों के प्रहार के विरुद्ध एकजुटतात्मक हड़तालें; ट्रांसनेशनल कार्पोरेशनों के साथ एक ही समय सामूहिक समझौते सम्पन्न करना; विभिन्न देशों में एक ही कार्पोरेशन के प्रतिष्ठानों की ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के बीच परामर्श।

ट्रांसनेशनल कार्पोरेशनों के विरुद्ध संघर्ष में विभिन्न रुझानोंवाली ट्रेड यूनियनों की संयुक्त कार्रवाइयों में विश्व ट्रेड यूनियन महासंघ विशेष भूमिका अदा करता है, जिसमें समाजवादी, पूंजीवादी तथा विकासमान देशों के २० करोड़ से अधिक मेहनतकश ऐक्यबद्ध हैं, चाहे

उनकी राजनीतिक अवस्थाएं, धार्मिक तथा पार्टी संलग्नता कुछ भी क्यों न हों। महासंघ में ६० राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन केन्द्र तथा ११ अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन असोसियेशनें हैं, जो अर्थव्यवस्था की एक ही शाखा अथवा एक दूसरी से संलग्न कई शाखाओं के आधार पर मेहनतकशों की संयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय कार्रवाइयां सुनिश्चित करते हैं। इन असोसियेशनों के दायरे में विभिन्न उद्योगों के ६०० संगठन आ जाते हैं। उनमें उन देशों के ६० से अधिक संगठन भी शामिल हैं, जिनकी ट्रेड यूनियनें विश्व ट्रेड यूनियन महासंघ में शामिल नहीं हैं।

विश्व ट्रेड यूनियन महासंघ का उद्देश्य है ट्रांसनेशनल कार्पोरेशनों के कार्यकलाप पर जनवादी नियंत्रण की स्थापना करना; किसी उद्यम का एक देश से दूसरे देश को स्थानान्तरण किये जाने पर एकसमान श्रम के लिए एकसमान उजरत हासिल करना; नयी टेक्नालाजी लागू करने और मेहनतकशों को पुन: प्रशिक्षित करने की योजनाएं तैयार करने और उन्हें मूर्त रूप देने के कार्य में ट्रेड यूनियनों की शिरकत को अनिवार्य बनाना; पूंजी निवेश की नीति पर मेहनतकशों के हितार्थ प्रभाव डालना।

विश्व ट्रेड यूनियन महासंघ का ट्रांसनेशनल कार्पोरेशनों के सम्बन्ध में एक स्थायी आयोग है, जिसका कार्यकलाप अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन आन्दोलन में अधिकाधिक दिलचस्पी पैदा कर रहा है। आयोग के अनुभव का सामान्यीकरण करते हुए १९८५ के अन्त में महासंघ की जनरल कौंसिल ने समस्त अन्तर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों का आह्वान किया कि वे अन्तर्राष्ट्रीय इजारेदारियों की प्रतिक्रियावादी नीति का मुंहतोड़ उत्तर देने के लिए अपनी कार्रवाइयों को ऐक्यबद्ध करें।

साम्राज्यवाद के दुर्गों में मेहनतकशों की व्यापक श्रेणियां केवल आन्तरिक समस्याओं से ही चिन्तित नहीं हैं और केवल अन्तर्राष्ट्रीय एकजुटता ही अनुभव नहीं करतीं। इस बात के बावजूद कि कई देशों में सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी देशों के साथ सद्भावना की अभिव्यक्ति मुसीबतों और दमन को जन्म दे सकती है, पूंजीवादी देशों में मई दिवस प्रदर्शनों में बहुधा सोवियत संघ की शान्ति की पहलों तथा पूरब के साथ आर्थिक सहयोग के, जिनसे हज़ारों-हज़ार लोगों के लिए रोज़गार सुनिश्चित होता है, समर्थन में नारे लगते हैं। इस पर्व पर अक्सर यह आह्वान सुनने को मिलता है: "व्यापार करो, लड़ो मत!"

पिछले चंद दशकों में पूंजीवादी देशों में राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन की समस्याओं में दिलचस्पी बहुत बढ़ी है। संघर्षरत जनगण के साथ, उदाहरण के लिए, निकारागुआ, चिली, साल्वाडोर के जनगण के साथ एकजुटता के नारों का मई दिवस प्रदर्शनों में अत्यन्त व्यापक प्रसार हुआ है।

मई दिवस की कार्रवाइयों की व्यापकता तथा कारगरता में और ज़्यादा वृद्धि के लिए राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर ट्रेड यूनियनों की एकता का अनन्य महत्व है। पहले मई दिवस प्रदर्शनों की पहल बहुधा मज़दूर वर्ग की पार्टियां करती थीं, परन्तु अब पूंजीवादी देशों में यह भूमिका ट्रेड यूनियनों ने अपना ली है। जिन देशों में ट्रेड यूनियनें ऐक्यबद्ध हैं, वहां मई दिवस पर मेहनतकशों की कार्रवाइयां भी अधिकाधिक ऐक्यबद्ध तथा सशक्त होती हैं।

मई दिवस प्रदर्शन उन देशों में अत्यन्त प्रभावशाली होते हैं, जहां विद्यमान बहुत से ट्रेड यूनियन केन्द्र संयुक्त रूप से उत्सव मनाने के लिए सहमत होते हैं। ऐसा ही १९८३ में फ़्रांस में, १९८६ में इटली में हुआ। टोकियो के योयोगी पार्क में, जहां परम्परागत रूप से मई दिवस सभा होती है, हर वर्ष हज़ारों-हज़ार मेहनतकश जमा होते हैं।

विभिन्न राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन केन्द्र बहुधा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों से सम्बन्धित होते हैं, इसके फलस्वरूप संयुक्त रूप से मई दिवस की तैयारियां करने और उसे मनाने में काफ़ी और कभी-कभी अलंघ्य कठिनाइयां पैदा होती हैं। इस कारण विश्व ट्रेड यूनियन आन्दोलन की एकता मेहनतकशों की अन्तर्राष्ट्रीय एकजुटता के लिए और साथ ही हर वर्ष मई दिवस कार्रवाइयों की सफलता के लिए नितान्त आवश्यक है।

जैसा कि सुविदित है, पांचवें दशक के अन्त में साम्राज्यवादी क्षेत्रों द्वारा छेड़े गये शीतयुद्ध की अवस्थाओं में मज़दूर आन्दोलन में सुधारवादी धड़े के संगठनों ने आन्दोलन में फूट डालनेवाली कार्रवाइयां कीं। अमरीका तथा ब्रिटेन के ट्रेड यूनियन नेताओं ने अक्तूबर १९४५ में स्थापित विश्व ट्रेड यूनियन महासंघ को विभक्त कर दिया, जो उस समय विद्यमान राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन केन्द्रों की बहुसंख्या को ऐक्यबद्ध करनेवाला इतिहास में पहला सच्चा विश्वव्यापी संगठन था। विश्व ट्रेड यूनियन महासंघ के मुक़ाबले में १९४९ में अन्तर्राष्ट्रीय फ़्री ट्रेड यूनियन महासंघ की, सुधारवादी ट्रेड यूनियनों के असोसियेशन की स्थापना की गयी। तब से ट्रेड यूनियनों की एकता की समस्या विश्व ट्रेड यूनियन

महासंघ, अन्तर्राष्ट्रीय फ़्री ट्रेड यूनियन महासंघ (सदस्य-संख्या ८ करोड़ ५० लाख) तथा विश्व श्रम संघ (सदस्य-संख्या १ करोड़ ८० लाख)—सुधारवादी तथा ऐतिहासिक तथा परम्परागत रूप से कैथोलिक चर्च से सम्बन्धित संगठन—पर निर्भर करती रही है।

अपनी स्थापना के समय से ही अन्तर्राष्ट्रीय फ़्री ट्रेड यूनियन महासंघ ने विभिन्न कम्युनिस्ट विरोधी निर्णय किये, वह विश्व ट्रेड यूनियन महासंघ में शामिल ट्रेड यूनियनों के साथ सम्पर्कों की स्थापना की राह में रुकावटें डालता रहा है। परन्तु यह नीति बहुत अक्सर ट्रेड यूनियनों के आम सदस्यों की इच्छा से टकराती है, जो जनसाधारण के हितों की रक्षा के लिए एकजुट होकर कार्रवाइयां करना चाहते हैं।

पूंजीवादी समाज की ठोस समस्याओं का सामना होने पर अन्तर्राष्ट्रीय फ़्री ट्रेड यूनियन महासंघ में शामिल ट्रेड यूनियन केन्द्रों के सदस्यों समेत मेहनतकशों को यह देखने की सम्भावना मिली है कि मेहनतकशों के निजी हितों की दृष्टि तक से ट्रेड यूनियन आन्दोलन में फूट के कितने नकारात्मक परिणाम निकल रहे हैं। इसलिए ट्रेड यूनियनों के आम सदस्य समस्त शोषितों की एकजुटतात्मक कार्रवाइयों में भाग लेने के लिए बहुधा अपने नेताओं पर दबाव डालते हैं।

सुधारवादी ट्रेड यूनियनों में ऐक्यबद्ध कामगारों पर सुसंगत वर्गगत संगठनों के उस सोद्देश्य कार्यकलाप का सारभूत प्रभाव पड़ता है, जिसका लक्ष्य कार्रवाई में एकता हासिल करना है।

तनाव-शैथिल्य की अवधि (सातवें दशक के अन्त तथा आठवें दशक) में अन्तर्राष्ट्रीय फ़्री ट्रेड यूनियन महासंघ के कई पृथक-पृथक राष्ट्रीय दस्तों ने उन ट्रेड यूनियनों के साथ, जो विश्व ट्रेड यूनियन संघ में शामिल हैं, सम्पर्कों पर प्रतिबन्ध की उपेक्षा की। विशेष रूप से सोवियत संघ के केन्द्रीय ट्रेड यूनियन निकाय—केन्द्रीय ट्रेड यूनियन कौंसिल—और अन्तर्राष्ट्रीय फ़्री ट्रेड यूनियन महासंघ के प्रमुख संगठनों जैसे कि ब्रिटिश ट्रेड यूनियनों, जर्मन ट्रेड यूनियन असोसियेशन, आदि के बीच सुदृढ़ सम्बन्ध क़ायम हुए। ट्रेड यूनियनों के बीच सम्बन्धों के विकास की स्वयं तर्कसंगति तथा मजदूर प्रतिनिधियों की वर्गगत चेतना ने सर्वहारा एकजुटता को सम्पर्कों के आधारभूत प्रभुत्वशाली उद्देश्य निरूपित करने में मदद दी। यह कोई संयोग की बात नहीं थी कि १६६६ में ट्रेड यूनियन एकता के सबसे कट्टर विरोधी—अमरीकी श्रम संघ-औद्योगिक संगठन कांग्रेस—ने विश्व ट्रेड यूनियन महासंघ के सदस्यों के साथ सम्पर्कों पर प्रतिबन्ध के बहुत

से अतिक्रमणों के "विरोध" के प्रतीकस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय फ़्री ट्रेड यूनियन महासंघ से अपना नाता तोड़ लिया था।

विश्व श्रम महासंघ तनाव-शैथिल्य के वर्षों में एकजुटता की प्रक्रियाओं से अलग-थलग खड़ा नहीं रहा, हालांकि वह अन्तर्राष्ट्रीय फ़्री ट्रेड यूनियन महासंघ की ट्रेड यूनियनों के साथ सहयोग को सदैव प्राथमिकता देता था। विश्व ट्रेड यूनियन महासंघ के साथ उसके सम्बन्धों पर अक्सर कम्युनिज़्मविरोध तथा सोवियतविरोध के बार-बार झटकों की काली छाया पड़ती रही और इस प्रगतिशील अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन केन्द्र को बदनाम करने के प्रयत्न किये जाते रहे। फिर भी १९७० में ही विश्व श्रम महासंघ ने समाजवादी देशों की ट्रेड यूनियनों के साथ सम्पर्कों के लिए एक आयोग की स्थापना की और १९७१ में इस संगठन तथा विश्व ट्रेड यूनियन महासंघ के महासचिवों की पहल पर दो संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों की पहली बैठक हुई।

परन्तु विश्व ट्रेड यूनियन आन्दोलन में आठवें दशक के अन्त तथा नौवें दशक के आरम्भ में स्थिति सारत: बदल गयी, जब अमरीकी प्रशासन ने तनाव-शैथिल्य की जड़ खोदने और समाजवादी देशों पर सैनिक श्रेष्ठता प्राप्त करने का दुस्साहसिकतापूर्ण मार्ग खुलेआम अपनाया। इन परिस्थितियों में ट्रेड यूनियन एकता के विरोधी फिर बहुत सक्रिय हो गये और तरह-तरह के बहानों की आड़ में एकजुटता की प्रवृत्तियों को निष्फल बनाने की कार्यनीति को अमल में लाने लगे।

अमरीकी श्रम संघ-औद्योगिक संगठन कांग्रेस ने अपनी अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियां बहुत तेज़ कर दीं। आठवें दशक के अन्त में अन्तर्राष्ट्रीय फ़्री ट्रेड यूनियन महासंघ तथा विश्व श्रम संघ के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर और समाजवादी देशों में मानव-अधिकारों के "उल्लंघन" के विरुद्ध साम्राज्यवादी मुहिम के समर्थन में उसने सोवियत ट्रेड यूनियनों में मानव-अधिकारों के कथित अतिक्रमणों से सम्बन्धित प्रश्न अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में उठाया। ट्रेड यूनियन एकता के दुश्मनों ने पोलैंड और अफ़ग़ानिस्तान की घटनाओं के सिलसिले में पश्चिम में सोवियत विरोधी उन्माद का उपयोग किया और इस तरह सुधारवादी ट्रेड यूनियनों तथा सुसंगत वर्गगत दिशावाली ट्रेड यूनियनों के बीच सम्बन्धों को ध्वस्त किया।

फिर भी ट्रेड यूनियन एकता के शत्रुओं की विध्वंसकारी गतिविधियों को बहुत सफलता नहीं मिली। मेहनतकश लोग राष्ट्रीय और साथ ही

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वहारा एकजुटता के महत्व तथा मूल्य को अधिकाधिक समझने लगे हैं। इसमें उन्हें हाल के वर्षों में अर्जित उनका अपना अनुभव सहायता देता है। इस तरह, दक्षिण अफ़्रीका, निकारागुआ, लेबनान तथा साल्वाडोर के मेहनतकशों, तुर्की तथा इंडोनेशिया के सक्रिय ट्रेड यूनियन कार्यकर्त्ताओं के समर्थन में वर्गगत दिशावाली ट्रेड यूनियनों के अथक कार्यकलाप की सुधारवादी ट्रेड यूनियन केन्द्र उपेक्षा नहीं कर सकते, जो उनके साथ संयुक्त अथवा समानान्तर कार्रवाइयां करते हैं।

वर्ग-संघर्ष की तर्कसंगति जनसाधारण को अपने सच्चे वर्गगत हितों, श्रम की महान अन्तर्राष्ट्रीय सेना में अपनी सहभागिता तथा समस्त स्तरों पर अन्तर्राष्ट्रीय एकजुटता और अधिक सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता को अधिकाधिक समझने में मदद देती है। मई दिवस कार्रवाइयों का बढ़ता हुआ पैमाना तथा गहनता इस बात का एक और प्रमाण हैं।

४. एकजुटता, स्वतंत्रता, विकास के हेतु

साम्राज्यवाद की औपनिवेशिक प्रणाली के ढह जाने के बाद उसके खंडहरों पर दर्जनों राज्यों का उद्‌भव हुआ। राष्ट्रीय मुक्ति क्रान्तियों तथा आन्दोलन की इस ऐतिहासिक विजय ने संसार में शक्ति-सन्तुलन पर अत्यधिक प्रभाव डाला। मानवजाति के बहुसंख्य जनगण के जीवन में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों की धीमी और कठिन परन्तु अविराम प्रक्रिया जारी है।

फिर भी राजनीतिक दांव-पेंचों, वायदों, रिश्वतों, सैनिक धमकियों, ब्लैकमेल और अक्सर स्वतंत्र हो चुके राज्यों के आन्तरिक मामलों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के ज़रिये पूंजीवाद को उनके साथ आर्थिक अधीनता के पहले के सम्बन्धों को बरकरार रखने में काफ़ी सफलता मिली है। इस आधार पर वह नव-उपनिवेशवाद की सबसे अधिक परिष्कृत प्रणाली का निर्माण करने और उसे विकसित करने, नवस्वतंत्र देशों की काफ़ी बड़ी संख्या को कसकर अपने साथ संलग्न करने में सफल रहा है।

इसके त्रासदीभरे परिणाम निकले हैं। विकासमान राज्यों के पास विशाल मानव तथा प्राकृतिक साधन हैं। वहां दुनिया की दो तिहाई आबादी बसी हुई है और ग़ैरसमाजवादी देशों में बुनियादी क़िस्म के खनिज पदार्थों का दो तिहाई से अधिक उनके पास है। परन्तु वे वस्तुतः घोर

दरिद्रता की स्थिति में हैं। नौवें दशक के आरम्भ में नवस्वतंत्र देशों में प्रतिव्यक्ति आय विकसित पूंजीवादी देशों की तुलना में ११ गुना नीचे थी। बात केवल अपेक्षाकृत दरिद्रता की ही नहीं है। यह तो निरक्षरता और अज्ञान, कुपोषण और अकाल, भयावह बाल मृत्यु दर, संक्रामक रोगों का मामला है, जो लाखों-लाख लोगों को अपनी लपेट में ले लेते हैं।

यह स्थिति सभ्यता के माथे पर कलंक का टीका है! इसके लिए अपराधी है साम्राज्यवाद। वह इतिहास के दृष्टिकोण से केवल इसी कारण अपराधी नहीं है कि पूरे के पूरे महादेशों की उपनिवेशवादी लूट-खसोट ने उन्हें घोर पिछड़ेपन की हालत में पहुंचा दिया है, अपितु अपने वर्त्तमान अमल के दृष्टिकोण से भी वह अपराधी है। अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक के, जो पूंजीवादी जगत के एक सबसे बड़े वित्तीय संगठनों में से एक है, आंकड़ों के अनुसार १९८५ में पश्चिम ने विकासमान देशों से असी वर्ष के अपने पूंजी-निवेशों की तुलना में २२ अरब डालर अधिक धन खसोटा। विकसित पूंजीवादी देश नवस्वतंत्र देशों को अपने लिए कच्चा माल सप्लाई करनेवाले पुच्छल्ले में बदलते हुए उनके उत्पादों की क़ीमतें घटाने और खाद्य-वस्तुओं समेत अपने उत्पादों की क़ीमतें बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं उठा रखते। १९८६ में बहुत से अफ़्रीकी देश, जो सूखे और फ़सल न होने के कारण संत्रस्त थे, पश्चिम से आयातित खाद्यान्न के लिए १९८५ की तुलना में १४ प्रतिशत अधिक क़ीमतें देने के लिए विवश हुए थे।

यह बात किसी अतिशयोक्ति के बिना कही जा सकती है कि साम्राज्यवादी प्रणाली काफ़ी हद तक विकासमान देशों की क़ीमत पर, उनके निर्ममतम शोषण के बल पर जी रही है। शोषण के रूप तथा विधियां बदलते रहते हैं, परन्तु उसका सार नहीं बदलता। उदाहरण के लिए, अमरीका की सकल राष्ट्रीय आय का काफ़ी बड़ा हिस्सा इन्हीं स्रोतों से बनता है। विकासमान देशों का सभी साम्राज्यवादी राज्य शोषण करते हैं, परन्तु अमरीकी साम्राज्यवाद यह काम, निस्सन्देह, सबसे ज़्यादा बेशर्मी से करता है। असमतुल्य विनिमय, असमानतापूर्ण व्यापार, बट्टे की दरें नियत करने में मनमानापन और तिकड़मबाज़ी, धन खसोटने की ट्रांसनेशनल कार्पोरेशनों की कार्रवाइयां — इन सबका एक ही लक्ष्य है। उनसे अमीरों की अमीरी और ग़रीबों की कंगाली बढ़ती हैं।

परन्तु इसके साथ-साथ लूट-खसोट की नीति का नवस्वतंत्र देशों

के जनगण द्वारा प्रतिरोध भी बढ़ता जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर राज्यों का एक बहुत बड़ा ग्रुप लंबे अर्से से मौजूद है। आर्थिक तथा सामाजिक-राजनीतिक विकास के स्तरों में सारे अन्तरों के बावजूद इस ग्रुप के एकसमान लक्षण तथा हित हैं। ये हैं औपनिवेशिक अथवा पराधीनता का अतीत तथा उसके परिणामों पर क़ाबू पाने की आवश्यकता; राजनीतिक स्वाधीनता तथा आर्थिक पराधीनता के बीच तीक्ष्ण अन्तर्विरोध; विश्व राजनीति तथा विश्व अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका बढ़ाने की आकांक्षा; नव-उपनिवेशवादी शोषण की वस्तुओं के रूप में इनके प्रति साम्राज्यवाद का रुख़। अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर इन देशों की कार्रवाइयां स्वतंत्रता, शान्ति तथा सामाजिक प्रगति के लिए जनगण के आम साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष के साथ वस्तुगत रूप से संलयित हो जाती हैं।

इस आधार पर राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन में साम्राज्यवाद विरोधी एकजुटता की भूमिका बढ़ती है। घटना-प्रवाह लेनिन के इस कथन की पुष्टि करता है कि "विश्व क्रान्ति की आसन्न निर्णायक लड़ाइयों में पृथ्वी की आबादी की बहुसंख्या का आरम्भ से राष्ट्रीय मुक्ति की ओर लक्षित आन्दोलन पूंजीवाद तथा साम्राज्यवाद के विरुद्ध मुड़ जायेगा, और, हो सकता है, उससे कहीं बड़ी क्रान्तिकारी भूमिका अदा करेगा, जिसकी हम प्रतीक्षा करते हैं।"*

स्वयं इतिहास ने राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन के सफल विकास के लिए एकजुटता के अत्यधिक महत्व की पुष्टि कर दी है। समाजवादी देशों के, पूंजीवाद के दुर्गों में मज़दूर तथा जनवादी आन्दोलनों के समर्थन से एशिया, अफ़्रीका तथा लैटिन अमरीका के जनगण, जो पहले "डंडे" से काम लेनेवाले उत्पीड़कों के विरुद्ध असमान लड़ाइयों में जूझे रहते थे, अब अधिक बलशाली हो गये हैं।

राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष में एकजुटता की महान भूमिका की चेतना सातवें दशक से, जो अपने अन्तिम गढ़—अफ़्रीका में—औपनिवेशिक प्रणाली के ढहने की अवधि है, मई दिवस उत्सव के व्यवहारत: सर्वत्र मनाये जाने में प्रकट हुई है। मेहनतकशों की अन्तर्राष्ट्रीय एकजुटता के इस दिवस पर मज़दूर, किसान, बुद्धिजीवियों के प्रतिनिधि, प्रगतिशील विचारों के सैनिक क्षेत्र नव-उपनिवेशवाद तथा युद्ध,

---

* व्ला० इ० लेनिन, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की तीसरी कांग्रेस में रू० क० पा० की कार्यनीति के बारे में भाषण, ५ जुलाई, १६२१।

नस्लवाद तथा पृथग्वासन के विरुद्ध सभी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों की एकजुटता की अपील करते हैं। ये हैं राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन की राजनीतिक मांगें।

एकजुटता का विकास होता जा रहा है। राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में उसकी कारगरता की जांच-परख हो चुकी है। अब आर्थिक स्वाधीनता प्राप्त करने और सामाजिक तथा आर्थिक समस्याएं हल करने के लिए उसकी आवश्यकता है। इसी कारण पहली मई के प्रदर्शनों के दौरान दुर्भिक्ष, दरिद्रता के विरुद्ध तथा विश्व व्यापार में समानता और नयी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के हेतु संघर्ष करने के नारे राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष के क्षेत्रों में अधिकाधिक प्रसारित होते जा रहे हैं।

नवस्वतंत्र तथा समाजवादी देशों के बीच समानता पर आधारित आर्थिक सहयोग के विकास ने राष्ट्रीय मुक्ति की शक्तियों के लिए साम्राज्यवादी राज्यों के आर्थिक दबाव का प्रतिरोध करने की सम्भावनाएं बढ़ायीं। अब साम्राज्यवाद नवस्वतंत्र देशों में अपनी आर्थिक तथा तकनीकी गतिविधियों की शर्तें उनपर पहले की तरह नहीं थोप सकता। बदली हुई परिस्थितियों में इन नवस्वतंत्र देशों ने अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों को पुनर्गठित करने, साम्राज्यवादी केन्द्रों के साथ किशोर राज्यों के व्यापार में असमानता का अन्त करने, साम्राज्यवादी इजारेदारियों, सर्वप्रथम, ट्रांसनेशनल कार्पोरेशनों द्वारा उनके प्राकृतिक तथा मानव संसाधनों के बर्बर शोषण का अन्त करने में पहलक़दमी की है।

नवस्वतंत्र देशों के विदेशी ऋणों की राशि का, जो दस खरब डालर की कल्पनातीत सीमा पर पहुंच गयी है, प्रश्न पिछले वर्षों में उभर कर सामने आया है। उन्हें प्रतिवर्ष ऋणों की जितनी धनराशि का भुगतान करना पड़ता है, वह एक खरब से ऊपर है। इससे केवल दीर्घकालीन विकास कार्यक्रम ही नहीं, अपितु सामान्य रूप से उनकी अर्थव्यवस्था के कार्य रहते रहने की सम्भावना ही खटाई में पड़ जाती है। इस समस्या का राजनीतिक अर्थ भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि साम्राज्यवाद विकासमान देशों की सामाजिक-आर्थिक तथा राजनीतिक लाइन पर भूमंडलीय नियंत्रण स्थापित करने के लिए ऋणों का उपयोग करता है। इस तरह ऋणों की अदायगी में कतिपय आस्थगन और नये ऋणों की मंजूरी के बदले में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सम्बन्धित सरकारों से सामाजिक कार्यक्रमों में कटौती करने, वेतन जाम करने, पूंजीवादी

इजारेदारियों के लिए अनुकूल "निवेश वातावरण" बनाने की मांग करता है।

दूसरी ओर, साम्राज्यवादी राज्य अपनी अर्थव्यवस्थाओं को स्थिरता प्रदान करने के लिए नवस्वतंत्र देशों के उन प्रयासों का विरोध करते हैं, जिनमें, उदाहरण के लिए, वे "चरम पग" शामिल हैं, जिन्हें उठाने का प्रस्ताव दिल्ली में वसंत, १९८३ में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के राष्ट्राध्यक्षों तथा सरकारों के प्रधानों के सम्मेलन में किया गया था। इस तरह नव-उपनिवेशवादी शक्तियों ने दरअसल "ट्रांसनेशनल कार्पोरेशनों के लिए आचार-संहिता" की स्वीकृति में बाधा डाली और विदेशी ऋणों के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने से इन्कार किया, जिस पर विकासमान देश ज़ोर देते हैं। उन्होंने कच्चे माल पर संयुक्त राष्ट्र संघ के "समेकित कार्यक्रम" को अन्तर्ध्वस्त किया, जिस पर प्रारम्भिक समझौता हो चुका था। जुलाई १९८५ में अमरीका ने कच्चे माल की कीमतें स्थिर करने के लिए एक संयुक्त कोष में भाग लेने से इन्कार कर दिया।

सोवियत संघ का इस समस्या के प्रति सारत: दूसरा ही रुख़ है। उसने जनवरी १९८६ में 'राज्यों की अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा—अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्ध सुधारने की एक महत्वपूर्ण शर्त' शीर्षक एक मेमोरेंडम संयुक्त राष्ट्र संघ को भेजा था। उसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया था कि विदेशी ऋणों की समस्या पश्चिम के साथ विकासमान देशों के सम्बन्धों का अभिन्न अंग है और अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों को न्यायपूर्ण, समानतापूर्ण तथा जनवादी आधार पर पुनर्निर्मित किये बिना इस समस्या का कोई सच्चा समाधान असम्भव है। विदेशी ऋणों की समस्या के समाधान की आवश्यक शर्तें हैं ऋणों एवं उधारों पर ब्याज की दरें घटाना, विनिमय दरों को स्थिर करना, व्यापार में संरक्षणवाद को अस्वीकार करना, समस्त राज्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली का पुनर्गठन करना और उसके वित्तीय प्रतिष्ठानों का जनवादीकरण करना। मेमोरेंडम में मांग की गयी कि वित्तीय कठिनाइयां अनुभव करनेवाले देशों पर राजनीतिक दवाब डालने और उनके अन्दरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने से सम्बन्धित व्यवहार का अन्त किया जाये।

निस्सन्देह, अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों के जनवादीकरण के लिए संघर्ष स्वयं पूंजीवादी व्यवस्था के चौखटे को पार नहीं करता। परन्तु उसकी साम्राज्यवाद विरोधी दिशा इजारेदारियों की गतिविधियों और

ट्रांसनेशनल कार्पोरेशनों की नव-उपनिवेशवादी दूरगामी नीति के कार्यान्वयन की सम्भावना को सीमित कर देती है। इसके अलावा, यह संघर्ष साम्राज्यवाद विरोधी एकजुटता को फैलाने और गहन बनाने में मदद देता है।

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों के पुनर्निर्माण का सक्रिय योद्धा गुटनिरपेक्ष आन्दोलन है, जिसका स्वरूप वस्तुगत रूप से साम्राज्यवाद विरोधी है। इस दिशा में आन्दोलन के विकास को बहुत से समाजवादी देश और साथ ही समाजवादी दिशा की ओर उन्मुख सभी राज्य बढ़ावा देते हैं। गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की प्रगतिशील दिशा के कारण साम्राज्यवादी क्षेत्र उसकी पांतों में फूट डालने और आन्दोलन के अन्दर समाजवाद विरोधी, सोवियत विरोधी प्रवृत्तियों को मज़बूत बनाने का निरन्तर प्रयत्न करते रहते हैं।

अधिकांश विकासमान देश यह समझते हैं कि ऐसे प्रयासों की सफलता आन्दोलन के ऐतिहासिक ध्येयों को मूर्त रूप देने में बाधा डालती है और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में उसकी स्वतंत्रता को घटाती है। इसलिए यह कोई संयोग की बात नहीं है कि राष्ट्रीय मुक्ति क्षेत्र के बहुत से देशों में और सर्वप्रथम, समाजवादी दिशा में उन्मुख देशों में मई दिवस समारोहों के दौरान समाजवादी देशों की विदेशनीति, उनकी शान्तिपूर्ण पहलों के समर्थन में नारे लगाये जाते हैं।

विकासमान देशों के व्यापक जनसमुदाय साम्राज्यवाद विरोधी एकजुटता के बढ़ते महत्व को अधिकाधिक अनुभव करते जा रहे हैं। इसका प्रमाण है विकासमान देशों में मई दिवस समारोहों का बढ़ता हुआ जनव्यापी स्वरूप तथा लोकप्रियता।

उन देशों में भी, जहां मई दिवस मनाना असम्भव प्रतीत होता है तथा जहां सत्ता दक्षिणपंथी रेडिकल, तानाशाही हुकूमतों के हाथों में है, इस दिवस पर प्रदर्शन बहुधा महत्वपूर्ण घटनाएं बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, चिली में पिनोचेट ने पहली मई को मेहनतकशों की व्यापक कार्रवाइयों का रास्ता रोकने के लिए हर सम्भव पग उठाये। उसने इस दिवस को सैनिक शासक गुट, श्रम और पूंजी की एकता के प्रतीक में परिणत करने का प्रयत्न किया। १९८० में इस फ़ासिस्ट शासन ने अपने नियंत्रण में केवल एक ही मई दिवस कार्रवाई की अनुमति दी। परन्तु पिनोचेट के मन्सूबों के विपरीत सांटियागो और अन्य नगरों में बहुत बड़े प्रदर्शन हुए।

प्लास्टिक और सीसे की गोलियां, डंडे, अश्रु गैस फैलानेवाले

हथगोले, पानी की प्रचंड बौछार करनेवाले उपकरण मई दिवस प्रदर्शनों के व्यापक होते जाते स्वरूप को अवरुद्ध नहीं कर सकते। चिली की राजधानी सांटियागो में पहली मई १९८४ को ढाई लाख से ज़्यादा लोग मई दिवस सभा में जमा हुए। बहुत से लोगों के हाथों में साल्वाडोर अलेंदे के चित्र थे, वे फ़ासिस्ट विरोधी नारे लगा रहे थे और पिनोचेट से तुरन्त इस्तीफ़ा देने की मांग कर रहे थे। पुलिस के साथ टक्करें हुईं, जिनके दौरान लगभग १०० व्यक्ति घायल हुए तथा १२० से अधिक गिरफ़्तार किये गये।

१९८३ में उरुग्वे में प्रतिक्रियावादी सैनिक हुकूमत मोंटेविडियो में मई दिवस प्रदर्शन को नहीं रोक सकी, जिसमें दो लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। इस प्रदर्शन ने जन-आन्दोलन को ऊपर नये स्तर पर पहुंचाया। अगले वर्ष के मई दिवस प्रदर्शन में भाग लेनेवालों की संख्या पिछले वर्ष से दुगुनी थी। और नवम्बर १९८४ में उरुग्वे में सैनिक तानाशाही का अन्त हो गया।

पराग्वे में स्ट्रोएस्सनेर की ३२ वर्षों की खूनी तानाशाही के दौरान पहली बार १९८६ में मेहनतकशों ने विशाल प्रदर्शन में भाग लेकर मई दिवस समारोह मनाया, जिसमें पुलिस के साथ जबर्दस्त टक्करें हुईं। राजधानी के केन्द्र में एक विशाल सभा हुई।

अतः, सामाजिक मुक्ति की विश्वव्यापी प्रक्रिया की समकालीन मंज़िल में उस लक्ष्य की मुख्यतया सिद्धि हो चुकी है, जो दूसरे इंटरनेशनल ने अपने ज़माने में निर्दिष्ट किया था। एक ही दिन — पहली मई — को अधिकांश देशों के मेहनतकश साम्राज्यवाद के विरुद्ध, शान्ति, राष्ट्रीय स्वाधीनता, जनवाद, सामाजिक प्रगति के हेतु संयुक्त संघर्ष में अपनी एकता तथा अन्तर्राष्ट्रीय एकजुटता प्रदर्शित करते हैं।

अध्याय ३

अभी बहुत विलंब नहीं हुआ है

१. साम्राज्यवाद—युद्ध के बढ़ते हुए ख़तरे का स्रोत

मई दिवस, उसके नारों तथा आह्वानों का कभी भी जड़ीभूत स्वरूप नहीं रहा। उन्होंने सदैव भिन्न-भिन्न मंज़िलों में अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर आन्दोलन के मुख्य कार्यभारों को प्रतिबिम्बित किया। नौवां दशक भी अपवाद नहीं था, जिसके आरम्भ में अमरीका के नेतृत्व में साम्राज्यवादी राज्यों की विदेशनीति में एकाएक मोड़ आया। दिसम्बर १९७९ में नाटो ने पांच पश्चिमी यूरोपीय देशों में प्रथम प्रहारकारी नये अमरीकी नाभिकीय मिसाइल लगाने का निर्णय किया था। इसमें तनाव-शैथिल्य को ध्वस्त करने, हथियारों की होड़ तेज़ करने, समाजवादी देशों पर सैनिक श्रेष्ठता प्राप्त करने की नीति पूर्णत: उजागर हुई।

संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के अनुसार ४० युद्धोत्तर वर्षों में हथियारों की होड़ पर १२० खरब डालर व्यय किये गये। यह रक़म ७ करोड़ मानव को मौत के घाट उतारनेवाले दो विश्वयुद्धों में सभी देशों को हुई वित्तीय हानि से तिगुना है।

प्रत्येक दिन हथियारों की होड़ ३ अरब डालर निगल जाती है और प्रत्येक दिन भूख और सामान्य बीमारियों से ४० हज़ार बच्चे मरते हैं। पृथ्वी के हर एक लाख निवासियों के पीछे ५५६ सैनिक और सिर्फ़ ८५ चिकित्सक हैं। एक आधुनिक नाभिकीय बमवर्षक की क़ीमत दुनिया के सभी नवजातों को टीका लगाने के लिए आवश्यक धनराशि से कहीं ज़्यादा है।

साथ ही १३ मुख्य पूंजीवादी देशों से सम्बन्धित सामग्री का पिछले बीस वर्षों में जो विश्लेषण किया गया है उससे स्पष्ट है कि सैनिक व्यय के आकार और आर्थिक-सामाजिक विकास के प्रमुख सूचकांकों के बीच उलटा सम्बन्ध है। सैनिक व्यय में एक प्रतिशत की वृद्धि से समग्र राष्ट्रीय उत्पाद औसतन ०.५८ प्रतिशत घटता है। मगर सैनिक बजटों को वर्तमान

स्तर पर रहने देने से ही, जिसका प्रस्ताव सोवियत संघ ने कई बार किया है, दुनिया की आर्थिक प्रगति की सालाना रफ़्तार कम से कम २ प्रतिशत बढ़ जायेगी।

यह है तीसरी सहस्राब्दी की दहलीज़ पर खड़ी मानवजाति के अस्तित्व का कटु यथार्थ, जो दृढ़तापूर्वक नाभिकीय अस्त्रों का उन्मूलन करने और मानवजाति को बचाने हेतु सक्रिय संघर्ष का तक़ाज़ा करता है।

तमाम नेकदिल लोगों के लिए शान्ति की रक्षा करने, साम्राज्यवाद की मानवद्वेषी योजनाओं को विफल बनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्यभार और कोई नहीं है। शान्ति के लिए संघर्ष में एकजुटता इस कार्यभार के समाधान के वास्ते सबसे अधिक कारगर, विश्वसनीय साधन है। "विभिन्न देशों के मज़दूर वर्ग की ऐक्यबद्धता को अन्ततः जनगण के बीच युद्धों को असम्भव बना देना चाहिए"* —मार्क्स का यह निष्कर्ष आज जितने तात्कालिक महत्व का पहले कभी नहीं था। इसके अलावा भूमंडलीय ख़तरे ने मज़दूर वर्ग तथा उसके संगठनों को युद्धविरोधी संघर्ष में मज़दूर आन्दोलन के तमाम दस्तों की एकता को सुदृढ़ बनाने का महत्व समझने के लिए बाध्य कर दिया है, परन्तु उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इतना ही काफ़ी नहीं है। सुदृढ़ शान्ति विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक शक्तियों के सक्रिय, संयुक्त प्रयासों से ही हासिल की जा सकती है।

शान्तिप्रिय शक्तियों की एकजुटता एकमात्र सही, याने साम्राज्यवाद विरोधी दिशा अपना सके, इसके लिए जनगण के समक्ष विश्वसनीय ढंग से यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि नौवें दशक में घटनाओं के ख़तरनाक मोड़ के लिए दोषी कौन है।

वाशिंगटन और नाटो देशों की दूसरी राजधानियों में सैन्यवाद के विचारधारानिरूपक सत्य से उत्पन्न ख़तरे को समझते हैं और इसलिए वे तनाव-शैथिल्य तथा सहयोग के सिद्धान्तों से आठवें तथा नौवें दशकों के संधिकाल में अमरीका और उसके कतिपय अन्य साथियों द्वारा एकाएक मुंह फेर लिये जाने के बारे में एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाते हुए मिथक फैला रहे हैं, जिन्हें "सोवियत ख़तरे के अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाने" के आरोपों का सहारा दिया जाता है। अगर बहुत ही हुआ, तो वे अन्तर्राष्ट्रीय तनाव के अत्यन्त तीक्ष्ण होने के लिए अमरीका की

---

* का० मार्क्स, 'शान्ति एवं स्वतंत्रता लीग की कांग्रेस के प्रति अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर संघ के रवैये' के बारे में भाषण, १८६७।

ज़िम्मेवारी को मानने के वास्ते तैयार हैं, परन्तु केवल इस शर्त पर कि ऐसी ही ज़िम्मेवारी सोवियत संघ भी ग्रहण करे।

इस में ही इस वाद-विवाद का स्रोत निहित है कि शान्ति तभी अधिक स्थिर होगी, जब "दो महाशक्तियां" संसार पर प्रभाव डालने की अपनी प्रतिद्वन्द्विता बन्द कर देंगी। परन्तु सोवियत संघ अपने को न तो दूसरे राज्यों तथा जनगण के ऊपर रखने का और न उनपर अपना हुक़्म चलाने, अपनी इच्छा थोपने का प्रयत्न कर रहा है। सोवियत संघ किसी भी तरह की प्रतिद्वन्द्विता — मंडियों के लिए अथवा प्राकृतिक संसाधनों के लिए, आकाशीय मार्गों पर अथवा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण के लिए या बाह्य अन्तरिक्ष पर कब्ज़ा करने के लिए प्रतिद्वन्द्विता — में भाग नहीं ले रहा है।

बेशक, सोवियत संघ संसार की दो सबसे ताक़तवर शक्तियों में से एक है। पर सवाल तो यह है कि यह ताक़त किन राजनीतिक ध्येयों की सिद्धि करती है। जो लोग "दो महाशक्तियां" सम्बन्धी सिद्धान्त की चर्चा करते हैं, उन्हें कभी-कभी इसपर ग़ौर करना चाहिए कि यदि सोवियत संघ कमज़ोर होता और सोवियत जनता ने अपने देश की आर्थिक तथा सैनिक क्षमता को आवश्यक स्तर पर क़ायम रखने में श्रम, भौतिक साधनों तथा वैज्ञानिक चिन्तन के रूप में अपना इतना योगदान न किया होता, तो बहुत से स्वतंत्र देशों और साथ ही सामान्यतया विश्व का क्या हाल हुआ होता।

साम्राज्यवाद की विदेश नीति में ख़तरनाक मोड़ उससे कहीं अधिक गहन तथा गंभीर स्वरूप का था, जितना सैनिक-औद्योगिक समुच्चय के पैरवीकार जनसाधारण के समक्ष चित्रित करने का प्रयास करते हैं। आठवें दशक के अन्त तक साम्राज्यवादी देशों के शासक क्षेत्रों के अन्दर, लेनिन के शब्दों में, "घोर बुर्जुआ, आक्रामक बुर्जुआ, प्रतिक्रियावादी बुर्जुआ"* शिविर तथा उन पूंजीपतियों के बीच अन्तर्विरोध अत्यन्त तीक्ष्ण हो गये थे, जिनका विश्व में नये शक्ति-सन्तुलन को ध्यान में रखने की ओर अधिक झुकाव है, जिनकी विश्व आर्थिक सहयोग में दिलचस्पी है। टकराव में पहल सर्वाधिक आक्रामक सैनिक-औद्योगिक ग्रुपों की ओर से की गयी। अमरीका में ऐसी स्थिति बनती जा रही थी, जिसमें सरकार शस्त्रास्त्र-उत्पादन को नियंत्रित नहीं करती थी, अपितु शस्त्रास्त्र-उत्पादन सरकार को नियंत्रित करता था।

"शस्त्रास्त्रों में पिछड़ेपन" के बारे में, "सोवियत ख़तरे"

---

* व्ला० इ० लेनिन, गेनोआ में सोवियत शिष्टमंडल के कार्यभारों के सम्बन्ध में रू० क० पा० (बो०) की केन्द्रीय समिति के निर्णय का मसविदा, २४ फ़रवरी, १९२२।

के बारे में भयाक्रान्त चीत्कारों की आड़ लेकर अमरीकी सैनिक-औद्योगिक समुच्चय ने १९४५ और १९८० के बीच करदाताओं की जेब से दस खरब डालर खसोट लिये। फिर १९८० और १९८५ के बीच उसने १० खरब डालर और वसूल किये। और अब वह "तारक युद्ध" प्रोजेक्ट से खरबों की नयी राशि हड़पने के लिए तैयार है और इस तरह आनेवाले ३० वर्षों में अपने लिए अति मुनाफ़ों की गारंटी कर रहा है। सैनिक इजारेदारियों से "सामरिक रक्षा पहल" से नाता तोड़ने के लिए कहने का अर्थ होगा वाल स्ट्रीट को विस्फोट से ध्वस्त करने की अनुमति मांगना। साम्राज्यवाद कई कारणों से सैनिक-औद्योगिक समुच्चय पर निर्भर करता है।

पहला, पूंजीवाद की आर्थिक प्रणाली के संकट की पृष्ठभूमि में समाजवादी देशों की आर्थिक तथा सामाजिक-राजनीतिक स्थितियों का दृढ़ीकरण हुआ है, उनकी आकर्षण-शक्ति में वृद्धि अत्यधिक ज्वलंत होती जा रही है। इसी कारण सत्ताधारी साम्राज्यवादी क्षेत्र यह बात अधिकाधिक समझने लगे हैं कि विश्व समाजवाद को "ढीला" करने के लिए तनाव-शैथिल्य के उपयोग पर उनकी आशाएं मृग-मरीचिका हैं।

तनाव-शैथिल्य को इकतरफ़ा मार्ग जैसी चीज़ मानते हुए, जिसका मानो केवल समाजवादी देश अपने हितार्थ उपयोग करते हैं, "तनाव-शैथिल्य विरोध" के पक्षधरों ने बलात लादी गयी हथियारों की दौड़, नये क्षेत्रों में उसके प्रारम्भ, भांति-भांति के प्रतिबन्धों तथा निषेधों के कार्यान्वयन, परस्पर विरोधी सामाजिक प्रणालियोंवाले देशों के बीच आर्थिक सम्बन्धों के परिसीमन की सहायता से उनकी अर्थव्यवस्थाओं को कमज़ोर बनाने की योजनाएं बनायी हैं।

दूसरा, साम्राज्यवादी राज्यों के शासक क्षेत्र बढ़ती बेरोज़गारी, सामाजिक आवश्यकताओं पर व्ययों में तीक्ष्ण कटौतियों की परिस्थितियों में मज़दूर आन्दोलन से उत्पन्न होनेवाले ज़बर्दस्त ख़तरे को भली-भांति समझते हैं।

साम्राज्यवादी देशों के सत्ताधारी क्षेत्र अर्थव्यवस्था के सैन्यीकरण तथा शस्त्रीकरण की होड़ को "ऊपर से" वर्ग-संघर्ष चलाने के एक तरह के औज़ार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। साम्राज्यवाद तथा विश्व समाजवाद के बीच विचारधारात्मक-राजनीतिक मुक़ाबलेबाज़ी को तीक्ष्ण बनाते हुए, उसके कारणों को विकृत करते हुए वे "पूरब से बढ़ते ख़तरे" के सामने पूंजीवादी समाज के तमाम वर्गों तथा श्रेणियों की एकता की आवश्यकता के विचार का प्रचार करते हैं। यह चीज़ उन्हें

मज़दूर तथा जनवादी आन्दोलनों पर प्रहार करने के लिए, शान्तिप्रिय शक्तियों का दमन बढ़ाने के लिए बहाने मुहैया करती है।

इसके अलावा साम्राज्यवादी शिविर में प्रभावशाली शक्तियां इस बात से भली-भांति अवगत हैं कि "युद्ध के ख़तरे" की मनोदशा का वातावरण केवल टुटपुंजिया तत्त्वों में ही नहीं, अपितु कुछ हद तक मज़दूर वर्ग में भी अन्धराष्ट्रवादी तथा राष्ट्रवादी भावनाओं को पोषित करता है। और यह सर्वहारा एकजुटता बढ़ाने में सहायक नहीं होता।

तीसरा, विकासमान देशों में चल रही प्रक्रियाएं बुर्जुआ नेताओं के बीच चिन्ता बढ़ाती हैं। भूतपूर्व उपनिवेशों तथा भूतपूर्व पराधीन देशों से कच्चे माल पर पूंजी के दुर्गों की बढ़ती निर्भरता की परिस्थितियों में एशिया, अफ़्रीका तथा लैटिन अमरीका में साम्राज्यवाद विरोधी कार्रवाइयों में आम वृद्धि ने विकसित पूंजीवादी देशों की, जो असमानताभरे आर्थिक सम्बन्धों को मज़बूती से क़ायम रखने का प्रयास कर रहे हैं, आर्थिक मशीनरी की क्रियाशीलता में सारभूत कठिनाइयों के पैदा होने का ख़तरा पेश कर दिया है।

दक्षिण-पूर्वी एशिया में अमरीका आक्रामकता की विफलता, औपनिवेशिक प्रणाली का अन्तिम रूप से ढह जाना, राष्ट्रीय मुक्ति के क्षेत्र में समाजवादोन्मुख दिशावाले देशों का उद्‌भव—इस सबको साम्राज्यवाद के दुस्साहसिकतावादी क्षेत्र तनाव-शैथिल्य के "हानिप्रद" प्रभाव से जोड़ते हैं।

चौथा, विश्व साम्राज्यवाद के गढ़—अमरीका—के आक्रामक क्षेत्र कथित "सोवियत सैनिक ख़तरे" का अपने साथी-देशों को इस बात का कायल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि वे सैनिक उद्देश्यों पर विशाल धनराशियां ख़र्च करें, हालांकि इससे उनकी अर्थव्यवस्थाएं कमज़ोर होंगी और विश्व पूंजीवादी मंडी में जापानी तथा पश्चिम यूरोपीय प्रतियोगियों की राह में बाधाएं खड़ी होंगी। राजनीतिक दबाव डालने के लिए इस तनाव का उपयोग अपने साथी देशों को वाशिंगटन का अधिक आज्ञाकारी बनाने , उन्हें उसकी हुक्मशाही के अधीन करने में कोई कम भूमिका अदा नहीं करता।

पांचवां, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बार-बार संकट कतिपय बड़े इजारेदारी कार्पोरेशनों के अस्तित्व को ही ख़तरे में डाल देता है, जो उनके मालिकों को कभी-कभी दिवालियापन के मुंह में पहुंचा देते हैं। उपभोक्ता वस्तुएं मुहैया करनेवाली इजारेदारियों के प्रतिनिधियों की दिलचस्पी बुनियादी तौर पर इस बात में होती है कि अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक

सम्बन्धों का विकास हो, तनाव-शैथिल्य का विस्तार हो, जनसाधारण की क्रय शक्ति का उच्च स्तर बना रहे। परन्तु आज के हालात में वे भी युद्ध उद्योग को ललचायी नज़रों से देखने लगे हैं। आखिरकार, कतिपय परिस्थितियों के अन्तर्गत सैनिक प्रतिष्ठानों में मुनाफ़े असैनिक प्रतिष्ठानों से मिलनेवाले मुनाफ़ों से कहीं ज्यादा होते हैं। और ये "कतिपय" परिस्थितियां ही सैनिक-औद्योगिक समुच्चय तथा उनकी सेवा करनेवाली ऐसी राजनीतिक शक्तियों का निर्माण कर सकती हैं और वस्तुत: निर्माण करती हैं, जो "तोपों के बादशाह" अल्फ़ेड क्रुप्प द्वारा पहले विश्वयुद्ध से पहले ही, कैसर के ज़माने में ही दिये गये इस निर्देश का कड़ाई से पालन करती हैं: प्रत्येक फ़र्म को अपने उत्पादों की मांग स्वयं पैदा करनी चाहिए।

सैनिक उत्पादों की मांग कई बातों के कारण बढ़ती है। ये हैं: अन्तर्राष्ट्रीय तनावों का तीक्ष्ण होना; युद्धोन्माद; "पूरब से ख़तरे" के बारे में, "सोवियत सैनिक श्रेष्ठता" के बारे में मनगढ़न्त बातों का व्यापक पैमाने पर प्रचार; प्रादेशिक टकरावों की आग भड़काना, आदि। ठीक तभी हथियारों तथा बारूद की मांग बढ़ती है, उसी तरह उनकी क़ीमतें बढ़ती हैं और इस प्रकार अति मुनाफ़े सुनिश्चित होते हैं। इसी कारण असैनिक तथा "मिश्रित" फ़र्मों में सैन्यीकरण मालिकों के लिए केवल प्रलोभन ही नहीं है, अपितु कई मामलों में दिवालियेपन से बचने का एक ही रास्ता भी है। ये मालिक भी जल्द ही नयी दिशा में मोड़े गये अपने प्रतिष्ठानों के उत्पादों के लिए मांग पैदा करने में लग जाते हैं। और अन्तत: इसका परिणाम बुर्जुआ वर्ग के अन्दर शक्ति-सन्तुलन में परिवर्तन होता है।

ट्रांसनेशनल कार्पोरेशन सैनिक उद्योगों के उत्पादों के लिए मांग पैदा करने में विशेष कारगर ढंग से योगदान करते हैं। इनमें से वे कार्पोरेशन, जो सैनिक-औद्योगिक समुच्चय के अभिन्न अंग हैं, अपनी वस्तुत: अपरदेशीय स्थिति का उपयोग करते हुए अक्सर पृथक-पृथक देशों तथा जनगण के बीच तरह-तरह की टक्करों, शत्रुता तथा घृणा की आग भड़काते हैं, उन्हें हथियारों की होड़ के भंवर में धकेल देते हैं। साथ ही ट्रांसनेशनल कार्पोरेशनों को अपने फ़ौजी उत्पादों की व्यवहार में जांच-परख करने का मौक़ा मिल जाता है।

आठवें दशक तथा नौवें दशक के संधिकाल में साम्राज्यवाद की अन्तर्राष्ट्रीय नीति में तेज़ी से आया मोड़ अत्यन्त विनाशकारी स्वरूप का था। आधुनिक शस्त्रास्त्रों की विशिष्टता को देखते हुए तकनीकी दृष्टि

से सर्वाधिक समुन्नत सैनिक प्रतिरक्षा तक राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी नहीं की जा सकती। नाभिकीय युद्ध की तो बात ही क्या, आज शस्त्रास्त्रों की होड़ तक में विजयी होना उसम्भव है। पृथ्वी पर शस्त्रास्त्रों की होड़ को जारी रखने और उसे अन्तरिक्ष तक पहुंचाने से नाभिकीय तथा अन्य प्रकार के हथियारों का केवल अम्बार लगेगा और उनका आधुनिकीकरण होगा। इसके फलस्वरूप बराबरी सैनिक-राजनीतिक परिरोधन में मुख्य कारक नहीं रह जाती। इस कारण सुरक्षा सुनिश्चित करना अब अधिकाधिक राजनीतिक कार्यभार बनता जा रहा है, जिसका समाधान केवल राजनीतिक साधनों से ही सम्भव है।

हमारी शताब्दी में साम्राज्यवाद और केवल साम्राज्यवाद ही युद्धों तथा टकरावों के लिए, हथियारों की होड़ भड़काने, उसे आगे बढ़ाने, उसके लिए नयी दिशाओं के द्वार खोलने के लिए ज़िम्मेवार है। परन्तु पृथ्वी पर अपना अस्तित्व क़ायम रखने की आवश्यकता विभिन्न देशों के जनगण को संयुक्त कार्रवाइयां करने के लिए बाध्य कर रही है। विश्व घटना-प्रवाह ने इसके लिए आवश्यक भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक पूर्वाधारों का निर्माण कर दिया है।

इसी कारण सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम के नये संस्करण में कहा गया है: "मानवजाति के सिर के ऊपर मंडरा रहे ख़तरे के बादल पहले कभी इतने भयावह नहीं थे। परन्तु शान्ति की रक्षा करने और उसे मज़बूत बनाने की सम्भावनाएं भी पहले कभी इतनी वास्तविक नहीं थीं। अपने प्रयासों को एकजुट कर जनगण नाभिकीय सर्वनाश के ख़तरे को टाल सकते हैं और उन्हें उसे टालना चाहिए।

"साम्राज्यवाद की आक्रामक नीति का शान्ति की बढ़ती क्षमता से मुक़ाबला किया जा रहा है। इसका अर्थ है समाजवादी राज्यों की सक्रिय, सुसंगत शान्तिप्रिय नीति और उनकी बढ़ती हुई आर्थिक तथा प्रतिरक्षात्मक शक्ति। इसका अर्थ है एशिया, अफ़्रीका और लैटिन अमरीका के राज्यों की भारी बहुसंख्या की नीति, जिनकी शान्ति की रक्षा करने और हथियारों की होड़ ख़त्म करने में बुनियादी रुचि है। इसका अर्थ है समस्त महाद्वीपों में व्यापकतम जनसमुदायों के युद्धविरोधी आन्दोलन, ऐसे आन्दोलन, जो सामाजिक जीवन में दीर्घकालीन तथा प्रभावशाली कारक बन गये हैं। शक्तियों के वास्तविक सहसम्बन्धों के संजीदा मूल्यांकन के फलस्वरूप पूंजीवादी राज्यों के बहुत से राजनीतिक नेता भी हथियारों की होड़ की निरन्तरता तथा प्रसार के ख़तरे को समझने लगे हैं।

"सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी यह मानकर चलती है कि साम्राज्यवाद के आक्रामक क्षेत्रों की नीति शान्ति के लिए चाहे कितना ही बड़ा ख़तरा पैदा क्यों न करे, **विश्वयुद्ध नियतिनिर्दिष्ट नहीं है। युद्ध टालना तथा मानवजाति को महाविपदा से बचाना सम्भव है। यह है समाजवाद का, हमारी पृथ्वी की समस्त प्रगतिशील तथा शान्तिप्रिय शक्तियों का ऐतिहासिक मिशन।**"

यह बात अधिकाधिक स्पष्ट होती जा रही है कि युद्ध के पथ पर बुद्धिमत्तापूर्ण समाधान नहीं मिल सकते। अब, जबकि नाभिकीय शस्त्रास्त्रों के विशाल ज़खीरे जमा हो चुके हैं और विशेषज्ञों में केवल इस बारे में वाद-विवाद हो रहा है कि उनके ज़रिये मानवजाति को कितनी बार या कितनी दसियों बार नष्ट किया जा सकता है, शायद समय आ चुका है कि युद्ध के कगार पर सन्तुलन से, भय के सन्तुलन से दो प्रणालियों के राज्यों के बीच पारस्परिक सम्बन्धों के सामान्य सभ्यतापूर्ण रूपों में व्यावहारिक ढंग से संक्रमण किया जाये। इसलिए भिन्न-भिन्न महाद्वीपों में मई दिवस के नारों के बीच अधिकाधिक ऐसे नारे सुनने को मिल सकते हैं, जो शान्ति के लिए संघर्ष करने का, समस्त शान्तिप्रिय शक्तियों के एकीकरण का आह्वान करते हैं।

२. समाजवाद शान्तिप्रिय शक्तियों की अग्रिम पांत में

"समस्त देशों के लोगो! युद्ध के ख़तरे के विरुद्ध, हथियारों की होड़ रोकने और सार्विक अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली के निर्माण के लिए लड़ो!"; "विश्व के लोगो! साम्राज्यवाद की ओर से उत्पन्न नाभिकीय युद्ध के ख़तरे का सक्रियतापूर्वक मुक़ाबला करो! नाभिकीय परीक्षणों को पूरी तरह रोकने के लिए प्रयास करो!"; "हम अन्तरिक्ष का सैन्यीकरण नहीं होने देंगे!"; "एशियाई देशों के लोगो! एशिया और प्रशान्त महासागरीय प्रदेश में सुरक्षा, सद्भावना तथा सहयोग के लिए संघर्ष में प्रयासों को एकजुट करो!"; "यूरोप के लोगो! राज्यों के बीच शान्तिपूर्ण सहयोग, अच्छे पड़ोसियों जैसे सम्बन्धों के लिए, तनाव-शैथिल्य के लिए तथा महाद्वीप में सुरक्षा की विश्वसनीय प्रणाली के निर्माण के लिए लड़ो!"; "संसार के लोगो! आक्रामकता तथा हिंसा

की साम्राज्यवादी नीति के विरुद्ध संकल्पपूर्वक लड़ो! फ़ौजी ख़तरे के स्रोतों को मिटाने के लिए प्रयास करो!"—इन नारों के साथ समाजवादी देशों के जनगण, जो शान्ति के लिए संघर्ष की अग्रिम पांत में हैं, मई दिवस प्रदर्शनों में भाग लेते हैं।

निस्सन्देह, मानवजाति को बचाने की आवश्यकता से न तो पूंजीवाद एवं समाजवाद के अन्तर्विरोध ख़त्म हो जाते हैं, न ही वर्ग-संघर्ष के वस्तुगत नियम अपना काम बन्द कर देते हैं। परन्तु समाजवाद के ऐतिहासिक मिशन का तक़ाज़ा है कि वह युद्ध की विपदाओं और ज़ोर-ज़बरदस्ती से मानवजाति की रक्षा, सभी राष्ट्रों की सुरक्षा एवं न्यायपूर्ण शांति हेतु संघर्ष की अगुआई करे। हालांकि विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं के बीच प्रतिस्पर्द्धा अवश्यंभावी है, समाजवादी व्यवस्था की मानवता इसमें प्रकट होती है कि वह इस प्रतिस्पर्द्धा में से सैनिक तत्त्व को, जो महाविनाश ला सकता है, सदा के लिए बाहर करने और सभी राष्ट्रों के हित में सहयोग बढ़ाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहती है।

नये चिन्तन पर आधारित समाजवादी जगत की विदेश नीति और बदल रहे यथार्थ को समझने में साम्राज्यवादी राज्यों की अक्षमता के बीच अन्तर्विरोध आधुनिक काल का एक प्रमुख अन्तर्विरोध है। वे अभी अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों की बलि देने, सैनिक श्रेष्ठता हासिल करने और किसी भी समय युद्ध छेड़ने के लिए तैयार रहने की कोशिश नहीं छोड़ते। पुराने चिन्तन के इन सभी अवशेषों को नये चिन्तन पर आधारित समाजवादी देशों की नीति, उनकी व्यावहारिक पहलों और सबके हित में समझौतों के लिए उनकी तत्परता द्वारा ख़त्म किया जाना चाहिए।

शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व के लेनिनीय सिद्धान्त का अडिगतापूर्वक तथा सुसंगत पालन वह आधारशिला है, जिसपर समाजवादी देश पूंजीवादी देशों के साथ अपने सम्बन्ध का निर्माण करते हैं। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम के नये संस्करण में कहा गया है: "शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति, जिस तरह उसे सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी समझती है, इन बातों की पूर्वकल्पना करती है—युद्ध, विवादास्पद प्रश्नों के समाधान के रूप में बल-प्रयोग का अथवा उसकी धमकी का परित्याग करना और ऐसे प्रश्नों का बातचीत के ज़रिये समाधान करना; आन्तरिक मामलों में अहस्तक्षेप तथा एक दूसरे के जायज़ हितों का ध्यान रखना; अपने भाग्य का स्वतंत्र रूप से निर्णय करने के जनगण का अधिकार; राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय

अखण्डता का कड़ाई के साथ आदर और उनकी सीमाओं की अनुल्लंघनीयता; पूर्ण समानता तथा पारस्परिक लाभ के आधार पर सहयोग; अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून के सर्वमान्य सिद्धान्तों तथा प्रतिमानों से और सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय संधियों से उत्पन्न दायित्वों की शुद्ध अन्त:करण से परिपूर्ति।"

समाजवादी देश शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व को महज़ युद्ध न होना नहीं मानते। राज्यों के बीच अच्छे पड़ोसी जैसे सम्बन्ध तथा सहयोग; विज्ञान और तकनीक की उपलब्धियों, विश्व संस्कृति के मूल्यों का व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय; सैनिक आवश्यकताओं पर अनुत्पादक ढंग से ज़ाया होनेवाले विशाल संसाधनों को अकाल, ग़रीबी, रोगों के विरुद्ध संघर्ष जैसी भूमंडलीय समस्याओं के समाधान पर लगाना—ये हैं इसके पहलू।

सोवियत जनों को इस तथ्य पर अत्यधिक संतोष है कि ठीक सोवियत संघ ने ही विश्व को वर्तमान शताब्दी के अन्त तक नाभिकीय शस्त्रास्त्रों से छुटकारा दिलाने का आमूलगामी कार्यक्रम प्रस्तुत करने में पहल की थी। मिखाईल गोर्बाचोव का १५ जनवरी, १९८६ का वक्तव्य, सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की २७वीं कांग्रेस में पार्टी की केन्द्रीय समिति की राजनीतिक रिपोर्ट में विदेशनीति सम्बन्धी पहलक़दमियां, कांग्रेस के बाद सोवियत संघ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव—ये सब लोगों के हृदय में नयी आशा पैदा करते हैं।

सोवियत संघ और अन्य समाजवादी देशों की शान्तिपूर्ण पहलक़दमियां यथार्थपरक हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य सोवियत संघ, उसके साथी देशों और मित्रों के लिए किसी तरह की एकतरफ़ा श्रेष्ठता प्राप्त करना नहीं है और वे समस्त संसार के जनगण के हितों से मेल खाती हैं। ये पहलक़दमियां अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा की एक सर्वग्राही प्रणाली के, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा के आज के तमाम पहलू—सैनिक, राजनीतिक, आर्थिक और मानवीय पहलू—शामिल हों, निर्माण के बारे में २७वीं पार्टी कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम के पूर्णत: अनुरूप हैं।

सैनिक क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा की सर्वग्राही प्रणाली के निर्माण के कार्यक्रम में विशेष रूप से इस बात की पूर्वकल्पना की गयी है कि नाभिकीय शक्तियां एक दूसरे के विरुद्ध अथवा तीसरे राज्यों के विरुद्ध नाभिकीय और आम, दोनों तरह के युद्ध करने से इन्कार करेंगी, अन्तरिक्ष में शस्त्रास्त्रों की होड़ नहीं होने दी जायेगी, समस्त नाभिकीय शस्त्रास्त्रों के परीक्षण बन्द कर दिये जायेंगे और उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया

जायेगा, रासायनिक शस्त्रास्त्र निषिद्ध तथा नष्ट कर दिये जायेंगे, आदि।

राजनीतिक क्षेत्र में इस प्रणाली में इस बात की व्यवस्था की गयी है कि संप्रभुता तथा स्वतंत्र विकास के प्रत्येक जनगण के अधिकार का बिना शर्त सम्मान किया जायेगा; राज्यों के बीच विश्वास मज़बूत बनाया जायेगा; बाहर से आक्रमण के विरुद्ध तथा सीमाओं की अनुल्लंघनीयता के लिए पक्की गारंटियां की जायेंगी; अन्तर्राष्ट्रीय आतंक रोकने के लिए कारगर पग उठाये जायेंगे।

आर्थिक सुरक्षा की नींव का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि उसका अर्थ हर तरह के भेदभाव, नाकाबन्दी या प्रतिबन्धों से इन्कार करना, ऋणों की समस्या का न्यायपूर्ण ढंग से समाधान करना तथा एक नयी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना है।

मानवीय क्षेत्र में इस बात की अपेक्षा की जाती है कि वस्तुगत सूचना का विनिमय किया जाये, जो जनगण को एक दूसरे के जीवन से परिचित होने में मदद दे, पारस्परिक समझ तथा मैत्री को सुदृढ़ बनाया जाये, जनसंहार और पृथग्वासन को, फ़ासिज़्म के प्रसार को, नस्लवाद, राष्ट्रीय अथवा धार्मिक अनन्यता को मिटाया जाये तथा सहयोग के महत्वपूर्ण कार्यभार का समाधान किया जाये।

सोवियत संघ अच्छी तरह समझता है कि विश्वव्यापी सुरक्षा की प्रणाली एकाएक, बनी-बनायी और एक ऐसी कृत्रिम संरचना के रूप में नहीं पैदा हो सकती, जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों और विषमताओं के विद्यमान व्यवहार पर लागू हो सके। यह स्थिर नहीं, बल्कि गतिशील प्रणाली है। उसकी गतिशीलता राज्यों के समुदाय के सोद्देश्य कार्यों पर निर्भर है। कोई भी देश अथवा देशों का कोई भी समूह ऐसी प्रणाली का एकमात्र निर्माता होने का दावा नहीं कर सकता। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय ध्येय है जो समय और संयुक्त प्रयत्नों की अपेक्षा करता है।

इस सिलसिले में नाभिकीय अस्त्रों और हिंसा से मुक्त संसार के मूलाधारों के बारे में नवम्बर १९८६ में राजीव गांधी और मिखाईल गोर्बाचोव द्वारा हस्ताक्षरित दिल्ली घोषणापत्र का महत्व अद्वितीय है। वास्तव में उसका महत्व दोपक्षीय सम्बन्धों के दायरे से कहीं ज़्यादा व्यापक है, क्योंकि वह सभी राष्ट्रों और सरकारों को संबोधित करता है। इस घोषणापत्र के सिद्धान्त नये प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की नैतिक और राजनीतिक बुनियाद हैं। इसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि मानवजाति की भौतिक और बौद्धिक क्षमता को विश्वव्यापी समस्याओं

के समाधान के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, कि बुद्धिमत्ता इस बात में है कि इन समस्याओं में वृद्धि न होने दी जाये, अन्यथा कल वे और बलिदानों की मांग करेंगी। घोषणापत्र में बताया गया है कि मानव संसार की सबसे बड़ी सम्पदा है, मानव की सृजनात्मक प्रतिभा ही शान्ति की परिस्थितियों में प्रगति की प्रेरक शक्ति होती है।

जुलाई १९८७ में बर्लिन में हुई वार्सा सन्धि संगठन की राजनीतिक परामर्शकारी समिति की बैठक में स्वीकृत वार्सा सन्धि के सदस्य-देशों के सैनिक सिद्धान्त से सम्बन्धित दस्तावेज़ इस बात का ज्वलंत प्रमाण है कि अपनी नयी सामाजिक व्यवस्था की प्रकृति के कारण ही समाजवादी देशों ने कभी अपना भविष्य विश्व समस्याओं के सैनिक समाधान से नहीं जोड़ा और अब भी नहीं जोड़ते हैं। इस दस्तावेज में प्रभावी ढंग से दिखाया गया है कि समाजवाद की दूरगामी नीति का स्वरूप प्रतिरक्षात्मक है। ऐसे स्वरूप की न केवल घोषणा की गयी है बल्कि नाभिकीय अस्त्रों के उपयोग में पहल करने से इन्कार द्वारा, आम तौर पर सैनिक कार्रवाइयां शुरू करने में पहल न करने की आश्वासन द्वारा और सैनिक नियोजन और निर्माण में सैनिक साधनों की विवेकसंगत पर्याप्तता के सिद्धान्त का अनुकरण करने द्वारा इसकी व्यावहारिक पुष्टि भी की गयी है। इस दस्तावेज़ में नया राजनीतिक चिन्तन व्यक्त हुआ है, जिसे समाजवादी देश अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के ताने-बाने में इतने आग्रह से समाविष्ट कर रहे हैं।

समाजवादी देश साम्राज्यवाद के आक्रामक हल्क़ों द्वारा पेश किये गये "नाभिकीय निरोधन" के सिद्धान्त को एक झूठी, ख़तरनाक और अनैतिक चीज़ समझकर ठुकराते हैं क्योंकि नाभिकीय अस्त्र सुरक्षा की गारन्टी नहीं हो सकते। उल्टे, देशों के पास जितने अधिक नाभिकीय अस्त्र जमा होते हैं, उतनी ही कम कारगर उनकी सुरक्षा बनती है। मानव विवेक की मांग है कि नयी सहस्राब्दी की दहलीज़ पर आकर संसार अपने को नाभिकीय ज़ंजीरों से मुक्त कर दे। डेढ़ वर्ष तक सोवियत संघ ने कोई नाभिकीय परीक्षण नहीं किया और कई बार संयुक्त राज्य अमरीका से इसका अनुकरण करने का प्रस्ताव किया। सोवियत संघ की इस पहल को विश्व जनमत का व्यापक समर्थन मिला, परन्तु अन्त में सोवियत संघ को नाभिकीय परीक्षण फिर से शुरू करने पड़े, क्योंकि अमरीका अपने नाभिकीय परीक्षण पूर्ववत् जारी हुए था और इससे सोवियत संघ की सुरक्षा को यथार्थ हानि पहुंच सकती थी।

कभी-कभी ऐसा होता है कि सोवियत संघ और दूसरे समाजवादी

देशों की विदेशनीतिक पहलों की नम्यता और रचनात्मकता को पश्चिम अपने कड़े रवैये के सामने उनके झुक जाने का प्रमाण समझता है। परन्तु वास्तव में यह अमरीका और उसके मित्र-देशों के दबाव के सामने पीछे हटना नहीं, बल्कि सहजबुद्धि के तक़ाज़े को पूरा करना है।

नये चिन्तन पर आधारित नयी विदेश नीति फल भी देने लगी है। उदाहरण के लिए, नाभिकीय अस्त्र के दो प्रकारों के उन्मूलन के बारे में दिसम्बर १९८७ में वाशिंगटन में सम्पन्न सन्धि का सारी मानवजाति ने सहर्ष स्वागत किया। पहली बार इस दिशा में ठोस क़दम उठाया गया कि नाभिकीय अस्त्रों का वस्तुत: उन्मूलन हो जाये और नाभिकीय अस्त्रों से मुक्त संसार के निर्माण का प्रारम्भ हो। निस्सन्देह, इस प्रकार की सन्धि सभी राष्ट्रों के बहुवर्षीय प्रयत्नों का फल और सारी मानवजाति की उपलब्धि है, परन्तु इसमें सबसे बड़ा योगदान समाजवादी देशों ने ही किया है। और वाशिंगटन में सोवियत शिष्टमंडल ने अपने सभी संघातियों का प्रतिनिधित्व किया था।

आम सुरक्षा के हितों से प्रेरित होकर और अपनी-अपनी परम्पराओं एवं विशेषताओं को देखते हुए प्रत्येक समाजवादी देश समाजवाद के शान्तिमय प्रयत्नों में अपना योगदान करता है। मिसाल के तौर पर जुलाई १९८७ में पोलैंड की सरकार ने एक स्मरणपत्र छापा जिसमें केन्द्रीय यूरोप में शस्त्रास्त्रों में कमी करने और परस्पर विश्वास बढ़ाने विषयक व० यरुज़ेल्स्की की योजना सविस्तार बतायी गयी थी। जनवादी जर्मनी और चेकोस्लोवाकिया ने मिलकर यह कार्यक्रम पेश किया कि वार्सा सन्धि और नाटो देशों के बीच परमाणु अस्त्रों से मुक्त एक ३०० किलोमीटर चौड़ी पट्टी हो। बुल्गारिया और रूमानिया का संयुक्त प्रस्ताव है कि बाल्कान प्रायद्वीप को नाभिकीय और रासायनिक अस्त्रों से मुक्त क्षेत्र बनाया जाये। रूमानिया का एक और प्रस्ताव यह है कि १-२ वर्ष तक वार्सा सन्धि और नाटो अपने-अपने सैनिक ख़र्चों में कोई वृद्धि न करें।

समाजवादी देशों के विदेश नीति कार्यक्रम ने समस्त शान्तिप्रिय जनों के बहुत से विचारों तथा पहलक़दमियों को ग्रहण किया है। उनका व्यावहारिक कार्यान्वयन बहुत हद तक सामाजिक आन्दोलनों, धाराओं तथा संगठनों पर, युद्ध तथा शान्ति के मूल प्रश्न के बारे में आपसी समझदारी हासिल करने की नाना विचारधारात्मक दृष्टिकोणवाले लोगों की क्षमता पर, उनके सहयोग तथा ठोस संयुक्त कार्यवाहियों पर निर्भर करता है।

समाजवादी देश अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए जो भी सम्भव है , वह करने के लिए तैयार हैं। ऐसा कर सकने के लिए उन्हें

अपने सिद्धान्तों का, अपने आदर्शों का परित्याग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समाजवादी देशों की शान्तिपूर्ण विदेश नीति एक नियमसंगत परिघटना है, जो उनके सामाजिक स्वरूप से पूरी तरह मेल खाती है। जिन देशों में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व का कोई अस्तित्व नहीं है, वहां कोई ऐसे वर्ग, सामाजिक ग्रुप अथवा व्यक्ति नहीं हैं, जिनकी किन्हीं भौतिक, राजनीतिक या विचारधारात्मक कारणों से हथियारों की दौड़ में या अन्तर्राष्ट्रीय तनाव को उग्र बनाने में दिलचस्पी हो। स्वभावत:, समाजवादी देशों के पास फ़ौजी प्रतिष्ठान और उनके नेता हैं, जनरल हैं। परन्तु न तो मज़दूरों, न फ़ौजी उद्योगों और न सेनाओं के नेताओं को इनसे कोई निजी मुनाफ़े मिलते हैं। यदि सेनाओं और फ़ौजी उत्पादन को विघटित करना सम्भव हो जाये, तो सारे समाज, उसके प्रत्येक सदस्य को इससे लाभ ही होगा।

इसके विपरीत, फ़ौजी व्ययों में वृद्धि का समाजवादी जगत के मज़दूर वर्ग तथा समस्त मेहनतकशों के रचनात्मक कार्यकलाप पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वह समाजवाद तथा कम्युनिज़्म के पथ पर उनकी अग्रगति में बाधा डालती है। प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं पर काफ़ी ज़्यादा भौतिक साधन लगाने से समाजवादी उत्पादन क्षमता और जीवन-पद्धति की श्रेष्ठता को पूरी तरह उजागर करने में कठिनाई पैदा होती है।

समाजवादी देशों में शान्ति के लिए संघर्ष सच्चे अर्थों में समस्त जनगण का ध्येय बन गया है। उसमें भाग लेनेवाले शान्ति के लिए सोवियत संघ की पहलक़दमियों का उत्साहपूर्वक समर्थन करते हैं तथा समस्त देशों में शान्ति के पक्षधरों का आह्वान करते हैं कि वे नाभिकीय ख़तरे को अन्तिम रूप से मिटाने के लिए पूरी ताक़त से प्रयास करें।

सोवियत जनता शान्ति का भिन्न-भिन्न रूपों में समर्थन करती है। ये हैं युद्धविरोधी सभाएं, "शान्ति के हेतु श्रम-पालियां", पारिश्रमिक को शान्ति कोश में जमा करना। सोवियत संघ में ये कोश, उदाहरण के लिए, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति वर्ष के अन्तर्गत की जानेवाली कार्रवाइयों के लिए, विशेष रूप से १९८६ में युद्ध के विरुद्ध, यूरोप में सुरक्षा और सहयोग के हेतु कार्रवाई-सप्ताह मनाने के लिए इस्तेमाल किये गये। नाना जनव्यापी कार्रवाइयों में भाग लेनेवालों ने अमरीकी राष्ट्रपति को तार, चिट्ठियां तथा अपीलें भेजकर अमरीकी प्रशासन द्वारा शान्ति के लिए सोवियत संघ की पहलों की ओर ध्यान देने से इन्कार किये जाने पर सख़्त विरोध प्रकट किया। सोवियत नौजवानों ने युद्धविरोधी कार्रवाई-सप्ताह

में सक्रिय भाग लिया। सोवियत संघ के बहुत से नगरों में युवा शान्ति मार्चों, युद्धविरोधी सभाओं का आयोजन किया गया। पांच करोड़ से अधिक सोवियत लोगों ने इस कार्रवाई-सप्ताह में भाग लिया।

सोवियत संघ के नौ करोड़ लोग अब तक अपने मासिक पारिश्रमिक का एक अंश सोवियत शान्ति कोश में दे चुके हैं। इससे पश्चिम में अक्सर किये जानेवाले इस दावे का खण्डन हो जाता है कि सोवियत युद्धविरोधी आन्दोलन के कार्यकलाप पर होनेवाला खर्च सरकार उठाती है। शान्ति कोश में सारे चंदे स्वेच्छया दिये जाते हैं। इस कोश के अलावा शान्ति आन्दोलन के लिए युवाओं, ट्रेड यूनियनों, सृजन कार्य करनेवालों के संगठनों के भी अपने-अपने कोश हैं।

स्वभावत:, जिन अवस्थाओं के अन्तर्गत पूंजीवादी देशों में शान्ति आन्दोलन विकसित होते हैं, वे समाजवादी देशों में विद्यमान अवस्थाओं से भिन्न हैं। अधिकांश पश्चिमी देशों में शान्ति के पक्षधरों की क़तारों में प्रवेश अत्यधिक साहस की अपेक्षा करता है, क्योंकि इससे राज्यसत्ता और उसके शक्तिशाली दमनकारी कार्यतंत्र से टकराव की सम्भावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका प्रमाण है अमरीका, ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी तथा नाटो गुट के अन्य देशों में शान्ति के लिए लड़नेवालों के विरुद्ध बहुसंख्य मुक़दमे।

इसके अलावा व्यापक बेरोज़गारी के हालात में शान्ति आन्दोलन में शिरकत का दुखद परिणाम निकल सकता है। यह है बर्ख़ास्तगी। शान्ति की पैरवी करनेवालों को बहुसंख्य प्रतिक्रियावादी, दक्षिणपंथी उग्रवादी संगठनों की सक्रिय कार्रवाइयों के प्रकोप का शिकार बनना पड़ता है, जो शान्ति और प्रगति की शक्तियों के विरुद्ध अपने संघर्ष में आतंक का सहारा लेते हैं। अन्तत:, विचारधारात्मक दबाव का भी बहुत महत्व है, जो जन-सूचना के बुर्जुआ साधन शान्तिप्रिय शक्तियों पर डालते हैं।

समाजवादी देशों में राजकीय निकाय तथा सामाजिक संगठन व्यापक युद्धविरोधी आन्दोलन को पूरा-पूरा समर्थन देते हैं। यह उनकी राजनीतिक प्रणालियों के जनवादी स्वरूप का मूर्त रूप है, जो जनसाधारण को विदेश नीति जैसे क्षेत्र तक के संचालन में शामिल करती हैं। लेनिन ने लिखा था: "राज्य की शक्ति जनसाधारण की चेतना में होती है। वह तब शक्तिशाली होता है, जब जनसाधारण सब कुछ जानते हैं, सब चीज़ों के बारे में राय बना सकते हैं तथा सब कुछ सचेतन ढंग से करते हैं।" *

---

* व्ला० इ० लेनिन, मज़दूर और सिपाही प्रतिनिधियों की सोवियतों की दूसरी अखिल रूसी कांग्रेस में शान्ति के बारे में भाषण, २६ अक्तूबर, १९१७।

समाजवादी देशों में शान्ति के लिए आन्दोलन जनगण द्वारा केवल विदेश नीति के संचालन में ही नहीं अपितु उसके निरूपण में भी वास्तविक शिरकत का एक रूप है।

केवल दो उदाहरणों से पता चलता है कि कैसे सर्वजनीन युद्धविरोधी आन्दोलन द्वारा निरूपित एक प्रस्ताव राजकीय क़ानून बना। १९५१ में सोवियत शान्ति समिति की पहल पर एक क़ानून पास हुआ था, जिसने किसी भी रूप में युद्ध के प्रचार को घोर फ़ौजदारी जुर्म घोषित किया। पश्चिम के किस देश में ऐसा क़ानून है? किसी में भी नहीं। परन्तु वहां नस्लवाद, अन्धराष्ट्रवाद, फ़ासिज़्म और राष्ट्रवादी घृणा की खुली अभिव्यक्तियां कदापि विरल नहीं हैं। सोवियत संघ में १९८२ से सोवियत जन-संगठनों की पहल पर हर नया स्कूली वर्ष 'शान्ति के बारे में पाठ' से शुरू होता है।

"बड़ी राजनीति" में जनसाधारण की व्यापक शिरकत से केवल वे ही विचलित होते हैं, जो अपनी गुप्त आक्रामक, दुस्साहसिकतावादी योजनाएं रचा करते हैं। प्रसंगत:, पश्चिम में कई बार ऐसा हुआ है कि युद्धविरोधी आन्दोलनों ने अपनी सरकारों की प्रगतिशील नीतियों का खुलेआम समर्थन किया है। १९७२ का वर्ष याद करें, जब पश्चिम जर्मनी में जनसाधारण ने समाजवादी देशों के साथ अच्छे पड़ोसियों के सम्बन्धों की नींव डालनेवाली संधियों का रास्ता रोकने की विपक्ष की योजनाओं को विफल बना दिया था। ऐसे ही उदाहरण इस समय फ़िनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, आस्ट्रिया, यूनान तथा न्यूज़ीलैंड में भी देखने को मिल सकते हैं।

इसलिए किसी भी शान्ति आन्दोलन की स्वतंत्रता का प्रश्न अपनी सरकार के साथ उसके आपसी सम्बन्धों से कदापि निर्धारित नहीं होता, अपितु इस बात से निर्धारित होता है कि वह किस नीति पर चल रहा है। तनाव-शैथिल्य तथा परस्पर लाभप्रद सहयोग में जनसाधारण की दिलचस्पी के फलस्वरूप शान्ति तथा निरस्त्रीकरण के प्रश्न पर पूंजीवादी देशों में शान्ति आन्दोलन तथा समाजवादी देशों की जनता तथा सरकारों की स्थिति एक जैसी है। समस्त शान्तिप्रिय शक्तियों—उनका विश्वदृष्टिकोण तथा राजनीतिक विचार चाहे कुछ भी हों, वे चाहे किसी भी वर्ग या सामाजिक श्रेणी या सामाजिक प्रणाली के हों—की इस एकजुटता को उन लोगों के अत्यधिक रोष तथा विरोध का सामना करना पड़ता है, जो शान्तिप्रिय शक्तियों की एकता को अपने दुस्साहसिकतावादी मन्सूबों की पूर्ति की राह में मुख्य अड़चन मानते हैं।

समाजवादी देशों में शान्ति के पक्षधर शान्ति तथा जीवन के हेतु,

नाभिकीय युद्ध के ख़तरे के विरुद्ध संघर्ष में तमाम देशों तथा महाद्वीपों के करोड़ों लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते हैं। इसी कारण मई दिवस प्रदर्शनों में वे शान्ति के लिए समस्त शान्तिप्रिय शक्तियों के साथ सहयोग के लिए अपनी अडिग इच्छा व्यक्त करते हैं।

३. पूंजीवादी जगत की प्रमुख युद्धविरोधी शक्ति

पूंजीवाद के दुर्गों में शान्तिप्रिय शक्तियों का सक्रिय कार्यकलाप मई दिवस समारोहों में विशेष रूप से दृष्टिगोचर होता है। यहां नौवें दशक के मध्य की अख़बारी रिपोर्टों से लिये गये केवल कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

१ मई, १९८४ को कनाडा में तूफ़ानी युद्धविरोधी प्रदर्शन हुए। अकेले वैंकोवर नगर में मई दिवस के शान्ति मार्च में लगभग १,१५,००० लोगों ने भाग लिया। उन्होंने कनाडा की भूमि पर क्रूज़ मिसाइलों के परीक्षण की अनुमति देनेवाली अमरीकी-कनाडियन संधि को मंसूख़ करने की मांग की। इसी तरह का शान्ति मार्च टोरोंटो में भी हुआ, जिसमें कई हज़ार लोगों ने भाग लिया।

उसी दिन जापान में १,२०० नगरों और बस्तियों में मई दिवस प्रदर्शन हुए, जिनमें लगभग ४० लाख व्यक्तियों ने भाग लिया। उन्होंने शान्ति तथा मेहनतकशों के अधिकारों की रक्षा का संकल्प व्यक्त किया। टोकियो के केन्द्रीय पार्क योयोगी में ५५वीं बार मुख्य सभा हुई, जिसमें तीन लाख व्यक्तियों ने भाग लिया।

पश्चिमी जर्मनी के छोटे-बड़े नगरों में मई दिवस के उपलक्ष्य में सभाएं तथा प्रदर्शन हुए। उनमें लगाये गये नारों में कुछ ये थे: "मिसाइल मुर्दाबाद! बेरोज़गारी मुर्दाबाद! अमरीकी साम्राज्यवाद का मुंह काला हो!"

पेरिस में फ़्रांसीसी राजधानी के हज़ारों-हज़ार निवासियों का जलूस मई दिवस प्रदर्शन के अवसर पर ग्रांड बूलवारों से गुज़रा। उनके हाथों में बड़े-बड़े झंडे थे, जिन पर लिखा था: "नाभिकीय ख़तरे का अन्त हो!", "बड़े पैमाने पर बर्ख़ास्तगियां रोकी जायें!", "शान्ति तथा रोज़गार!"

१९८५ में भी पूंजीवादी जगत में मेहनतकशों के मई दिवस प्रदर्शनों की सरगर्मी में कमी नहीं आयी। यूनान में राष्ट्रीय हड़ताल हुई

और देश के बहुत से शहरों में व्यापक प्रदर्शन हुए। एथेन्स में एक बहुत बड़ी सभा हुई। वहां झंडों पर लिखा था: "इजारेदारियों की 'साझा मंडी' नहीं चाहिए!", "अमरीकी फ़ौजी अड्डे मुर्दाबाद!", "शान्ति, श्रम, निरस्त्रीकरण!"

१ मई, १९८५ को न्यूयार्क नगर के यूनियन स्क्वायर में एक बहुत बड़ी सभा हुई। फ़ासिज़्म पर, जो इजारेदार पूंजी की निकृष्टतम उपज था, विजय की ४०वीं जयन्ती के अवसर पर अमरीकी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव गेस हाल ने इस विजय में निर्णायक भूमिका अदा करने के लिए सोवियत जनता का अभिवादन किया।

जापान में और भी विशाल प्रदर्शन हुए, जिनमें शान्ति के पक्ष में तथा अमरीका की आक्रामक रणनीतिक योजना में जापानी सरकार की शिरकत के विरोध में नारे लगाये गये। उनमें ४२ लाख व्यक्तियों ने भाग लिया। टोकियो में एक सभा हुई, जिसमें तीन लाख लोग उपस्थित थे। उसमें शस्त्रीकरण बन्द करने का घोषणापत्र स्वीकार किया गया था।

१९८६ में न्यूयार्क नगर के यूनियन स्क्वायर में शान्ति तथा श्रम के अन्तर्राष्ट्रीय पर्व—मई दिवस की शती—के उपलक्ष्य में एक विशाल प्रदर्शन हुआ।

इटली में भी इस दिवस पर बड़ी-बड़ी सभाएं तथा प्रदर्शन हुए, जिनमें शान्ति के पक्ष में, हथियारों की दौड़ के विरुद्ध, मेहनतकशों के आधारभूत अधिकारों तथा जनवादी उपलब्धियों की रक्षा के पक्ष में नारे गुंजायमान हुए। इन्हें देश के अग्रणी ट्रेड यूनियन एसोसियेशनों—इटालवी मज़दूरों की जनरल यूनियन, ट्रेड यूनियनों के इटालवी महासंघ, इटालवी श्रम यूनियन—ने संगठित किया था। इन प्रदर्शनों में भाग लेनेवालों ने मानवजाति के अस्तित्व को खतरे में डालनेवाली साम्राज्यवाद की खतरनाक योजनाओं के विरुद्ध संघर्ष जारी रखने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने अन्तरिक्ष का सैन्यीकरण करने की अमरीकी योजनाओं और साथ ही भूमध्यसागरीय क्षेत्र में तनाव बढ़ाने की अमरीकी नीति की भर्त्सना की।

"शान्ति, एकजुटता, सामाजिक न्याय!"—ये नारे पुर्तगाल के ७० नगरों तथा बस्तियों में मई दिवस के अवसर पर आयोजित नाना प्रदर्शनों में गूंज उठे थे, जिनमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया।

स्पेन की राजधानी मैड्रिड में मई दिवस के अवसर पर एक विशाल प्रदर्शन हुआ, जिसे मज़दूर आयोगों के ट्रेड यूनियन महासंघ तथा राष्ट्रीय

श्रम महासंघ ने आयोजित किया था। उसमें "शान्ति, रोज़गार!", "अमरीकी अड्डे मुर्दाबाद!", "निकारागुआ तथा लीबिया के जनगण के साथ एकजुटता!" के नारे लगाये गये थे।

हेलसिंकी के केन्द्रीय चौक—सेनाट्टी टोरी—में एक विशाल सभा हुई। उसमें विभिन्न राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि आज का मुख्य कार्यभार शान्ति, तनाव-शैथिल्य, निरस्त्रीकरण तथा सामाजिक प्रगति के हेतु समस्त देशों के मेहनतकशों की अन्तर्राष्ट्रीय एकजुटता को सुदृढ़ बनाना है। वक्ताओं ने अपने भाषणों में कहा कि यूरोप को नाभिकीय शस्त्रास्त्र मुक्त क्षेत्र में परिणत करने के सोवियत प्रस्ताव और अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा की व्यापक प्रणाली की स्थापना करने का सोवियत कार्यक्रम पूरी मानवजाति के हितों से मेल खाते हैं।

नौवें दशक में पूंजीवाद के दुर्गों में युद्धविरोधी आन्दोलन की संवृद्धि एक अकाट्य तथ्य है। जनव्यापी स्वरूप ग्रहण करने से पूर्व इस आन्दोलन में परम्परागत सैन्यवाद विरोधी, शान्तिवादी, नौजवान तथा छात्र संगठन मुख्य भूमिका अदा करते थे। मेहनतकशों के बहुत से सामाजिक-सुधारवादी स्वरूप के राजनीतिक तथा अराजनीतिक संगठनों का आन्दोलन के प्रति या तो नकारात्मक रुख़ होता था अथवा वे उससे महज़ अलग रहते थे।

फिर शान्ति आन्दोलन के सामाजिक तथा राजनीतिक आधार का ज़ोरदार विस्तार होने लगा। आम जनवादी आन्दोलनों का युद्धविरोधी आन्दोलन के साथ परस्पर सम्पर्क निरन्तर बनता चला गया। आन्दोलन में महिला संगठनों की शिरकत कहीं अधिक गहन होती चली गयी और बढ़ती गयी। युद्ध के ख़तरे के विरुद्ध आबादी के पेशेवर, सबसे पहले, बुद्धिजीवियों के ग्रुपों (डाक्टरों, अध्यापकों, वकीलों, आदि) के आन्दोलन का जन्म तथा विकास हुआ। रिहाइशी इलाक़ों में युद्धविरोधी संगठन के निर्माण तथा प्रसार ने महत्वपूर्ण स्वरूप ग्रहण किया। शान्ति के समर्थन में बड़े-बड़े धार्मिक संगठनों के कार्यकलाप के फलस्वरूप शान्ति आन्दोलन का अत्यधिक प्रसार हुआ।

समकालीन युद्धविरोधी आन्दोलन की अभिलाक्षणिकता यह है कि उसमें मज़दूर वर्ग की भूमिका स्पष्ट रूप से बढ़ती जा रही है। इसका प्रमाण है नाना पूंजीवादी देशों में सीधे उद्यमों-प्रतिष्ठानों के स्तर पर शान्ति के हेतु मज़दूर आन्दोलन में उभार, उसके युद्धविरोधी कार्यकलाप का गहन होते जाना, आन्दोलन के प्रति बहुत सी सुधारवादी ट्रेड यूनियनों और सामाजिक-जनवादी धारावाली पार्टियों के रुख़ में सकारात्मक

परिवर्तन, युद्धविरोधी आन्दोलन के अन्य दस्तों के साथ मज़दूर वर्ग के अधिक घनिष्ठ सहयोग की स्थापना।

वर्तमान युद्धविरोधी आन्दोलन में सबसे महत्वपूर्ण नयी परिघटनाओं में से एक है कई पूंजीवादी देशों में सीधे बड़े-बड़े प्रतिष्ठानों में शान्ति के हेतु संघर्ष के लिए मेहनतकशों के संगठनों का निर्माण। ख़ास तौर पर पश्चिम जर्मनी में ३०० से अधिक कारख़ाना शान्ति समितियां कार्यरत हैं। इटली में कारख़ाना परिषदें तथा भिन्न उद्यमों में प्राथमिक यूनियन संगठन शान्ति के लिए मेहनतकशों के संघर्ष के हरावल के रूप में प्रकट हुए हैं। फ़िनलैंड में औद्योगिक शान्ति समिति स्थापित हुई है, जिसने प्रतिष्ठानों में शान्ति के पक्षधर कामगारों को ऐक्यबद्ध किया है। वह हर साल राष्ट्रीय सभाएं तथा प्रभावशाली युद्धविरोधी प्रदर्शन आयोजित करती है।

कारख़ाना शान्ति समितियों के कार्यकलाप का महत्व घटाकर आंकना असम्भव है। पहली चीज़, वे मज़दूर वर्ग के बीच रहकर कार्य करती हैं और वहां युद्धविरोधी आन्दोलन का केन्द्रबिन्दु हैं। दूसरी चीज़, वे हथियारबन्दी के विरुद्ध संघर्ष और रोज़गार सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष के बीच घनिष्ठ सम्पर्क को सुस्पष्ट रूप से दर्शाती हैं। तीसरी चीज़, वे कारख़ाना शान्ति समितियों के ज़रिये शान्ति की रक्षा करने, समस्त युद्धविरोधी शक्तियों को ऐक्यबद्ध करने तथा उनके कार्यकलाप में समन्वय स्थापित करने की आम मज़दूरों की इच्छा व्यक्त करती हैं, जिसकी सुधारवादी ट्रेड-यूनियनों के नेता उपेक्षा नहीं कर सकते।

सैन्यवाद विरोधी कार्रवाइयों में मेहनतकशों की, जिनकी युद्ध तथा शान्ति की समस्याओं के प्रति सामाजिक चेतना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, सक्रिय शिरकत ने पूंजीवादी देशों के ट्रेड यूनियन केन्द्रों तथा उन लोगों तक को शान्ति के लिए संघर्ष में शामिल होने के लिए बाध्य किया है, जो उसके प्रति हाल तक उदासीन थे। ये प्रवृत्तियां सभी मुख्य पूंजीवादी देशों में देखी जा सकती हैं हालांकि उनके प्रभाव की मात्रा भिन्न-भिन्न है।

इस सम्बन्ध में युद्धविरोधी आन्दोलन के प्रति जर्मन ट्रेड यूनियनों के एसोसियेशन की, जो पश्चिमी जर्मनी का मुख्य ट्रेड यूनियन केन्द्र है, सैनिक-राजनीतिक अवधारणाओं तथा व्यावहारिक नीति का विकास अत्यन्त उल्लेखनीय है। युद्धविरोधी आन्दोलन में ट्रेड यूनियनों की शिरकत पर १९८१ की आधिकारिक पाबन्दी से हट कर ट्रेड यूनियनों के इस जर्मन एसोसियेशन ने १९८३ में शान्तिप्रिय शक्तियों के साथ सहयोग की

स्थापना की । इस समय वह अमरीका की "तारक युद्ध" योजना का विरोध कर रहा है, जो विद्यमान सामरिक शक्ति-सन्तुलन की नींव को ध्वस्त करती है और हथियारबन्दी की रफ़्तार को अभूतपूर्व पैमाने पर बढ़ाती है। एसोसियेशन पश्चिम जर्मन सरकार से वाशिंगटन के जोखिम भरे मन्सूबे से दूर रहने की मांग कर रहा है।

पूंजीवादी देशों में बड़े-बड़े दक्षिणपंथी ट्रेड यूनियन केन्द्रों के, ख़ास तौर पर, अमरीकी श्रम संघ-औद्योगिक संगठन कांग्रेस के नेता युद्ध तथा शान्ति, निरस्त्रीकरण की समस्याओं के प्रति अपनी पहले की स्थिति पर पुनर्विचार कर रहे हैं। भले ही वे कभी-कभी अमरीकी ट्रेड यूनियन आन्दोलन के विकास को महासागर पार के कथित विरोधी के विरुद्ध लक्षित करने का प्रयास करते हैं, फिर भी वे केवल साधारण ट्रेड यूनियन सदस्यों तथा प्राथमिक संगठनों के ही नहीं, अपितु कतिपय उद्योग-शाखाओं की बड़ी ट्रेड-यूनियनों के नेताओं और संघ की कार्यसमिति के सदस्यों के भी बढ़ते दबाव को अनुभव करते हैं।

अक्तूबर १९८३ में ही अमरीका के इस ट्रेड यूनियन संगठन ने एक प्रस्ताव पास कर शस्त्रास्त्रों को जाम करने की मांग की थी। १९८५ में अमरीकी ट्रेड यूनियनों ने देश के ६० नगरों में इस नारे के साथ मुहिम चलाया: "शान्ति की अवस्थाओं में रोज़गार!", जिसका मेहनतकशों ने व्यापक समर्थन किया। लास-एंजेल्स तक में, जहां अमरीका के वैमानिक-अन्तरिक्षीय उद्योग के कुल कर्मचारियों का पांचवां भाग काम करता है और जो मुख्यतया युद्धोद्योग का केन्द्र है, पांच लाख लोगों ने इस कार्रवाई का समर्थन किया।

अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय मशीन-निर्माता एसोसियेशन की मौजूदा स्थिति भी बहुत उल्लेखनीय है, जिसके बहुत से सदस्य रक्षा-उद्योग में काम कर रहे हैं। उसके एक दस्तावेज़ में कहा गया है: "और अधिक हथियार ख़रीदने के आर्थिक परिणाम उल्लेखनीय होंगे। इससे रोज़गार, पूंजी निवेश और आर्थिक संवृद्धि की बलि होगी। टेक्नालाजिक प्रगति पर ब्रेक लगेगा। लोगों के दुख-कष्ट कम करने की ओर लक्षित आर्थिक कार्यक्रमों में कटौती होगी।... सैनिक व्ययों में वृद्धि बेरोज़गारी की समस्या हल नहीं करेगी।... सामाजिक क्षेत्र में बहुत ऊंची कीमतें चुकानी पड़ेंगी।"

१९८० में ब्रिटिश ट्रेड-यूनियन कांग्रेस ने अपने ११२वें सम्मेलन में नाटो की "अतिरिक्त शस्त्रीकरण" योजनाओं का तथा इंगलैंड में अमरीकी क्रूज़ मिसाइल लगाये जाने का विरोध किया। ट्रेड यूनियनें

नाभिकीय निरस्त्रीकरण के लिए आन्दोलन के साथ, जो देश का प्रमुख युद्धविरोधी संगठन है, सक्रिय सहयोग करती हैं। इस संगठन का समर्थन करनेवाली ट्रेड यूनियनों की सदस्य-संख्या ६० लाख है। वे हथियारबन्दी में कटौती करने और सैनिक उद्योग को शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए पुनर्गठित करने की सक्रिय रूप से पैरवी करती हैं। उदाहरण के लिए, १९८४ में उन्होंने एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसका विषय था "रक्षा उद्योग के मज़दूरों के लिए बेहतर भविष्य"। १९८५ में रक्षा उद्योग का शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए पुनर्गठन करने से सम्बन्धित राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन समिति ने कई पहलक़दमियां कीं, जिनमें 'ट्राइडेंट' के, देश के सबसे बड़े रक्षा कार्यक्रम के शान्तिपूर्ण वैकल्पिक कार्यक्रम का प्रस्ताव शामिल था। इस प्रस्ताव को व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। बृहत्तर लन्दन परिषद ने सिफ़ारिश की कि रक्षा उद्योग के समस्त प्रतिष्ठानों में पुनर्गठन परिषद तथा उसकी शाखाओं का निर्माण किया जाये।

इटली में ट्रेड यूनियनों की युद्धविरोधी गतिविधियों ने देश में पहला अमरीकी क्रूज़ मिसाइल लगाये जाने के बाद ख़ास तौर पर जोर पकड़ा। फ़रवरी १९८४ में ट्रेड यूनियनों के आम संघ में फूट पड़ने के बाद भी तीन अग्रणी ट्रेड यूनियन केन्द्रों — इटालवी मज़दूरों की आम यूनियन, ट्रेड यूनियनों के इटालवी महासंघ तथा इटालवी श्रम संघ — ने शान्ति तथा निरस्त्रीकरण के लिए मिलकर काम करना जारी रखा।

ट्रेड यूनियन आन्दोलन जापान में शान्ति के लिए संघर्ष में विशेष भूमिका करता है। वह देश में सैन्यवाद के पुनरुत्थान के तथा जापान को अमरीका के "कभी न डूब सकनेवाले विमानवाहक पोत" में रूपान्तरण के विरुद्ध लक्षित है। जापान की ट्रेड यूनियनों की, सर्वप्रथम ट्रेड यूनियनों की जनरल परिषद की सक्रिय शिरकत के साथ देश में आठ करोड़ से अधिक हस्ताक्षर जमा किये गये, जिनमें नाभिकीय शस्त्रास्त्रों को ग़ैरक़ानूनी करार देने तथा नया युद्ध न होने देने की मांग की गयी।

फ़्रांस में फ़्रांसीसी श्रम जनवादी महासंघ तथा 'फ़ोर्स उव्रिएर' जैसे सुधारवादी ट्रेड यूनियन केन्द्रों के युद्धविरोधी कार्यकलाप का पैमाना तथा दिशा अब भी समय की मांग के पीछे हैं। परन्तु वहां भी हथियारों की होड़ की वृद्धि और मेहनतकशों की बिगड़ती सामाजिक और आर्थिक दशा के बीच गहरे सम्बन्ध की समझ अब बढ़ती जा रही है।

कनाडा में युद्ध के विरोधियों का एक राष्ट्रीय मोर्चा बन गया है। कम्युनिस्ट, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी और मुख्य ट्रेड यूनियन केन्द्र मिलकर यह मांग कर रहे हैं कि कनाडा की धरती पर क्रूज़ मिसाइलों का परीक्षण

बन्द हो, देश को नाभिकीय शस्त्रास्त्रों से मुक्त क्षेत्र में परिणत किया जाये, अन्तरिक्ष का सैन्यीकरण न होने दिया जाये, नाभिकीय तथा परम्परागत निरस्त्रीकरण के लिए पग उठाये जायें, तनाव-शैथिल्य की ओर लौटा जाये।

अपने युद्धविरोधी आन्दोलनों में हड़तालें जैसी परम्परागत सर्वहारा विधियों का उपयोग इस बात का प्रमाण है कि शान्ति की रक्षा करने तथा हथियारों की होड़ रोकने के लिए भरसक काम करने की आवश्यकता के विचार ने सुधारवादी ट्रेड यूनियन केन्द्रों तक में कितनी गहरी जड़ पकड़ ली है।

अमरीकी यूरो-मिसाइल लगाये जाने के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए ५ अक्तूबर, १९८३ को पश्चिम जर्मनी के मेहनतकशों द्वारा चेतावनी के रूप में काम का रोका जाना अल्पकालीन आम राजनीतिक हड़ताल में बदल गया।

६ माह बाद (१० मई, १९८४ को) "क्रूज़ मिसाइल नहीं!" नामक समिति तथा नीदरलैंड्स ट्रेड यूनियन संघ की, जो देश का प्रमुख ट्रेड यूनियन केन्द्र है, अपील पर नीदरलैंड्स में अमरीकी मिसाइल लगाये जाने के विरुद्ध "कार्रवाई सप्ताह" की परिधि के अन्तर्गत देश में १५ मिनट तक काम रोक दिया गया, जिसमें साढ़े सात हज़ार लोगों ने भाग लिया। ऐसे छोटे देश के लिए यह संख्या बहुत बड़ी है।

२४ अक्तूबर, १९८५ को दोपहर में डेनमार्क में बहुत से औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा संस्थानों में काम रुक गया। तनाव-शैथिल्य, निरस्त्रीकरण, उत्तरी यूरोप में नाभिकीय शस्त्रास्त्रों से मुक्त क्षेत्र के निर्माण की अपनी इच्छा प्रकट करने के लिए लगभग दस लाख व्यक्तियों ने ट्रेड यूनियनों के केन्द्रीय महासंघ तथा अन्य राष्ट्रीय संगठनों के आह्वान पर "शान्ति के लिए हड़ताल" की। "नाभिकीय शस्त्रास्त्रों से मुक्त डेनमार्क आज और सदा-सर्वदा के लिए!"—इस मांग को लेकर यहां शान्तिप्रिय शक्तियां सामने आती हैं।

विभिन्न राजनीतिक धाराओंवाली ट्रेड यूनियनों के युद्धविरोधी कार्यकलाप की सफलताएं बहुत हद तक उनकी संयुक्त कार्रवाइयों पर निर्भर करती हैं। संयुक्त कार्रवाई करने के लिए विश्व ट्रेड यूनियन संघ ने विश्व फ़्री ट्रेड यूनियन महासंघ और विश्व श्रम कांग्रेस का बार-बार आह्वान किया, ताकि हथियारों की होड़ रोकी जा सके और सरकारों को निरस्त्रीकरण के बारे में समझौता करने के लिए प्रेरित किया जा सके। परन्तु अविराम गति से शस्त्रास्त्रों के निर्माण से उत्पन्न ख़तरे को स्वीकार

करते हुए भी उपरोक्त दो संगठन मेहनतकशों को संयुक्त कार्यवाही के लिए एकजुट नहीं कर पाये हैं, हालांकि १९८३ के ग्रीष्मकाल में अपनी १३वीं कांग्रेस में विश्व फ़्री ट्रेड यूनियन महासंघ ने कहा था कि मेहनतकश और विभिन्न धाराओंवाले उनके संगठन शान्ति के हेतु संघर्ष को सबसे प्रमुख राजनीतिक समस्या मानने की मांग करते हैं।

समकालीन ट्रेड यूनियन आन्दोलन की तात्कालिक समस्याओं पर विचार करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय फ़ोरमों ने भिन्न-भिन्न राजनीतिक धाराओंवाली ट्रेड यूनियनों के बीच युद्धविरोधी अन्तर्राष्ट्रीय एकजुटता स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। यही दिसम्बर १९८१ में पेरिस में निरस्त्रीकरण के सामाजिक तथा आर्थिक पहलुओं से सम्बन्धित पहले विश्व ट्रेड यूनियन सम्मेलन में हुआ था। उसमें दुनिया के मेहनतकशों तथा उनके संगठनों का आह्वान किया गया था कि वे अपने सारे मतभेदों का ख़याल किये बिना शान्ति के लिए संघर्ष में शामिल हों।

विश्व ट्रेड यूनियन आन्दोलन में युद्धविरोधी कार्रवाइयों का समन्वय करने में महत्वपूर्ण भूमिका शान्ति तथा निरस्त्रीकरण की अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन समिति अदा करती है। इसे डबलिन समिति कहते हैं, क्योंकि वह उपरोक्त पेरिस सम्मेलन के निर्णयानुसार मई १९८२ में डबलिन में स्थापित हुई थी। उसके संगठनकर्ताओं में सोवियत संघ, अमरीका, ब्रिटेन, जापान, फ़्रांस, भारत, अल्जीरिया और अन्य देशों की ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि थे। अपनी सक्रिय गतिविधियों के कारण समिति को शान्तिप्रिय जनता के व्यापक क्षेत्रों में अत्यधिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है।

निरस्त्रीकरण के सामाजिक तथा आर्थिक पहलुओं पर दूसरा विश्व ट्रेड यूनियन सम्मेलन, जो मई १९८६ में डबलिन में हुआ था, उल्लेखनीय घटना बन गया है। लगभग ५० देशों के ट्रेड यूनियन संगठनों के प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया। उनमें इस बात पर मतैक्य था कि युद्ध और शान्ति के बीच सीमारेखा अब इतनी अधिक सूक्ष्म हो गयी है कि उसपर सन्तुलन क़ायम रखना असम्भव हो गया है और हथियारबन्दी की होड़ के सामाजिक-आर्थिक कुपरिणाम अब असह्य हो चुके हैं।

फ़ोरम में भाग लेनेवालों ने एक समापन प्रस्ताव पास किया। उसका शीर्षक था: 'शस्त्रीकरण की होड़ के बिना विश्व अर्थव्यवस्था'। इसके अलावा उन्होंने एक विशेष घोषणापत्र भी स्वीकृत किया, जिसमें बढ़ते फ़ौजी ख़तरे के विरुद्ध सक्रिय संघर्ष में ट्रेड यूनियन आन्दोलन को आगे एकजुट करने की कार्रवाइयों की रूपरेखा निश्चित थी। इन दोनों

दस्तावेज़ों में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि मौजूदा हालात में मेहनतकशों की सामाजिक-आर्थिक उपलब्धियों की रक्षा करने, आर्थिक पिछड़ेपन, भूख, बीमारियों तथा निरक्षरता को मिटाने के लिए ट्रेड यूनियनों की कार्रवाइयां संसार में शस्त्रास्त्रों के ज़खीरे जमा करने की घातक प्रक्रिया को रोकने के मुख्य कार्यभार से अटूट रूप से जुड़ी हुई हैं। घोषणापत्र इस बात पर ज़ोर देता है कि सैनिक-औद्योगिक समुच्चय के सरगनों द्वारा तेज़ की जा रही इस प्रक्रिया के अरोध्य बनने का ख़तरा है। इसलिए इन परिस्थितियों में ट्रेड यूनियनों, जनवादी सामाजिक शक्तियों को युद्धविरोधी मोर्चा सुदृढ़ बनाने के तरीक़ों की दृढ़तापूर्वक खोज पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। फ़ोरम में सोवियत संघ के शान्ति-कार्यक्रम का बहुत उच्च मूल्यांकन किया गया था।

युद्ध तथा शान्ति और निरस्त्रीकरण की समस्याओं के प्रति मेहनतकश जनसमुदाय के बहुत बड़े भाग के रुख़ में परिवर्तन प्रतिष्ठानों की श्रम-टोलियों और साथ ही ट्रेड यूनियन केन्द्रों के स्तर पर दृष्टिगोचर हो रहा है। इस परिवर्तन ने सामाजिक-जनवादी पार्टियों की सैनिक तथा राजनीतिक अवधारणाओं का और युद्धविरोधी आन्दोलन के साथ इन पार्टियों के परस्पर सम्बन्धों का रूपान्तरण करने में मदद दी। साम्राज्यवादी विदेश नीति के मामले में दक्षिणपंथी पार्टियों और सामाजिक-जनवादी आन्दोलन के बीच सीमारेखा उभरती जा रही है।

आठवें दशक के अन्त में पश्चिमी यूरोपीय देशों की राजनीतिक पार्टियों में केवल कम्युनिस्ट पार्टियां ही नाटो की सैनिक-राजनीतिक रणनीति का विरोध करती थीं। परन्तु आज सामाजिक-जनवादी तथा समाजवादी पार्टियों की भारी बहुसंख्या अन्तर्राष्ट्रीय तनाव प्रज्ज्वलित किये जाने, पहले प्रहार करनेवाले अमरीकी नाभिकीय मिसाइल लगाये जाने और अन्तरिक्ष का सैन्यीकरण किये जाने की नीति का विरोध कर रही है।

उदाहरण के लिए, फ़िनलैंड तथा स्कैंडिनेवियन देशों के सामाजिक-जनवादी उत्तरी यूरोप में नाभिकीय शस्त्रास्त्रों से रहित क्षेत्र के निर्माण के लिए संघर्षरत हैं। यूनानी समाजवादियों ने बहुमूल्य युद्धविरोधी पहलक़दमियां की हैं। ब्रिटिश लेबर पार्टी ने नाभिकीय शस्त्रास्त्रों के परित्याग और सारे अमरीकी नाभिकीय अड्डे ख़त्म करने का कार्यक्रम अनुमोदित किया है। और ऐसे उदाहरणों की सूची जारी रखी जा सकती है।

सामाजिक-जनवादियों की स्थिति में परिवर्तन अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर

आन्दोलन के सुधारवादी पक्ष के प्रभावाधीन लाखों मेहनतकशों के युद्धविरोधी कार्यकलाप को आगे बढ़ाने के लिए नयी, बहुत सी अनुकूल परिस्थितियां तैयार करता है और विश्व फ़्री ट्रेड यूनियन महासंघ पर सारभूत प्रभाव डाल सकता है। इससे शान्ति तथा निरस्त्रीकरण के लिए विश्वव्यापी पैमाने पर संघर्षरत समस्त मेहनतकशों और अन्य जनवादी शक्तियों की एकजुटता, जो आज अत्यधिक आवश्यक बन चुकी है, का विकास बहुत आसान हो जायेगा।

निरस्त्रीकरण के विषय में समाजवादी इंटरनेशनल की वियेना में अक्तूबर १९८५ को हुई कांफ़्रेंस के परिणाम इस बात का प्रमाण हैं कि इस तरह का विकास पूर्णतया सम्भव है। कांफ़्रेंस ने एक तरह से इस समस्या पर सामाजिक-जनवादी पार्टियों की अप्रैल १९७८ में हेलसिंकी में हुई पहली सभा की लाइन जारी रखी। तबसे संसार में स्थिति बदली है और अधिक ख़तरनाक बन गयी है, परन्तु इसके साथ ही युद्ध के ख़तरे को दूर करने की लाखों-लाख लोगों की इच्छा भी बढ़ी है। उनकी मांगों ने कांफ़्रेंस में भाग लेनेवालों की संख्या और विचाराधीन विषयों का दायरा बढ़ाने में मदद दी।

यदि १९७८ में २० देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने सम्मेलन में भाग लिया, तो १९८५ में पांचों महाद्वीपों के लगभग ५० देशों के सामाजिक-जनवादी, समाजवादी तथा लेबरपंथी सभा में एकत्र हुए। वाद-विवाद को अधिक सार्थक बनाने, अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में प्रमुख भूमिका अदा करनेवाले राज्यों, आन्दोलनों तथा संगठनों की स्थिति को गहन, बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने के लिए वियेना सभा के आयोजकों ने सोवियत संघ, अमरीका, संयुक्त राष्ट्र संघ, गुटनिरपेक्ष आन्दोलन, चीन लोक जनतंत्र तथा बहुत से दूसरे राज्यों के प्रतिनिधियों को सभा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।

कांफ़्रेंस में भाग लेनेवाले बहुत से लोगों ने इस बात की चर्चा की कि शान्ति तथा निरस्त्रीकरण के लिए संघर्ष अत्यन्त जटिल है। कुछ ने शान्तिप्रिय शक्तियों की क्षमताओं का निराशावादी मूल्यांकन किया। परन्तु शान्ति की रक्षा करने और उसे सुदृढ़ बनाने की समस्या के बारे में यथार्थवादी दृष्टिकोण का पलड़ा अन्ततः भारी रहा। और काफ़ी हद तक इसका श्रेय अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण को सुधारने के लिए सोवियत संघ द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम तथा ठोस प्रस्तावों को था।

सम्मेलन में विचार-विमर्श का केन्द्रबिन्दु अन्तरिक्ष के असैन्यीकरण का प्रश्न था। समाजवादी इंटरनेशनल की पार्टियों का प्रतिनिधित्व

8 601

करनेवाले वक्ताओं में से एक ने भी ह्वाइट हाउस की कथित "सामरिक रक्षा पहल" सम्बन्धी योजना का समर्थन नहीं किया।

निस्सन्देह, कांफ़ेंस में प्रकट किये गये विचार कई तरह से एक दूसरे से भिन्न थे, इस कारण वहां तीक्ष्ण वाद-विवाद हुआ। परन्तु बुनियादी मसलों के प्रति स्थितियां तथा दृष्टिकोण एक दूसरे से मेल खाते थे। सबसे पहले इनका सम्बन्ध सैनिक ख़तरा मिटाने, हथियारों की होड़ पर रोक लगाने, शान्ति और सहयोग की नींव को पुख़्ता बनाने के लिए संघर्ष करने के कार्यभारों तथा मांगों से था।

कांग्रेस ने समाजवादी इंटरनेशनल की 'वियेना अपील' अनुमोदित की, जिसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया था कि जनसंहारकारी शस्त्रास्त्रों का संग्रह जारी रखना पृथ्वी पर जीवन के ही अस्तित्व के लिए ख़तरा है, इसलिए मानवजाति के हितार्थ शस्त्रीकरण की होड़ का अन्त करना आवश्यक है। अपील में यह उल्लेख भी किया गया कि समाजवादी इंटरनेशनल शस्त्रीकरण की होड़ के अन्तरिक्ष में फैलने के ख़तरे से विशेष रूप से चिन्तित है और वह अमरीका की "सामरिक रक्षा पहल" और इसी तरह की दूसरी सब अवधारणाओं को अस्वीकार करता है।

प्रश्नों के इतने व्यापक दायरे पर विचारों के एक दूसरे से मेल खाने से कम्युनिस्ट और सामाजिक-जनवादी पार्टियों के बीच कामकाजी सहयोग की सम्भावनाएं पैदा होती हैं, यह विश्वास पैदा होता है कि विचारधारात्मक मतभेद शान्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए मज़दूर तथा जनवादी आन्दोलनों के विभिन्न दस्तों के संघर्ष में वार्ताओं तथा आपसी समझदारी का रास्ता नहीं रोक सकते।

इस बात में विश्वास करते हुए कि वर्तमान परिस्थितियों में शान्ति की रक्षा करने से अधिक महत्वपूर्ण कार्यभार और कोई नहीं है, कम्युनिस्ट, जो मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण तथा उत्पीड़न के विरुद्ध पहले की तरह सबसे अडिग योद्धा हैं, मानव-सभ्यता, मनुष्य के मूल अधिकार—जीवित रहने के अधिकार—की रक्षा के लिए अथक संघर्ष करते जा रहे हैं।

युद्धविरोधी एकजुटता के विकास के उद्देश्य से कम्युनिस्ट अपने साझीदारों से धैर्यपूर्वक वाद-विवाद करना और सद्भावना के साथ तर्क-वितर्क करना अपना कर्त्तव्य मानते हैं, भले ही बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर उनके विचारों में भिन्नता हो। कम्युनिस्ट युद्धविरोधी एकजुटता के शत्रुओं के इस आरोप का खण्डन करते हैं कि वे शान्ति आन्दोलन की शक्तियों पर अपना नायकत्व थोपने का प्रयास करते हैं। कम्युनिस्टों

के सुसंगत कार्यकलाप, जिनका उद्देश्य शान्ति आन्दोलन की शक्तियों को ऐक्यबद्ध करना है, पश्चिम के व्यापक जनवादी क्षेत्रों के बीच कम्युनिस्टों की प्रतिष्ठा बढ़ाने में मदद देते हैं।

आज बुर्जुआ राजनीतिज्ञ तथा विचारधारानिरूपक विकसित पूंजीवादी देशों में शान्ति के लिए संघर्ष के अग्रमंच पर मज़दूर वर्ग और उसके संगठनों के आगे बढ़ने को "नज़रन्दाज़ करने" को तरजीह देते हैं। परन्तु वे यह बात, निस्सन्देह, समझते हैं—हालांकि वे इसे सार्वजनिक रूप से विरले ही स्वीकार करते हैं—कि मज़दूर वर्ग हथियारबन्दी की होड़ तथा फ़ौजी उन्माद की राह में मुख्य बाधक है। इसी कारण मेहनतकशों के बीच तरह-तरह की मनगढ़ंत बातें फैलायी जाती हैं, जिनका उद्देश्य मज़दूर वर्ग को इस बात का क़ायल करना है कि नाटो की मौजूदा सैनिक नीति तथा राजनीति उसकी सुरक्षा और युद्ध उद्योग के ज़रिये अतिरिक्त रोज़गार सुनिश्चित करेंगी।

ऐसा प्रचार सदा असफल नहीं रहता। पूंजीवादी जगत में मेहनतकशों के ऐसे काफ़ी ज़्यादा दस्ते हैं, जो युद्ध उद्योग में लगे हुए हैं या उसमें काम पाने की आशा रखते हैं। बहुत से नौजवान भी सेना में अथवा सैनिक विद्यालयों में भर्ती होकर अपने रोज़गार या शिक्षा की समस्या हल करते हैं। वे ऐसे विचारों के वाहक हो सकते हैं, जो मूलत: शान्तिप्रिय शक्तियों के हितों के विपरीत हैं।

कुछ भी हो, पश्चिम में शान्ति के लिए संघर्ष में मज़दूर वर्ग की बढ़ती भूमिका एक अकाट्य तथ्य है। हालांकि मज़दूर वर्ग तथा अन्य शान्ति-संगठनों के बीच अन्योन्यक्रिया अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है, फिर भी शान्ति, एकजुटता तथा पारस्परिक सहयोग के हेतु सम्पूर्ण जनव्यापी आन्दोलन की कारगरता बहुत हद तक मज़दूर वर्ग की शान्तिपूर्ण गतिविधियों के पैमाने पर निर्भर करती है।

अपनी कतारों में पूर्वाग्रहों, फूट तथा बाधाओं पर क़ाबू पाकर ही शान्ति के लिए संघर्ष की जनव्यापी धारा शक्ति प्राप्त करेगी और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर अधिकाधिक प्रभाव डलेगी।

४. प्रगति हेतु निरस्त्रीकरण

नवस्वाधीन देशों के कम विकसित होने में न केवल उनके औपनिवेशिक अतीत का, बल्कि नवउपनिवेशवादियों के वर्तमान कुकृत्यों का भी बड़ा हाथ है। नौवें दशक की अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति भी सभी देशों और ख़ासकर विकासमान राष्ट्रों के सामान्य सामाजिक-आर्थिक विकास और विश्व आर्थिक सम्बन्धों को स्वस्थ बनाने के लिए अनुकूल नहीं थी। इन वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय तनाव बहुत बढ़ गया, क्योंकि हथियारों, प्रथमत: नाभिकीय हथियारों की होड़ सतत बढ़ रही थी और साम्राज्यवादी हल्के, सर्वोपरि अमरीकी साम्राज्यवादी हल्के मुक़ाबलेबाज़ी की नीति पर चलते हुए सैनिक श्रेष्ठता पाने के लिए प्रयत्नशील रहे और बल-प्रयोग, भूमंडलवाद, दूसरे देशों के मामलों में हस्तक्षेप, उनकी राष्ट्रीय स्वाधीनता व संप्रभुता के उल्लंघन और नवस्वाधीन देशों के विरुद्ध प्रत्यक्ष सैनिक उकसावों से काम लेते रहे।

अग्रगामी शक्तियों का विश्वास है कि प्रगति तथा निरस्त्रीकरण के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध है, कि एकमात्र निरस्त्रीकरण ही आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विशाल मात्रा में आवश्यक साधन प्रदान कर सकता है। इसलिए उनकी मांग है कि निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में किये जानेवाले ठोस उपायों के साथ-साथ सैनिक व्यय भी घटाया जाये। इस प्रकार से प्राप्त भौतिक, वित्तीय, जन तथा वैज्ञानिक संसाधन सम्बद्ध देशों की आर्थिक-सामाजिक प्रगति को तीव्र बनाने और विभिन्न भूभागों के आर्थिक पिछड़ेपन का उन्मूलन करने हेतु इस्तेमाल किये जा सकते हैं। शस्त्रास्त्रों के परिसीमन और निरस्त्रीकरण, विशेष रूप से नाभिकीय हथियारों के उन्मूलन के पथ पर बढ़ाये गये हर क़दम से प्रगति हेतु अतिरिक्त साधन मिलेंगे।

इस सिलसिले में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्त्वावधान में अगस्त-सितम्बर १६८७ में न्यूयार्क में आयोजित प्रगति व निरस्त्रीकरण के सम्बन्ध विषयक अन्तर्राष्ट्रीय कांफ़्रेंस विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण थी। उसने साफ़-साफ़ दिखाया कि इस समस्या के बारे में नूतन और पुराने साम्राज्यिक राजनीतिक चिन्तन में कितना बड़ा अन्तर है।

सोवियत संघ ने इस बात के लिए अपनी सहमति को दोहराया कि हथियारों की होड़ को घटाने सम्बन्धी समन्वित पगों से मिले साधनों के एक

हिस्से को वह नवस्वाधीन देशों को देगा। उसकी राय है कि इस प्रकार मिले साधन विकासमान देशों को सौंपने का काम 'प्रगति हेतु निरस्त्रीकरण' नामक एक विशेष अन्तर्राष्ट्रीय कोष कर सकता है, जो सभी राज्यों के लिए खुला रहेगा। यह कोष संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्गत और ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के आधार पर बनाया जा सकता है, जो उसके कार्यों, साधन के निर्माण और वितरण को निर्दिष्ट करेगा। 'प्रगति हेतु निरस्त्रीकरण' सिद्धान्त की समाजवादी देश नये राजनीतिक चिन्तन के अनुरूप व्याख्या करते हैं, जिसमें सैन्यवाद को ठुकराकर विश्वव्यापी सहयोग और आपसी सहायता पर ज़ोर दिया गया है। ऐसा करते हुए वे अच्छी तरह समझते हैं कि विकास की स्थायी रफ़्तार के बिना आजकल सामाजिक-आर्थिक स्थिरता और सुदृढ़ शान्ति नहीं लायी जा सकती। आज प्रगति और अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्याएं एक हो गयी हैं।

खेद की बात है कि अमरीका ने उक्त कांफ़्रेंस में भाग लेने से इन्कार कर दिया, हालांकि इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य कोई १५० राज्य और संसार के २०० से अधिक ग़ैरसरकारी संगठन शिरकत कर रहे थे। अमरीका के इस इन्कार में उसके विदेश विभाग का एक ख़ास राजनीतिक रुख़ व्यक्त हुआ है और वह यह कि विकसित औद्योगिक राज्यों का निरस्त्रीकरण और प्रगति एक दूसरे से सम्बद्ध नहीं हैं। विकास जैसी विश्वव्यापी समस्या के समाधान की सामूहिक खोज की उपेक्षा पुराने पड़ गये अहंवादी चिन्तन का एक ज्वलंत उदाहरण है।

इस कांफ़्रेंस के प्रति संयुक्त राज्य अमरीका के रवैये को देखते हुए हम सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की २७वीं कांग्रेस में केन्द्रीय समिति की राजनीतिक रिपोर्ट के उस अंश की याद दिलाये बिना नहीं रह सकते जिसमें कहा गया है: "इन (विकासमान—**लेखक**) देशों के दस खरब डालर के कर्ज़ों और पिछले दस वर्षों में अमरीकी सैनिक व्ययों में दस खरब से ज़्यादा की वृद्धि के बीच अकाट्य कारणात्मक सम्बन्ध है। विकासमान देशों से प्रतिवर्ष खसोटी जा रही २० करोड़ डालर की धनराशि और हाल के वर्षों में लगभग ऐसा ही विशाल सैनिक बजट कोई संयोग मात्र नहीं हैं। इसी कारण सैनिकवाद की नव-उपनिवेशवादी अति शोषण को बरक़रार रखने में सीधी दिलचस्पी है।" इस बात को भी याद करें कि संसार में हर साल प्रति व्यक्ति १८० डालर सैनिक ख़र्चों पर व्यय होते हैं, जबकि विकासमान देशों में करोड़ों लोग अपने परिवार के जीवन-यापन पर साल में १५० डालर से कम ही ख़र्च कर पाते हैं। विकासमान देशों को सैनिक व्यय के बोझ से मुक्त करके भी काफ़ी अधिक

साधन प्राप्त किये जा सकते हैं। इसी कारण सोवियत संघ सामान्य हथियारों की खरीद और सप्लाई के परिसीमन सम्बन्धी प्रश्नों पर दोपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ताओं का समर्थन करता है। वह इस सम्बन्ध में की जानेवाली क्षेत्रीय पहलों में शामिल होने के लिए भी तैयार है, बशर्ते अमरीका बराबरी के आधार पर इनमें भाग ले और इनमें सम्बद्ध क्षेत्रों के सभी राज्यों के वैध हितों का खयाल रखा जाये।

हथियारों के आयात का तीन चौथाई अंश विकासमान देशों के हिस्से में आता है। जहां वे स्वास्थ्य-रक्षा पर अपनी समग्र घरेलू उपज का १ प्रतिशत और शिक्षा पर २.८ प्रतिशत खर्च करते हैं, वहां सैनिक ज़रूरतों पर उनका व्यय ६ प्रतिशत के बराबर है। नवस्वाधीन देशों के सैन्य व्ययों की कुल रक़म १९७० में २८ अरब डालर से बढ़कर १९८५ में १६५ अरब डालर तक पहुंच गयी है।

विकास की कौन सी सम्भावनाओं की चर्चा की जा सकती है, जब भूखों मर रहे अफ़्रीका ने १९८४ में अन्न की तुलना में हथियारों के आयात पर कहीं ज़्यादा खर्च किया था?

"प्रगति हेतु निरस्त्रीकरण" समस्या के प्रति अमरीकी प्रशासन का रुख इस तथ्य से भी स्पष्ट हो जाता है कि अमरीका के शस्त्रास्त्र-निर्यात का कम से कम २७ प्रतिशत भाग विकासमान देशों में पहुंचता है। इसके साथ ही अमरीका से शस्त्रास्त्रों के आयात और, उदाहरण के लिए, इन देशों की आबादी की मृत्यु-दर के बीच सीधा सम्बन्ध है। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों के एक ग्रुप ने हिसाब लगाया, ऐसे विकासमान देश में, जिसकी आबादी ८५ लाख और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद ३५० डालर हो, प्रति २० करोड़ डालरों के अमरीका से आयातित शस्त्रास्त्रों के पीछे प्रति १,००० नवजात शिशुओं में मृत्यु-दर में २० की वृद्धि होती है और औसत जीवन-अवधि ३-४ साल घटती है।

विकासमान देशों के बाहरी क़र्ज़ में गंभीर वृद्धि न केवल अन्यायपूर्ण उधार-प्रणाली और विश्व व्यापार में उनकी असमान स्थिति से, बल्कि हथियारों के उनके आयात में वृद्धि से भी जुड़ी हुई है। इस सिलसिले में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कार्रवाइयां भी उल्लेखनीय हैं, जो अमरीकी साम्राज्यवाद से घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है। "क़र्ज़ की बराबर अदायगी" के लिए वह देनदार देशों से सामाजिक आवश्यकताओं पर व्यय को घटाने, प्रथम आवश्यकता की चीज़ों की क़ीमतों में वृद्धि रोकने के लिए राज्य के अनुदानों को रद्द करने जैसी न जाने कितनी मांगें कर रहा है। परन्तु वह कभी भी यह मांग नहीं करता कि उसके देनदार अपने

सैन्य ख़र्चों में कमी करें, क्योंकि उनमें वह ठीक ही पैसा कमाने का एक अच्छा ज़रिया देखता है।

फिर भी नवस्वाधीन देशों के मेहनतकश जनसाधारण और उनके संगठनों में यह चेतना बढ़ती जा रही है कि विकास तथा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों का पुनर्गठन और शान्ति एवं निरस्त्रीकरण के प्रश्न आपस में गहनत: जुड़े हुए हैं।

प्रशान्त महासागर को नाभिकीय शस्त्रास्त्रों से रहित प्रदेश घोषित करने के बारे में इस क्षेत्र के १३ राज्यों द्वारा १९८६ में स्वीकृत निर्णय राष्ट्रीय मुक्ति क्षेत्र के जनगण में युद्धविरोधी, विशेष रूप से नाभिकीय शस्त्रास्त्र विरोधी भावनाओं की वृद्धि का प्रमाण है। लैटिन अमरीका तथा अफ़्रीका के देशों ने इससे भी पहले अपने महाद्वीपों में इसी तरह के प्रदेशों के निर्माण का निर्णय किया था। इससे केवल एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है: नवस्वतंत्र राज्यों की भारी बहुसंख्या साम्राज्यवाद की नाभिकीय योजनाओं के विरुद्ध है।

राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक ट्रेड यूनियन केन्द्र एशिया, अफ़्रीका और लैटिन अमरीका में युद्धविरोधी आन्दोलन के विकास में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। उनमें कुछ सबसे सक्रिय केन्द्र हैं ट्रेड यूनियन एकता की लैटिन अमरीकी स्थायी कांग्रेस, अफ़्रीकी ट्रेड यूनियन एकता संगठन तथा अरब ट्रेड यूनियनों का अन्तर्राष्ट्रीय महासंघ।

तनाव-शैथिल्य तथा शान्ति के लिए अफ़्रीकी ट्रेड यूनियन एकता संगठन की अपील में, जिसे लागोस में जनवरी १९८५ में संगठन की चौथी कांग्रेस में अनुमोदित किया गया था, यह लक्षित किया गया था कि यूरोप में मंझोली दूरी की मिसाइलों और पेर्शिंग-२ मिसाइलों के लगाये जाने से नाभिकीय युद्ध का ख़तरा विशेष रूप से बढ़ा है। एक भी देश, वह चाहे कहीं भी अवस्थित हो, नाभिकीय महानाश के भयंकर परिणामों से नहीं बच पायेगा।

फ़रवरी १९८५ में दिल्ली में प्रशान्त महासागरीय क्षेत्र की ट्रेड यूनियन कांफ़्रेंस ने शान्ति के लिए संघर्ष में ट्रेड यूनियनों के महत्व की विशेष रूप से चर्चा की: "साम्राज्यवादी सैनिक-औद्योगिक समुच्चयों द्वारा थोपी गयी हथियारों की होड़ दुनिया को नये विश्वयुद्ध के कगार की ओर धकेल रही है। अन्तरिक्ष के सैन्यीकरण के लिए अमरीका द्वारा घोषित योजना को देखते हुए हथियारों की होड़ के अन्तरिक्ष में फैलने का गंभीर ख़तरा है। पृथ्वी पर शान्ति की सक्रियतापूर्वक रक्षा करने के लिए संघर्ष आज जितना महत्वपूर्ण हो गया है, उतना पहले कभी नहीं था।

संसार भर में ट्रेड यूनियनें, जिनकी क़तारों में लाखों-लाख मेहनतकश ऐक्यबद्ध हैं, एक ऐसी वास्तविक शक्ति हैं, जो युद्धलिप्सुओं को लगाम लगाने के संघर्ष का नेतृत्व करने में सक्षम है।" इस घोषणापत्र की स्वीकृति और भी अधिक मूल्यवान है क्योंकि दिल्ली कांफ़्रेंस में भाग लेनेवाले ३५ ट्रेड यूनियन केन्द्रों में से १० विश्व ट्रेड यूनियन संघ, ५ अन्तर्राष्ट्रीय फ़्री ट्रेड यूनियन महासंघ और २ विश्व श्रम महासंघ के सदस्य थे तथा १८ इन अन्तर्राष्ट्रीय असोसियेशनों में शामिल नहीं थे। यह चीज़ एक बार फिर शान्ति तथा निरस्त्रीकरण के लिए संघर्ष में भिन्न-भिन्न धाराओंवाली ट्रेड यूनियनों की संयुक्त कार्रवाइयों की आवश्यकता और सम्भावना दर्शाती है।

निस्सन्देह, नवस्वाधीन देशों में युद्धविरोधी, साम्राज्यवाद विरोधी एकजुटता के विकास में निश्चित बाधाएं मौजूद हैं और ये बाधाएं इन देशों के पिछड़ेपन, अधिकांश आबादी के निम्न शिक्षा स्तर, बाहरी राजनीति की अपर्याप्त जानकारी तथा उन भ्रमों से सम्बद्ध हैं, जो नाभिकीय मुक़ाबलेबाज़ी के केन्द्रों से अधिकांश विकासमान देशों के बहुत दूर अवस्थित होने के फलस्वरूप उनमें अपनी सुरक्षा के बारे में प्रचलित हैं। कम्युनिस्टों, अन्य प्रगतिशील शक्तियों और ट्रेड यूनियनों के आन्दोलन द्वारा किये जानेवाले सुसंगत प्रयत्नों की बदौलत ये बाधाएं अब धीरे-धीरे दूर हो रही हैं। जनसामान्य में यह समझ बढ़ती जा रही है कि राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन में हस्तक्षेप की साम्राज्यवाद की क्षमता को सीमित करने और युद्धों को रोकने के लिए विश्व के जनगण के एकजुटता आन्दोलन का बहुत बड़ा महत्त्व है।

पूर्ण मुक्ति की मुख्य शर्त की पूर्ति—शान्ति तथा निरस्त्रीकरण की उपलब्धि—के लिए राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन में समस्त प्रगतिशील शक्तियों की और अधिक ऐक्यबद्धता बढ़ती जाती है। विकासमान देशों में युद्धविरोधी आन्दोलन का गहनीकरण तथा मई दिवस प्रदर्शनों का विस्तार भी इस बात के प्रमाण हैं। ये प्रदर्शन प्राय: "प्रगति के लिए निरस्त्रीकरण" नारे तले हो रहे हैं।

उत्सव, जो एकता का आह्वान करता है

अमरीका में उन घटनाओं के बाद १०० से भी अधिक वर्ष बीत चुके हैं, जिन्होंने मई दिवस को जन्म दिया था। संसार के मेहनतकशों ने अत्यन्त कठोर, विषम संघर्ष में सच्चे अर्थों में महान, विश्वव्यापी प्रदर्शन का अधिकार प्राप्त किया। १९वीं शताब्दी बहुत पहले गुज़र चुकी है और २०वीं शताब्दी भी समाप्त होने जा रही है, परन्तु वर्ग-संघर्ष की आग संसार में अभी धधक रही है। मई दिवस प्रदर्शनों के बारे में समाचार हमें हर वर्ष पूंजी के साथ सर्वहारा वर्ग की पहली टक्करों की याद दिलाते हैं। कभी-कभी ये समाचार दुखद होते हैं।

१९८६ में पृथग्वासन का अन्त करने के लिए कृत संकल्प दक्षिण अफ़्रीकी मेहनतकशों के प्रदर्शनों में लाखों लोगों ने मई दिवस मनाने के लिए भाग लिया। न्यूज़ एजेंसियों की ख़बरों के अनुसार, नियोजित प्रदर्शनों तथा सभाओं में भाग लेने की ट्रेड यूनियनों की अपील पर जितने अफ़्रीकी मज़दूर उस दिन काम पर नहीं गये, उनकी संख्या ४० लाख से कम नहीं थी। ये सभाएं तथा प्रदर्शन जोहांसबर्ग, केपटाउन, डरबिन, पोर्ट एलिज़ाबेथ तथा देश के अन्य औद्योगिक केन्द्रों में हुए। परन्तु पुलिस प्रदर्शनकारियों पर क्रूरतापूर्वक टूट पड़ी—आठ व्यक्ति मारे गये तथा दर्जनों गिरफ़्तार किये गये।

उसी दिन चिली में सेना तथा पुलिस ने राजधानी पर व्यवहारत: क़ब्ज़ा कर लिया था। इन असाधारण पगों के बावजूद बहुत बड़ी संख्या में लोग पुलिस के घेरे के अन्दर घुस गये और उन्होंने सभा में भाग लिया। उनके नारे थे: "पिनोचेट मुर्दाबाद!", "चिली के लिए जनवाद!" पिनोचेट ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए ताज़ीरी पुलिस भेजी। दर्जनों लोग घायल हो गये और ५०० से अधिक लोगों को पकड़ कर जेलों में बन्द कर दिया गया।

निस्सन्देह, वह ज़माना, जब मई दिवस ग़ैरक़ानूनी हुआ करता था, बहुत पहले लद चुका है और कभी वापस नहीं लौटेगा। परन्तु दक्षिण अफ़्रीका, चिली और अन्य देशों में, जहां घोर दक्षिणपंथी हुकूमतें राज करती हैं, मई दिवस प्रदर्शनों में भाग लेनेवाले इस पर यक़ीन नहीं कर सकते कि वे प्रदर्शनों के बाद सुरक्षित अपने घरों को लौट पायेंगे। इन

देशों में दमनकारी निकाय पहले से ही अपना "असला" दुरुस्त कर लेते हैं। उनके इस असले में ये शामिल हैं—वाटरगन, पुलिस के डंडे, बंदूकें, हथकड़ियां और साथ ही जेलें तथा पुलिस के अहाते, जो मई दिवस समारोहों में गिरफ़्तार लोगों की भीड़ के कारण ठसाठस भरे रहते हैं।

पहले की तरह बहुत से देशों ने नये जनवाद विरोधी क़ानून अनुमोदित किये हैं, उनमें से कई तो खास तौर पर मई दिवस प्रदर्शनों में भाग लेनेवालों पर दमन को क़ानूनियत का रूप देने के लिए बनाये गये हैं। इस तरह १ मई, १९७९ को चिली के फ़ासिस्ट शासक गुट ने "आतंकवाद" के विरुद्ध संघर्ष के लिए एक "क़ानून" जारी किया, जिसे हुकूमत द्वारा किसी भी तरह के, मामूली से मामूली क़िस्म के प्रतिरोध पर लागू किया जाता है। परन्तु ऐसे पग भी सहायक नहीं होते। यद्यपि मई दिवस के अवसर पर गिरफ़्तार होनेवालों की संख्या वर्ष-प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है, मई दिवस प्रदर्शनों के जनव्यापी स्वरूप में ज़रा भी कमी नहीं आयी है।

जो लोग मई दिवस प्रदर्शनों को कुचलने के लिए कीर्ति अर्जित करना चाहते हैं, उन्हें शिकागो में दो स्मारकों के इतिहास से सबक़ सीखना चाहिए।

हेमार्केट चौक के छोर पर, केन्नेडी राजपथ की तरफ़ निर्गम-स्थली के पास, भूरे पत्थर का, चौकोर, कटा हुआ, पिरामिड खड़ा है। उसपर समय के थपेड़ों के कारण घिसे ये शब्द अंकित हैं: "शिकागो नगर द्वारा अपने उन रक्षकों की स्मृति में स्थापित स्मारक, जिन्होंने ४ मई, १८८६ को उपद्रवियों का डटकर मुक़ाबला किया।" स्मारक को देखकर राहगीरों के मन में विरोधी प्रतिक्रियाएं होती हैं। कुछ उदासीन भाव से आगे बढ़ जाते हैं, कुछ व्यंग्यपूर्वक मुस्कराते हैं—उन्हें याद है कि यहां कभी एक पुलिसमैन का स्मारक खड़ा था, जिसने प्रदर्शन में भाग लेनेवाले निहत्थे लोगों पर रक्तपातपूर्ण दमन में भाग लिया था।

शिकागो के थैलीशाहों ने यह स्मारक अपने अधिकारों के लिए लड़नेवाले सर्वहारा को चेतावनी के रूप में स्थापित किया था। यहां १८८९ में हाथ उठाये हुए एक पुलिसमैन की मूर्ति खड़ी की गयी थी। शिकागो के तत्कालीन मेयर ने "स्मारक" के अनावरण के अवसर पर कहा था कि यह हेमार्केट चौक में "स्वतंत्रता तथा क़ानून" के प्रतीक के रूप में सदा खड़ा रहेगा।

परन्तु मज़दूरों की इस बारे में अलग ही राय थी। कांसे की मूर्ति

को उसके आधारस्तम्भ से "अज्ञात व्यक्ति" बार-बार फेंक देते। और कभी-कभी तो मूर्ति टूटी हुई हालत में मिलती। उसके अंश जमा किये जाते और जोड़ दिये जाते। इस शताब्दी के तीसरे दशक में एक ट्राम ड्राइवर ने बहुत तेज़ रफ़्तार से ट्राम चलाकर मूर्ति को तोड़ दिया।

छठे दशक में, जब दक्षिण पूर्वी एशिया में अमरीकी आक्रमण विरोधी प्रदर्शनों ने देश को हिला दिया था, कांसे के पुलिसमैन के लिए हालात मुश्किल हो गये। मेयर डेली ने तो यहां तक सलाह दी कि इसे एक पारदर्शी टोप से ढक दिया जाये। अन्तत: यह निर्णय किया गया कि दिन-रात चौकसी की जाये। इस काम पर म्युनिसपल बजट की बहुत बड़ी राशि ख़र्च की जाने लगी। फिर भी १९७२ में अधिकारी इस मूर्ति को चौक से हटाने और मज़दूरों पर दमन के इस प्रतीक को उस सुरक्षित स्थान में स्थानान्तरित करने के लिए बाध्य हुए, जो पहले से ही उसका था। यह स्थान था पुलिस विभाग का आंगन। आगे चलकर बार-बार मरम्मत से गुज़रनेवाला यह "स्मारक" पुलिस अकादमी के अन्दरूनी अहाते में पहुंचा दिया गया।

अब उस मूर्ति के वीरान आधारस्तम्भ पर अक्सर इस तरह के नारे लिख दिये जाते हैं: "निकारागुआ से दूर हटो!", "अमरीकी साम्राज्यवादी युद्ध बन्द करो!"

शिकागो की प्रतिक्रियावादी शक्तियां इस बात के लिए पूरी-पूरी कोशिश करती हैं कि अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर एकजुटता के उत्सव का इतिहास भूल जाये। वे गत शताब्दी के नौवें दशक में शिकागो की घटनाओं से जुड़ी हर चीज़ को सहर्ष मिटा देतीं। आज हेमार्केट चौक को ढूंढ पाना आसान नहीं है। नगर के गाइड इसकी चर्चा नहीं करते, उसे पर्यटन-मानचित्रों में भी स्थान नहीं दिया गया है। नगर के पुनर्नियोजन के दौरान चौक का नाम ही ग़ायब हो गया। चौक के सामने खड़ी एक इमारत में कीलों के निशान हैं। यहां मज़दूर आन्दोलन के इतिहास की स्थानीय सोसायटी की पहल पर ३ मई, १९७० को एक विशाल सभा में 'मार्सेल्येज़' गीत की धुन के बीच एक स्मारक-पट स्थापित किया गया था। ६ माह बाद वह स्मारक-पट तोड़ दिया गया।

इस समय नगर के अधिकारी हेमार्केट क्षेत्र में डिस्नीलैंड क़िस्म के एक मनोरंजन पार्क का निर्माण करने की योजना बना रहे हैं। परन्तु ट्रेड यूनियनों के समर्थन से मज़दूर चौक पर एक छोटा स्मारक पार्क बनाने और अपने अधिकारों के लिए मज़दूर वर्ग के संघर्ष के प्रतीकस्वरूप एक स्मारक खड़ा करने की मुहिम चला रहे हैं।

और इस बीच दक्षिणपंथी शक्तियां पार्सन्स, श्पीस, एंगेल, फ़िशर और लाइंग की समाधियों पर स्मारक को देखकर चैन की नींद नहीं ले सकतीं। धुंधली आकृतियों के इस स्मारक में एक शोकमग्न नारी सफ़ेद संगमरमर की पृष्ठभूमि में रखे एक निर्जीव पुरुष के शरीर के ऊपर कांटों का ताज लिये हुए खड़ी है। हेमार्केट के शहीदों की समाधि-स्थली अमरीका के मेहनतकशों के लिए उतनी ही पवित्र है, जितनी पवित्र फ़्रांसीसी मज़दूरों के लिए पेरिस में कम्युनार्डों की स्मारक भित्ति है। यह समाधि-स्मारक शिकागो के फ़ारेस्ट होम कब्रिस्तान की केन्द्रीय वीथिका में स्थित है और उसके चारों ओर मज़दूर वर्ग के अन्य प्रमुख नेताओं — विलियम फ़ोस्टर, यूजीन डेनिस, एलिज़ाबेथ गेर्ले फ़्लीन, फ़्रैंक पेलेग्रिनो, आदि — की समाधियां हैं। अमरीकी तथा अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर आन्दोलन की दो अन्य विभूतियों के नाम भी यहां विद्यमान हैं। जो हिल की, जो मज़दूरों के प्रवक्ता तथा गायक थे और जिन्हें १९१८ में यूटा राज्य में झूठे आरोप में गोली से उड़ा दिया गया था, वसीयत के अनुसार, उनके देह की भस्म हेमार्केट के शहीदों के स्मारक पर बिखेर दी गयी थी। विलियम हेवुड ने भी, जो अमरीकी मज़दूर आन्दोलन के नेता थे और जिनका देहावसान १९२८ में मास्को में हुआ था, इसी तरह की वसीयत की थी। उनके देह की भस्म का एक अंश मास्को के लाल मैदान में और दूसरा हेवर्ड में पहली मई के वीरों की समाधि की बग़ल में दफ़न कर दिया गया था।

१९८२ के मई दिवस से दो दिन पूर्व पार्सन्स तथा उनके साथियों की क़ब्र पर गुंडागर्दी का शर्मनाक कुकृत्य किया गया। स्मारक के चमकदार संगमरमर पर दाहक रंग चढ़ा दिया गया।

जिन लोगों को आशा थी कि वे स्मारक को हटाने का बहाना ढूंढ लेंगे, उन्होंने ग़लत अनुमान लगाया था। इलिनोइस राज्य के मज़दूर आन्दोलन के इतिहास समाज तथा ट्रेड यूनियन संगठनों की अपील पर स्मारक को बहाल करने के लिए तुरन्त धन जमा हो गया था। १ मई, १९८२ तक उसे बहाल कर दिया गया था और उस दिन उसके दूसरे अनावरण के उपलक्ष्य में एक सभा हुई। समारोह के उपरान्त अभूतपूर्व रूप से बड़ा प्रदर्शन हुआ। अगस्त श्पीस के वे शब्द अनायास स्मरण हो आते हैं, जिन्हें उन्होंने अपने जल्लादों के चेहरे पर उछाला था। ये शब्द थे: "एक वक़्त आयेगा, जब हमारी ख़ामोशी उन आवाज़ों से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होगी, जिन्हें तुम आज दबा रहे हो।"

बहुत से विकसित पूंजीवादी देशों में शासक क्षेत्र मई दिवस प्रदर्शनों

को कुचलने का खुलेआम साहस नहीं कर सकते। परन्तु वे पहले की भांति तरह-तरह के और कभी-कभी तो उपहासास्पद बहानों की आड़ लेकर उन्हें ग़ैरक़ानूनी करार देने के लिए तिकड़मबाज़ी से काम लेते हैं। उदाहरण के लिए, १९८० में लास-एंजेल्स के अधिकारियों ने मई दिवस प्रदर्शन पर इस आधार पर पाबन्दी लगा दी कि उससे ट्रैफ़िक जाम हो जायेगा और शहर का जीवन कई घंटों के लिए ठप्प हो जायेगा।

दमन तथा प्रशासनिक पाबन्दियों का परित्याग करना तो रहा दूर, बहुत से पूंजीवादी देशों के शासक क्षेत्र अपनी मई दिवस विरोधी नीतियों में इस उत्सव के अर्थ तथा सार को विकृत करने का प्रयत्न करते हैं और बहुधा पहली मई को कुछ इस तरह का उत्सव घोषित करते हैं, जिसका मेहनतकशों की अन्तर्राष्ट्रीय एकजुटता के साथ कुछ भी मेल नहीं होता। यदि पिनोचेट मई दिवस को श्रम, पूंजी तथा अपने बीच एकजुटता के दिवस में परिणत करने का प्रयत्न कर रहा है, तो यह बात कदापि नहीं भुलायी जानी चाहिए कि वह हिटलर और उसकी कठपुतलियों की ही राह पर चल रहा है।

१९५५ में रोमन कैथोलिक चर्च के प्रधान तथा अपने प्रतिक्रियावादी, कम्युनिस्ट विरोधी विचारों के लिए मशहूर पोप पायस बारहवें ने एक नया धार्मिक उत्सव आरम्भ किया। यह था "बढ़ई सेंट जोसेफ़" दिवस, जिसे मनाने के लिए पहली मई का दिन निश्चित किया गया था। किसी तरह की ग़लतफ़हमी न होने देने के लिए पोप ने नये उत्सव का सार इस प्रकार निर्दिष्ट किया: चर्च द्वारा पवित्रीकृत मई दिवस को वर्ग-संघर्ष के बजाय वर्ग-शान्ति पर ज़ोर देना चाहिए। इस तरह चर्च ने मेहनतकशों की अन्तर्राष्ट्रीय एकजुटता के उत्सव के स्थान पर नये उत्सव के समारम्भ का प्रयत्न किया। इस उत्सव का नारा वर्ग-संघर्ष के स्थान पर सामाजिक शान्ति का आह्वान करता है, जो मानो चर्च के तत्वावधान में उपलब्ध की जा सकती है।

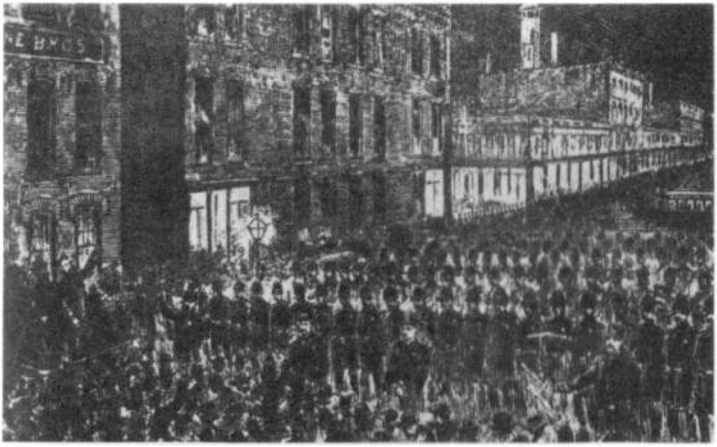
९ अप्रैल, १९८४ को अमरीकी राष्ट्रपति भवन के रोज़ गार्डन में एक समारोह हुआ। चारों ओर आंखों को चकाचौंध करनेवाली रोशनी में तथा टीवी कैमरों के सामने राष्ट्रपति रीगन ने एक आज्ञप्ति पर हस्ताक्षर किये, जिसमें १ मई को 'क़ानून दिवस' घोषित किया गया। उन्होंने पत्रकारों के सामने ऐलान किया कि मेहनतकशों का परम्परागत उत्सव उन्हें विषादपूर्ण और कृत्रिम लगता है, कि क़ानून तथा स्वतंत्रता के बीच साझीदारी क़ायम रहनी चाहिए, क्योंकि क़ानून के बिना स्वतंत्रता अकल्पनीय है, उसके स्थान पर अराजकता और अव्यवस्था का

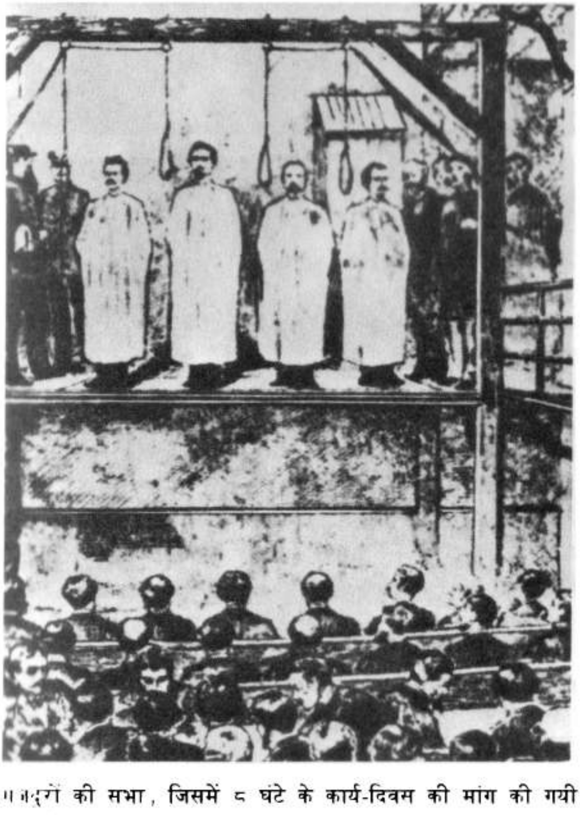
राज क़ायम होगा। 'क़ानून दिवस' के लिए तिथि संयोगवश नहीं चुनी गयी थी। इसका प्रयोजन यह जताना था कि सर्वहारा एकजुटता के उत्सव को जन्म देनेवाली घटनाएं अराजकतापूर्ण तथा अव्यवस्थापूर्ण थीं और "स्वतंत्रता" तथा "क़ानून" के विरुद्ध थीं।

"स्वतंत्रता" को वाशिंगटन किस तरह समझता है, यह अमरीकी विदेश विभाग की कार्रवाई से स्पष्ट हो जाता है, जिसने शिकागो में मई दिवस की सौवीं जयन्ती को अर्पित समारोहों में भाग लेने का इरादा रखनेवाले सोवियत मोटर-कार कारख़ाने के मज़दूरों के प्रतिनिधियों को वीज़ा देने से इन्कार कर दिया था। वे लोग, जो "लोगों तथा विचारों के स्वतंत्र विनिमय" की दिन-रात रट लगाते रहते हैं, अपने देश के फाटक तुरन्त बन्द कर लेते हैं, ताकि इस "विनिमय" से कामगारों के बीच सम्बन्ध सुदृढ़ न हों।

परन्तु मई दिवस की प्राणवान परम्पराओं को मिटाना उनके बूते से बाहर है। इसका सर्वोत्तम प्रमाण है हेमार्केट की घटनाओं, १८८६ में अमरीकी मेहनतकशों की आम हड़ताल की १००वीं जयन्ती से कुछ ही समय पूर्व शिकागो म्युनिसपलिटी द्वारा नगर को नाभिकीय शस्त्रास्त्रों से रहित घोषित करने के लिए अनुमोदित निर्णय। जिस नगर में सौ वर्ष पूर्व मई दिवस का जन्म हुआ था, वह वाशिंगटन की दुस्साहसिक नीतियों का समर्थन करने से इन्कार करता है तथा युद्ध और नाभिकीय हथियारों को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार करता है।

१८९६ के मई दिवस पर जर्मन मज़दूरों के एक अख़बार की भविष्यवाणी सचमुच सच निकली, जिसने कहा था कि मई दिवस "बुर्जुआ समाज के समस्त उत्सवों की आयु ख़त्म होने के बाद भी जीवित रहेगा और... पूरी मुक्त मानवजाति के लिए वसंत तथा शान्ति का उत्सव बन जायेगा।" मई दिवस भविष्य की दिशा में लक्षित उत्सव है, क्योंकि मानवजाति को सामाजिक प्रगति के अनन्त पथ पर आगे बढ़ते रहने के लिए अपने प्रयास एकजुट करने की सदैव आवश्यकता होगी।

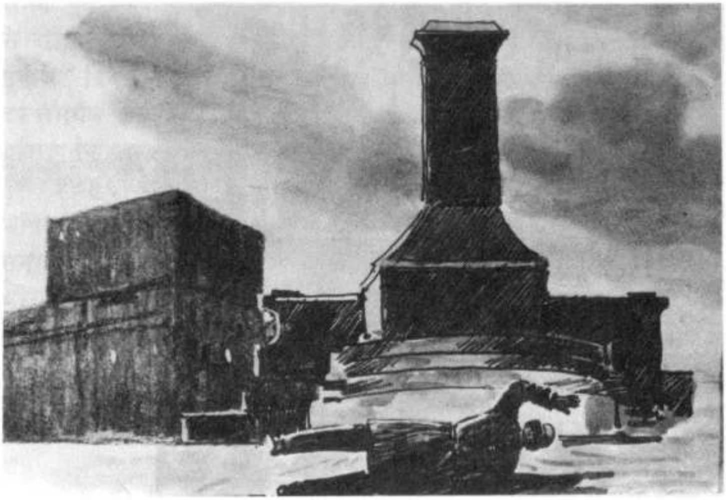




मजदूरों की सभा, जिसमें ८ घंटे के कार्य-दिवस की मांग की गयी। शिकागो, मई १८८६।

अदालती स्वेच्छारिता के शिकार। हेमार्केट के शहीदों को फांसी। शिकागो, नवम्बर १८८७।





शिकागो के मजदूरों द्वारा तोड़ा गया पुलिसमैन का स्मारक, जिसे निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर रक्तपातपूर्ण दमन की "प्रशस्ति" के लिए स्थापित किया गया था। रेखाचित्र इ० प्चेल्को।

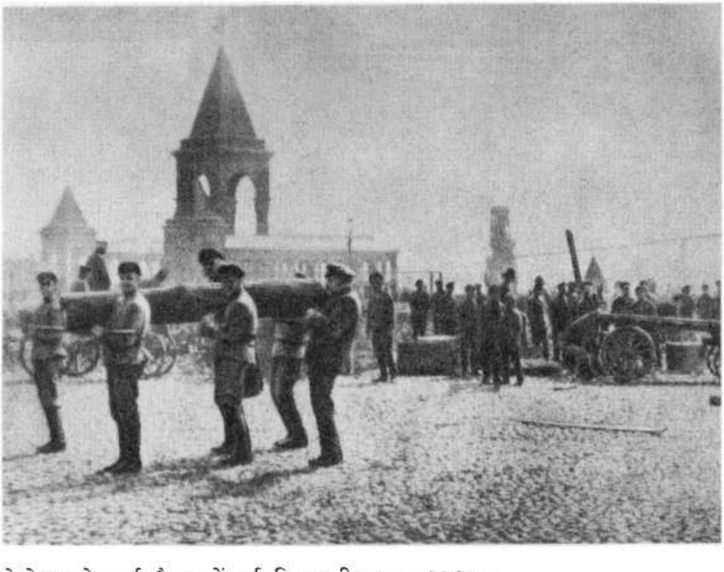
लन्दन के हाइड पार्क में मई दिवस। १८६२ (बायीं ओर से तीसरे फ़े० एंगेल्स। सामने एलेनोर मार्क्स-एवलिंग)।

मई दिवस का पोस्टर। इटली, १६०६।


14


SVEZIA
GERMANIA
RUSSIA
FRANCIA
AUSTRIA
ITALIA





पेत्रोग्राद के मार्स मैदान में मई दिवस की सभा। १९१७।

मास्को में १ मई, १९२० को अखिल रूसी सुब्बोत्निक में व्ला० इ० लेनिन।

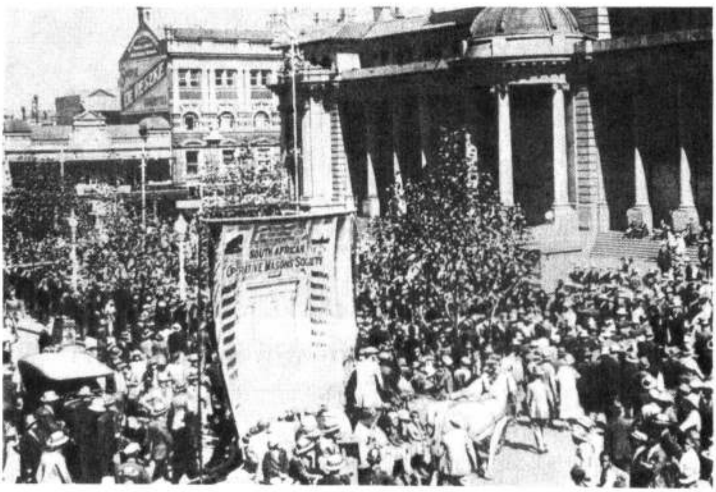




मोंटेविडियो (उरुग्वे) में जन-एकता मोर्चे द्वारा मई दिवस प्रदर्शन। १९२५।

१ मई, १९२६ को आम हड़ताल के पहले दिन का प्रदर्शन। लन्दन।

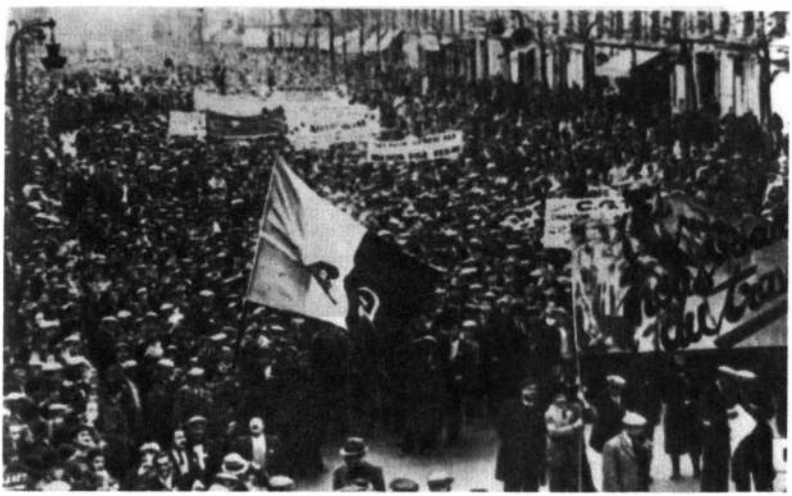




आस्ट्रेलियाई मज़दूरों का १ मई का पोस्टर। १९२७।

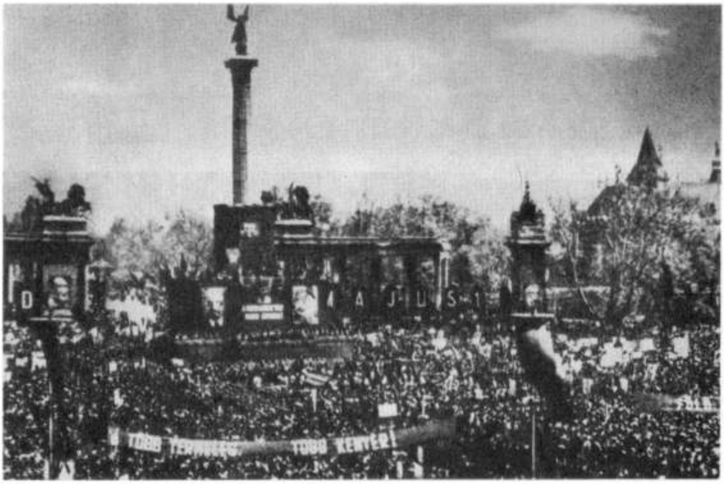
जोहान्सबर्ग नगर में मई दिवस प्रदर्शन। १९२८।



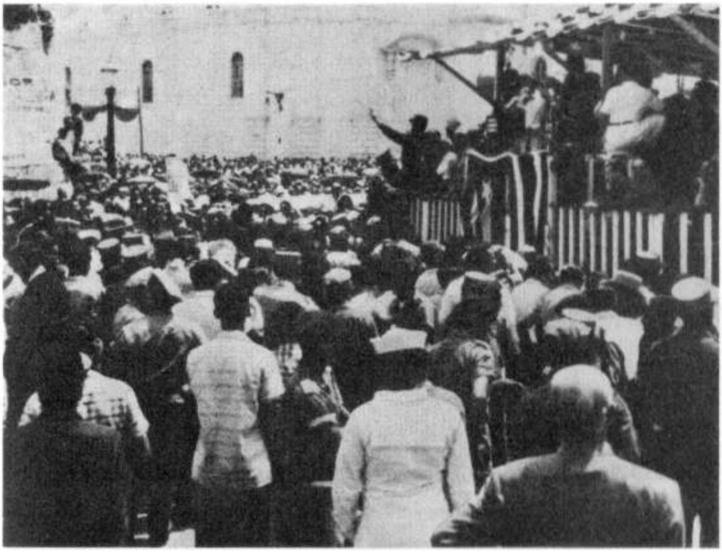


टोकियो में मई दिवस प्रदर्शन। १९३५।
पेरिस में मई दिवस प्रदर्शन। १९३७।





लन्दन में मई दिवस प्रदर्शन, जिसका नारा था : "फ़ासिज़्म का अर्थ है युद्ध"। १९३४।
मुक्त हुए बुडापेस्ट में मई दिवस। १९४५।





बाटिस्टा की तानाशाही का तख़्ता उलट दिये जाने के उपरान्त फ़िडेल कास्ट्रो हवाना में पहले मई दिवस के अवसर पर क्यूबाई मेहनतकशों की सभा में भाषण करते हुए। १९५९।

न्यूयार्क के यूनियन चौक में १ मई, १९६२ को सभा।





हनोई की जनता अमरीकी साम्राज्यवादियों तथा सैगोन में उनकी कठपुतलियों पर वियतनामी जनता की विजय मनाते हुए। १ मई, १९७५।

जर्मन जनवादी जनतंत्र। बर्लिन के मेहनतकशों का मई दिवस प्रदर्शन। १९८५।





प्राग में मई दिवस का समारोही प्रदर्शन। १९८५।

मास्को। लाल मैदान में मई दिवस। १९८५।





१ मई, १९८३, पश्चिम बर्लिन। प्रदर्शन में भाग लेनेवाले झंडा ले जाते हुए, जिसपर यह नारा अंकित है: "नाभिकीय मिसाइल लगाने का नाटो का निर्णय मुर्दाबाद!"

भारत। मद्रास में शान्ति-मार्च। १९८५।





इंग्लैंड। ग्रीनहाम-कामन में सैनिक अड्डे के बाहर युद्धविरोधी प्रदर्शन में भाग लेनेवाले।

कोपेनहागेन के निवासी नगर के केन्द्र में युद्धविरोधी प्रदर्शन में भाग लेते हुए। १९८३।



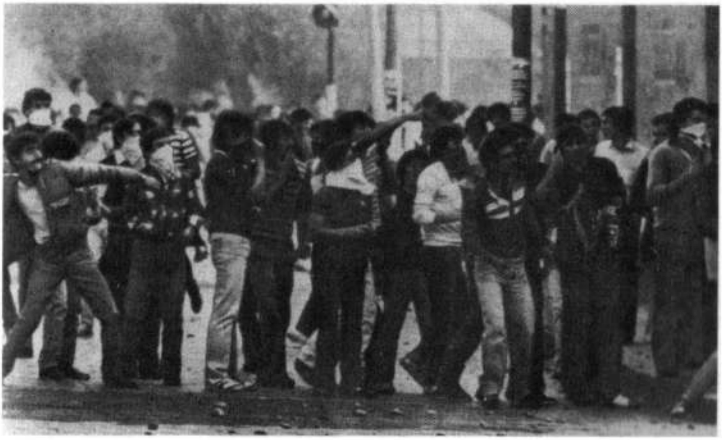


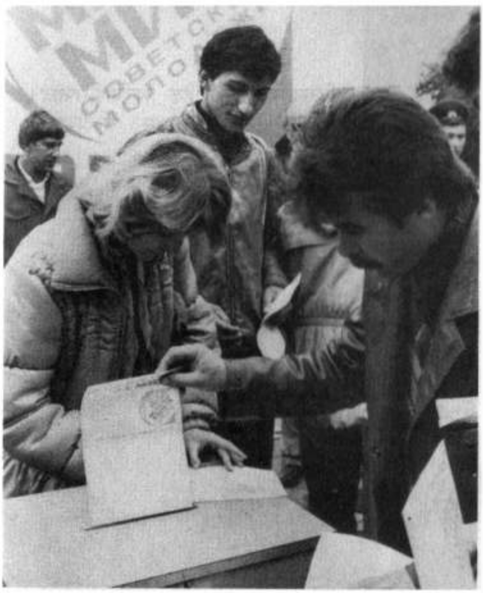
जर्मन जनवादी जनतंत्र। रोस्टोक अध्यापक प्रशिक्षण कालेज के छात्र निकारागुआ के साथ एकजुटता व्यक्त करनेवाली सभा में। १९८४।

जापान। छात्र मध्य अमरीका में अमरीकी प्रशासन की नीति के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए। १९८४।

चिली। प्रदर्शनकारियों तथा पुलिस की टक्कर के समय। २ मई, १९८४।

सोवियत नौजवान शान्ति के पक्ष में मत देते हुए।







न्यूयार्क में युद्धविरोधी प्रदर्शन।
१६८३।

निरस्त्रीकरण के हेतु कार्रवाई-सप्ताह।
वितेब्स्क नगर (बेलोरूस) में प्रदर्शन।



पाठकों से

प्रगति प्रकाशन इस पुस्तक की विषय-वस्तु, उसके अनुवाद और डिज़ाइन के बारे में आपके विचार जानकर अनुगृहीत होगा। आपके अन्य सुझाव प्राप्त करके भी हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। कृपया हमें इस पते पर लिखिये :

प्रगति प्रकाशन,
१७, ज़ुबोव्स्की बुलवार,
मास्को-११६०२१, सोवियत संघ।

प्रगति प्रकाशन · मास्को

प्रस्तुत पुस्तक मई दिवस के, जो मेहनतकशों की अन्तर्राष्ट्रीय एकजुटता का उत्सव है, उद्भव तथा विकास के बारे में है। उसमें इस ओर विशेष ध्यान दिया गया है कि विभिन्न देशों में इस उत्सव को किस तरह मनाया जाता है। पाठक पहली मई की परम्पराओं से अवगत हो जायेगा और वह इस तरह से यह देख लेगा कि समकालीन विशाल साम्राज्यवाद विरोधी, सैन्यवाद विरोधी आन्दोलन में ये परम्पराएं किस तरह व्याप्त हैं, क्योंकि इस आन्दोलन का लक्ष्य एकजुटता के उत्सव की ही भांति शान्ति तथा जनगण का अन्तर्राष्ट्रीय भ्रातृत्व है।

ISBN 5-01-001496-3

